चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

28 अक्टूबर–03 नवंबर 2013

आम आदमी पार्टी को अन्ना का समर्थन नहीं है

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जीने-मरने का सवाल है. इसलिए यह पार्टी साम, दाम, दंड, भेद- इन चारों हथियारों का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल कर रही है. कहने को तो इस पार्टी के नेता पारदर्शिता के पक्षधर हैं, लेकिन उनके बयान वैचारिक रूप से अशुद्ध व भ्रामक प्रतीत होते हैं. दिल्ली चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन का क्या मतलब है? दिल्ली सरकार देश की अकेली राज्य सरकार है जिसके पास न तो पुलिस है, न ही जनता की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी. यह ऐसी दंतहीन-विषहीन सरकार है जो दिल्ली में मौजूद उच्च अधिकारियों का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती. जब अधिकार ही नहीं है, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा. आम आदमी पार्टी जिन वादों पर चुनाव जीतना चाहती है वह तर्कसंगत नहीं हैं. इन वादों को लागू करना बड़े-बड़े राज्यों के भी बस में नहीं है क्योंकि भारत का संघीय ढांचा इसकी इजाज़त नहीं देता. देश में कोई भी मौलिक राजनीतिक परिवर्तन लोकसभा के जरिए ही संभव है. दिल्ली चुनाव के जरिए व्यवस्था परिवर्तन की डींगें हांककर आम आदमी पार्टी दिल्ली के वोटरों को मूर्ख बना रही है. साथ ही अन्ना हजारे को न केवल धोखा दे रही है, बल्कि उनके उद्देश्यों को पलीता लगा रही है, क्योंकि अन्ना हजारे देश में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत का बिंदु लोकसभा को मानते हैं. अरविंद केजरीवाल विधानसभा का चुनाव लड़ अन्ना हजारे के सपने को ध्वस्त करना चाह रहे हैं और यही वह काम है जिसे भाजपा और कांग्रेस भी करना चाह रही है.

मनीष कुमार

दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी अन्ना हजारे बने हुए हैं. यह पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से अलग होकर बनी है. इस पार्टी का आधार अन्ना हजारे की विश्वसनीयता, नैतिकता, लोकप्रियता, त्याग व सर्वमान्यता है. लेकिन अन्ना हजारे का साफ़-साफ़ आदेश यह है कि आम आदमी पार्टी उनके नाम, उनकी फोटो, उनकी टोपी व उनके किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती है. अन्ना के बिना पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और अन्ना का नाम लेने से अन्ना नाराज़ हो जाते हैं. लेकिन हक़ीक़त यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अन्ना का नाम धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. आज भी सोशल मीडिया के कई ऐसे एकाउंट हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को अन्ना की पार्टी बताया जाता है. दिल्ली में कई जगहों पर ऐसे पर्चे बांटे जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अन्ना जी की पार्टी है. वैसे इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता साफ़-साफ़ जवाब भी नहीं देते. अन्ना क्यों अलग हुए या आम आदमी पार्टी के साथ अन्ना क्यों नहीं हैं, ऐसे सवालों के जवाब में अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि अन्ना और आम आदमी पार्टी का मक़सद एक है, लेकिन रास्ते अलग हैं. यह बयान ग़लत क्यों है यह आगे बताएंगे, लेकिन अन्ना हजारे को अपने साथ बताने पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जता दी, साथ ही एक नोटिस भेज कर आयोग ने आम आदमी पार्टी से इसका सबूत मांगा कि अन्ना हजारे उनके साथ हैं. आयोग का कहना यह है कि यह साबित करने के लिए पार्टी को अन्ना हजारे का मंज़ूरी पत्र जमा करना होगा. इस मुद्दे को लेकर प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से मुलाक़ात भी की, लेकिन अन्ना का मंज़ूरी पत्र नहीं दे सके.

दरअसल, आम आदमी पार्टी प्रचार के दौरान एक लघु फ़िल्म दिखा रही है. इसमें जन लोकपाल को लेकर हुए आंदोलन की तस्वीरें भी शामिल हैं. इसमें अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के साथ नज़र आ रहे हैं. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टी को फ़िल्म दिखाने के लिए चुनाव आयोग की मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से मंज़ूरी लेनी होती है. इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी फ़िल्म की मंज़ूरी के लिए ज़िला चुनाव कार्यालय में आवेदन किया था. जब चुनाव आयोग की कमेटी ने इस लघु फ़िल्म को देखा तो उसका माथा ठनका. जब अन्ना साथ नहीं है तो इस फ़िल्म में अन्ना की तस्वीर क्यों हैं? ख़र्च निगरानी कमेटी के अंकुर गर्ग के मुताबिक, उन्हें किसी का नाम इस्तेमाल करने पर आपत्ति नहीं है. मगर उसके बारे में ग़लत या भ्रामक सूचना देने पर आपत्ति है. चुनाव अधिकारियों ने फ़ौरन आम आदमी पार्टी को तलब किया और इस बिंदु पर आपत्ति जताते हुए जवाब मांगा. आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, नोटिस चुनाव आयोग के निर्देश के तहत मांगा गया था. जवाब देने के बाद अगर वह उचित पाया जाता है तो फ़िल्म दिखाने की मंज़ूरी मिल जाएगी. आम आदमी पार्टी के लिए अब समस्या यह है कि अन्ना का मंज़ूरी पत्र कहां से लाया जाए. वो तो साथ हैं नहीं.

इसका जबाव देने आम आदमी पार्टी के नेता व देश के प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव अधिकारियों से मुलाक़ात की. अन्ना का मंज़ूरी पत्र न दे पाने की हालत में उन्होंने चुनाव आयोग के इस फ़ैसले पर ही हमला कर दिया. प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के कुछ निर्देश मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं. उन्होंने कहा कि अन्ना के ऐतराज़ जताए बिना आयोग को क्या आपत्ति हो सकती है? यह भी अजीब तर्क़ है. अब तक इसी चुनाव आचार संहिता के तहत चुनाव होते आए हैं. तब किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ, लेकिन आप को एक ज़रा सी नोटिस गई कि आप के नेता मौलिक अधिकारों का हनन की दुहाई देने लगे. शायद प्रशांत भूषण यह भूल गए कि अन्ना अपने नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करने पर अपनी आपत्ति कई बार सार्वजनिक कर चुके हैं. दूसरी बात यह कि प्रशांत भूषण व आम आदमी पार्टी के नेताओं को अन्ना हजारे के आंदोलन व उनकी गतिविधियों के बारे में अब कोई जानकारी नहीं रहती है. अरविंद केजरीवाल चुनावी राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें शायद इस बात को जानने की भी फ़ुर्सत नहीं है कि अन्ना अपनी देशव्यापी जनतंत्र यात्रा और अपनी सभाओं में आजकल क्या कह रहे हैं. इसलिए वो समझ नहीं पाए कि चुनाव आयोग ने आख़िर ये नोटिस क्यों दिया है.

दरअसल, अन्ना पूरे देश में घूम कर राजनीतिक दलों की संवैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं. उनका मानना यह है कि भारत के संविधान में जब राजनीतिक दल शब्द ही नहीं है तो इस देश की राजनीतिक सत्ता पर राजनीतिक दलों का कब्ज़ा कैसे हो गया? अन्ना कहते हैं कि राजनीतिक दलों ने देश की राजनीति को पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा बनाने का ज़रिया बना लिया है. उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कोई रियायत नहीं दी है. साथ ही, जब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रिजेक्ट पर फ़ैसला सुनाया और चुनाव आयोग से नापसंदी का बटन ईवीएम में डालने को कहा तो अन्ना ने यह फ़ैसला किया कि वो राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों को जागरूक करने व नापसंदी पर वोट डालने की अपील करेंगे. इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा. इस पत्र में उन्होंने लिखा कि उनका यह अभियान सभी राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़

(शेष पृष्ठ 3 पर)

आप दिल्ली की प्रजाराज्यम है?

आंध्र प्रदेश में 2009 में विधानसभा के चुनाव हुए. यहां दो पार्टियों के बीच सत्ता की लड़ाई होती आई है-कांग्रेस और तेलुगू देशम पार्टी यानी टीडीपी. इस राज्य में 2008 में एक प्रजाराज्यम पार्टी बनी. इसके नेता फिल्म स्टार चिरंजीवी थे. उनकी पहली ही रैली में 10 लाख लोग आ गए. एक साल तक यह पार्टी आंध्र प्रदेश में धुआंधार रैलियां करती रही. रैलियां बड़ी होती थीं. राजनीतिक दलों के हाथ-पांव फूलने लगे. ऐसा लगने लगा था कि सचमुच प्रजाराज्यम की सरकार बनने वाली है. पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए. तेलुगू देशम पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताकर चिरंजीवी ने सरकार बनाने का दावा किया. जब नतीजे आए तो इस पार्टी को 294 में से मात्र 18 सीटें मिलीं. कांग्रेस फिर से चुनाव जीत गई. कुछ समय बाद चिरंजीवी की पार्टी प्रजाराज्यम का कांग्रेस में विलय हो गया. चिरंजीवी आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं. सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी कहीं दिल्ली की प्रजाराज्यम पार्टी तो नहीं है?

अन्ना आंदोलन के साथी आप से दूर हुए

आम आदमी पार्टी में अन्ना आंदोलन के कुछ गिने चुने लोग ही रह गए हैं. अन्ना आंदोलन में काफी सक्रिय रहे अन्ना के लोकपाल को जनलोकपाल का नाम देने वाले महेश गिरि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. पूर्वी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई. रामलीला मैदान के आंदोलन की सफलता के पीछे महेश गिरि थे. साथ ही सोशल मीडिया के जरिए अन्ना के आंदोलन को युवाओं में प्रचारित करने वाले शिवेंद्र चौहान भी इस का कार्यक्रम में स्टेज पर मौजूद थे. आज भी अन्ना आंदोलन के फेसबुक और ट्वीटर अकाउंट उनके पास हैं. इन दोनों के अलावा इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक और फाउंडिंग मेम्बर पूर्वी दिल्ली के गौरव बक्शी ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ स्टेज शेयर किया. आम आदमी पार्टी को इस पर विचार करना होगा कि आख़िर पुराने दोस्त उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं?

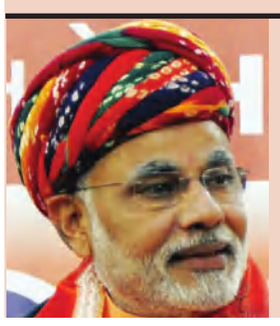

राहुल और नरेन्द्र मोदी में किसका जादू चलेगा 03

चुप्पी तोड़कर हमलावर हुई बसपा 04

तीसरा मोर्चा और नीतीश की दुविधा 05

साई की महिमा 12

आम आदमी पार्टी को अन्ना का समर्थन नहीं है

पृष्ठ एक का शेष

होगा. चुनाव आयोग ने चिट्ठी मिलने पर अन्ना को 25 अक्टूबर को मिलने का वक्त भी दिया. इस बीच आम आदमी पार्टी की लघु फ़िल्म में अन्ना की तस्वीर दिखी तो आयोग ने आपत्ति जता दी.

समझना यह है कि अन्ना का आंदोलन अब सिर्फ़ जनलोकपाल के लिए नहीं है. अन्ना अब सिर्फ़ भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन नहीं कर रहे हैं. अन्ना व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं. उनका मानना है कि देश में व्यवस्था परिवर्तन तभी संभव है जब व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा रखने वाले लोग लोकसभा में पहुंचेंगे. यह परिवर्तन राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं, बल्कि जनउम्मीदवार के जरिए ही संभव है. अन्ना विधानसभाओं व राज्य सरकारों को व्यवस्था परिवर्तन का टूल नहीं मानते हैं और यह सही भी है, क्योंकि देश की जो संघीय व्यवस्था है उसमें यह संभव ही नहीं है. हमारे संविधान ने केंद्र सरकार और खासकर लोकसभा को इतनी शक्तियां दी हैं कि उनकी सहमति के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है. यही वजह है कि देश में वामपंथियों की सरकार अलग अलग राज्यों में आई, लेकिन कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो सका. आम आदमी पार्टी विधानसभा के जरिए व्यवस्था परिवर्तन का दावा करके दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही है.

अन्ना का आंदोलन जनतंत्र मोर्चे के पच्चीस सूत्र व उसके नीतिगत मसौदे पर आधारित है. अन्ना अब किसी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं. अन्ना देश में एक राजनैतिक व वैचारिक क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें हर जगह से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है. जबकि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य फ़िलहाल दिल्ली की सत्ता पर क़ब्ज़ा करना है. हालांकि, सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को देश के प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की शुरुआत कर दी है. वैसे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल में तुलना करना बेमानी है, लेकिन दोनों के लक्ष्य में फ़र्क़ साफ़ नज़र आता है. अन्ना का आंदोलन एक देशव्यापी और वैचारिक बदलाव का आंदोलन है. अन्ना नवउदारवाद के सबसे सशक्त विरोधी के रूप में उभरे हैं. वह भारत में लोकहितकारी राज्य की पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे हैं. अन्ना का आंदोलन संघर्ष, त्याग व बलिदान की राह पर चल रहा है, जिसमें सत्तालोलुप महत्वाकांक्षा व अहंकार का कोई स्थान नहीं है.

दिल्ली चुनाव के बाद लोकसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है. आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन इसने देश भर में संगठन भी तैयार किया है. विदेश से पैसा आ रहा है. एनआरआई चंदा दे रहे हैं. इसलिए संसाधनों की भी कमी नहीं है. लेकिन चुनाव दिल्ली का हो या देश का, अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में हिस्सा ले रही है तो यह भी पूछना लाजिमी है कि पार्टी की विचारधारा क्या है? भारत विषमताओं का देश है. भारत जटिलताओं का देश है. इसलिए राजनीतिक दलों के लिए विचारधारा आवश्यक है. इसके बगैर भारत में राजनीति हो नहीं सकती. विचारधारा से ही पता चलता है कि कोई नेता या उसकी पार्टी देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कहां खड़ा है. अगर कोई राजनीतिक दल देश के ज्वलंत मुद्दों पर जबाव न दे. विवादित सवालों पर कोई राय नहीं हो. जनता के जीवन से जुड़ी समस्यों पर उसकी अपनी कोई राय न हो. भविष्य का कोई प्लान न हो. आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर पीठ दिखाए. राष्ट्रीय मुद्दों पर जवाब न दे तो ऐसा मान लेना चाहिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है.

हाल में ही अरविंद केजरीवाल एक टीवी इंटरव्यू से अचानक भाग खड़े हुए. सवाल सिर्फ़ ये था कि पाकिस्तान समर्थित आंतकियों पर आपकी क्या राय है. केजरीवाल का जवाब था यह सवाल देश के होम मिनिस्टर से पूछिए. एंकर ने फिर से पूछा कि दिल्ली आतंकियों के निशाने पर रही है तो उनका जवाब आया कि इसका जवाब बाद में देंगे. वो कुर्सी से उठकर चलने लग गए. लेकिन उठते–उठते एंकर ने यह भी पूछा कि गृह मंत्री की वह चिट्ठी, जिसमें मुसलमानों को बिना कसूर गिरफ़्तार करने पर रोक लगाने को कहा गया, उस पर उनकी क्या राय है? तो केजरीवाल का जवाब था कि इन सवालों का जवाब वो दिसंबर के बाद देंगे. यह एक समस्या है. दिल्ली में भी कई मुस्लिम नौजवानों को पुलिस पकड़ कर ले गई. सीलमपुर इलाके में ऐसे मामलों से लोग परेशान हैं. अगर दिल्ली का होने वाला भावी मुख्यमंत्री इन सवालों का जवाब न दे, तो इसका क्या मतलब है. ऐसे जवाब का मतलब तो यही निकलता है, चंद वोटों के लिए आप अपना स्टैंड बदलते रहेंगे.

एक और मुद्दा जिस पर आम आदमी पार्टी की राय अब तक स्पष्ट नहीं है, जबकि यह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए. यह मुद्दा कश्मीर का है. आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने एक विवादास्पद बयान दिया कि कश्मीर में रेफेरेंडम होना चाहिए और अगर कश्मीर के लोग भारत से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें अलग होने का अधिकार दे देना चाहिए. वैसे ऐसा कहना देशद्रोह से कम नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि ऐसे बयान वही दे सकता है जिसे यह पता नहीं है कि भारत के लिए कश्मीर का मतलब क्या है. भारत के लिए कश्मीर सिर्फ़ एक टेरिटरी नहीं है, बल्कि सेकुलरिज्म की गारंटी है. धर्म के नाम पर अगर कश्मीर को अगल करने का समर्थन करते हैं तो प्रशांत भूषण जी को यह भी बताना पड़ेगा कि बाकी देश के मुसलमानों का क्या होगा. इस बयान पर आम आदमी पार्टी की सफाई अभी तक बाक़ी है. प्रशांत भूषण ने इस बयान के लिए माफ़ी मांगी. अब आम आदमी पार्टी को यह बताना ही पड़ेगा कि कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है या नहीं. हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर भरोसा है या नहीं.

जब मायनॉरिटी की ही बात चली है तो आम आदमी पार्टी को यह भी बताना होगा कि कंस्टीट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल ने चंद मुसलमानों को पार्टी में शामिल करके नुमाइश तो की, लेकिन मुसलमानों के असल मुद्दे पर ख़ामोश रहे. सच्चर कमेटी ने मुसमलानों की हालत दलितों से भी ख़राब आंकी है. जिस तरह से सरकारें ख़ासकर सेकुलर पार्टियों ने मुसमलानों के साथ मज़ाक किया है उसकी वजह से मुसलमान आज देश का सबसे पिछड़ा वर्ग बन चुका है. रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट ने कई ज़रूरी क़दम सुझाए हैं, जिसमें सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन भी शामिल है. क्या आम आदमी पार्टी मुसलमानों के विकास के लिए रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने की पक्षधर है या नहीं? यह आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले बताना होगा. अगर इस मुद्दे पर कोई पार्टी कोई स्टैंड नहीं लेती है तो इसका मतलब है कि वह देश की जनता को

> **अन्ना का आंदोलन जनतंत्र मोर्चे के पच्चीस सूत्र व उसके नीतिगत मसौदे पर आधारित है. अन्ना अब किसी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं. अन्ना देश में एक राजनैतिक व वैचारिक क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें हर जगह से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है. जबकि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य फ़िलहाल दिल्ली की सत्ता पर क़ब्ज़ा करना है.**

धोखा दे रही है.

एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका कोई ज़िक्र नहीं कर रहा है. यह सवाल है खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी निवेश का. दिल्ली इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है. अगर खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी निवेश की इजाज़त मिली तो दिल्ली में सारे थोक एवं खुदरा बाज़ार पर आश्रित लोगों की रोज़ी–रोटी पर असर पड़ेगा. अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले यह बताना चाहिए कि वो खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी निवेश के पक्ष हैं या नहीं. सिर्फ़ भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात कहने से भविष्य के सवालों का हल नहीं मिल सकता है. वैसे भी जनलोकपाल से देश में भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि यह क़ानून भ्रष्टाचार हो जाने के बाद अमल में आएगा. इससे भ्रष्टाचारियों को सज़ा दिलाने में आसानी होगी. समझने वाली बात यह है कि देश के सामने भ्रष्टाचार के अलावा भी कई मुद्दे हैं जो ज़रूरी हैं. उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की राय क्या है? आम आदमी पार्टी पिछड़ों व दलितों को नौकरी व प्रमोशन में रिजर्वेशन का समर्थन करती है या नहीं? आम आदमी पार्टी देश में माओवादियों के आंतक का विरोध करती है या नहीं? आम आदमी पार्टी विदेशी धन पाने वाले एनजीओ जनलोकपाल के दायरे में लाने के पक्ष में है या नहीं? आम आदमी पार्टी की राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद पर राय क्या है? दिल्ली व पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पर आम आदमी पार्टी की राय क्या है? हिंदू आंतकवाद यानी सैफ्रन टेरर पर आम आदमी पार्टी की राय क्या है? इसके अलावा भी कई सवाल हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी के विकास का मॉडल क्या है? इसकी आर्थिक नीति क्या है? विदेश नीति क्या है? सांइस व टेक्नोलॉजी के विकास व प्रसार की नीति क्या है? निजीकरण पर पार्टी का रुख क्या है?

इस तरह के अनगिनत सवाल हैं. हर सवाल का जवाब जनलोकपाल, पारदर्शिता व विक्रेंदीकरण नहीं हो सकता है. उन मुद्दों पर पार्टी की राय अब तक सामने नहीं आई है, इसलिए भ्रम की स्थिति बनी हुई है. अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार यह कहें कि इन सवालों को जवाब दिसंबर के बाद देंगे, तब दिल्ली की जनता भी कह सकती है कि जब जवाब आ जाएगा, तब हमारे वोट लेकर जाना. इस तरह के सवाल उठाना कोई पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि वैचारिक पार्दर्शिता की मांग है. आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की पक्षधर होने का दावा करती है. अगर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी के विचार लोगों को मालूम नहीं हो, या यूं कहें कि बताया ही न जाए तो यह कैसे भरोसा पैदा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी.

चुनाव एक नशा है. इसके सामने अफीम भी फ़ीकी है. यह ऐसा नशा है जिसमें हर उम्मीदवार को लगता है कि वह भारी बहुमत से जीत रहा है. राह में मिलने वाले, तालियां बजाकर स्वागत करने वाले, हाथ हिलाने वाले और कभी–कभी सिर्फ़ सामने से मुस्कुराने वाले समर्थक नज़र आने लगते हैं. हर उम्मीदवार को लगता है कि सारे लोग उसी को वोट दे रहे हैं. उम्मीदवार अक्सर दिव–ास्वपन का शिकार हो जाते हैं. जिन नेताओं का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता और जो ज़मीनी हक़ीक़त को थामे रखते हैं, वही विजयी होते हैं. अगर ऐसा नशा सोनिया गांधी पर चढ़ जाए तो वह अहमदाबाद में मोदी से दो–दो हाथ करने पहुंच जाएंगी और अगर ऐसे ही नशे में नरेंद्र मोदी चूर हो जाएं तो वह सोनिया गांधी को हराने रायबरेली से उम्मीदवार बन जाएंगे. आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ख़िलाफ़ लड़ने का ऐलान किया है. अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है. 32 फ़ीसदी वोट मिल रहे हैं. केजरीवाल ने ख़ुद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ यह भी ऐलान कर दिया कि चुनाव जीतते ही वो रामलीला मैदान में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएंगे और जनलोकपाल बिल पास करेंगे. चुनाव में अभी एक महीने से ज़्यादा का वक़्त है. कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अभियान अभी रंग नहीं पकड़ा है. अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल के साहस की दाद देनी चाहिए या फिर इसे एक चुनावी नशा मान कर भुला देना चाहिए. ■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 34
दिल्ली, 28 अक्टूबर–03 नवंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022–42296060
	+91–8451050786
	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

लालू की नियति

दिलीप चेरियन

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में आरोपी ठहराए जाने की घटना ने एक अजीब सी खलबली मचा दी है. इस वजह से 17 साल पहले चारा घोटाले का खुलासा करने वाले 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खरे सुर्खियों में आ गए हैं. खरे वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं. चारा घोटाले के खुलासे के समय वह पश्चिमी सिंहभूम जिले में उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे. उन्हें उस समय इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके इस खुलासे की वजह से एक मुख्यमंत्री का पतन हो जाएगा. खरे को पशु प्रजनन और मत्स्य पालन विभाग में इस खुलासे को करने के कारण कई तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. उन्हें पहले तो एक निष्क्रिय विभाग में भेज दिया गया, लेकिन जब उनके पिता मृत्यु से लड़ रहे थे, तब उन्हें वापस कार्य पर बुला लिया गया था. खरे को अब तक एक निर्भीक निर्णय लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है. लेकिन अब उनके पास आत्मसंतोष के लिए कारण है. ■

ज्ञान पहेली सुलझाने की कोशिश

जब सरकार ने नौकरशाहों के वेतन वृद्धि के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया तब उत्तर प्रदेश कैडर के एक पूर्व नौकरशाह ने इस पर एक अलग प्रतिक्रिया अपने ब्लॉग में दी. और अनजाने में लेखक संजय अहलूवालिया का ध्यान आकर्षित किया. अहलूवालिया ने नौकरशाहों को मिलने वाले सरकारी

सुविधाओं मसलन आवास, फर्नीचर, घरेलू मदद, सरकारी वाहन और टेलीफोन आदि को कर के दायरे में लाने की पैरवी की. उन्होंने नौकरशाहों की वेतन वृद्धि को मंहगाई से अलग कर आर्थिक वृद्धि से जोड़ने की बात कही. जब तक नौकरशाह इससे उबर पाते उससे पहले ही उन्होंने यह बात रेखांकित कर दी कि लेखक वित्त मंत्रालय में विनिवेश विभाग में संयुक्त सचिव रह चुके हैं. विश्व बैंक भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ भाईचारा निभा रहा है. अब सारे अन्वेषक इस ज्ञान पहेली को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं. ■

पद हड़पने की संस्कृति

पहले तो सरकार सरकार स्वयं शून्य की स्थिति उत्पन्न करती है, उसके बाद नौकरशाहों को उस शून्य को भरने के लिए भेज देती है. देश की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए जिम्मेदार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान (एएसआई), भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई), राष्ट्रीय संग्रहालय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र जैसे महत्वपूर्ण संस्थान लंबे समय से पूर्णकालिक और विशेषज्ञ उच्चाधिकारियों के बिना काम कर रहे हैं. इस स्थिति में इन संस्थानों के कार्यकलापों को चलाने के लिए

संस्कृति मंत्रालय रिक्त स्थानों पर नौकरशाहों की नियुक्ति कर रहा है. आजकल संस्कृति मंत्रालय में बतौर संयुक्त संचिव के रूप में काम कर रहे प्रवीण श्रीवास्तव अब एक विशेषज्ञ के रूप में एएसआई प्रमुख का पद संभाले हुए हैं. इसी तरह उनके सहकर्मी प्रमोद जैन राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रमुख बने हुए हैं. राष्ट्रीय संग्रहालय में पिछले पांच सालों से किसी की महानिदेशक के पद पर नियुक्ति नहीं हुई है, वहां पर भी एक नौकरशाह वी वेणु प्रमुख बने हुए हैं. वे भी संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं. यह बात केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है. इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी संस्कृति संस्थानों में रिक्त उच्च पदों को भरने में कम वरीयता दे रहे हैं. इस वजह से नौकरशाह इन संस्थानों का कार्यभार संभाल रहे हैं. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

शरण खेल सचिव बने

1979 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अजीत एम शरण को खेल सचिव नियुक्त किया गया है. अजीत खेल सचिवालय में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. अब उनकी जगह युवाओं मामलों के सचिव राजीव गुप्ता कार्यभार संभालेंगे.

अरुणेंद्र अध्यक्ष बने

रेलवे बोर्ड में कार्यवाहक अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है. कुछ दिनों पहले ही रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधिकारिक तौर पर अरुणेंद्र कुमार के नाम की घोषणा की.

शर्मा स्थानांतरित हुए

1991 बैच के भारतीय रक्षा संपदा सेवा अधिकारी अनुज शर्मा गृह मंत्रालय में निदेशक के तौर पर कार्यभार संभालेंगे. शर्मा को (आप्रवासन और नागरिकता) विभाग से स्थानांतरित किया गया है.

मुखर्जी उपमहानिदेशक बने

1993 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अनिरुद्ध मुखर्जी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के उपमहानिदेशक (संयुक्त सचिव के समकक्ष) के रूप में नियुक्त किया गया है. मुखर्जी को 1983 बैच के आईएएस वी. वी. नानावटी के स्थान पर नियुक्त किया गया है.

सिंह एनआईए के प्रमुख नियुक्त

1991 बैच के असम–मेघालय के आईपीएस अधिकारी जी. पी. सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है. सिंह पुलिस महानिरीक्षक लोकनाथ बेहरा के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे. उम्मीद है कि सिंह खुफिया और नीतिगत मामले देखेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस ने राहुल गांधी को सारी ज़िम्मेदारी दे दी है, पर जानबूझ कर प्रत्यक्ष तौर पर राहुल का नाम कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं किया है. कांग्रेस ने हालिया दिनों में कुछ सफलताएं भी हासिल की हैं. कर्नाटक, हिमाचल और उत्तराखंड में वह सफल रही है. यह बात अलग है कि कांग्रेस को ये सफलता, बीजेपी की आपसी गुटबाजी की वजह से मिली है.

राहुल और नरेन्द्र मोदी में

किसका जादू चलेगा

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

रूबी अरुण

आने वाला लोकसभा चुनाव, कांग्रेस और भाजपा की बजाए नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी पर आकर टिक गया है. दोनों के लिए ही यह चुनाव उनके वजूद का सवाल बन चुका है. बड़ा सवाल यह है कि किसका जादू चलेगा? मोदी का या राहुल का? राहुल गांधी को लोग परिपक्व नेता के रूप में स्वीकारने को राज़ी नहीं हैं तो वहीं मोदी की देशव्यापी स्वीकार्यता सवालों के घेरे में है. ऐसे दुविधाग्रस्त माहौल में ख़ुद को साबित करने की ख़ातिर, राहुल गांधी और नरेन्द्र मोदी, दोनों ही अपनी-अपनी रणनीतियों से एक-दूसरे को पटखनी देने की फ़िराक़ में हैं.

सतही तौर पर देखें तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की राजनीतिक जंग में फ़िलहाल नरेन्द्र मोदी का पाला भारी दिख रहा है. इसकी वजहें हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों के ज़रिये जब भी कांग्रेस पर वार करते हैं और सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी को ललकारते हैं, तब देश के लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि शायद अब राहुल, मोदी की हुंकार का जवाब देंगे और पार्टी तथा सरकार का पक्ष रखेंगे. लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है. मोदी एक के बाद दूसरा प्रहार करते हैं और जवाब में राहुल की जगह कांग्रेस का कोई और नेता मोर्चा संभालता हुआ दिखता है. तब एक सवाल, अनायास ज़ेहन में आता है कि आख़िरकार क्यों कांग्रेस या राहुल, नरेन्द्र मोदी के आमने-सामने होने से बच रहे हैं? कांग्रेस, मोदी की तरह ही क्यों नहीं अपनी पूरी ताक़त से चुनावी समर में उतर रही है?

कांग्रेस के रणनीतिकारों के हवाले से जो ख़बर आ रही है, उसके मुताबिक कांग्रेस अभी जानबूझ कर चुप है. यह राहुल की रणनीति है. राहुल को इंतज़ार है नरेन्द्र मोदी की ऊर्जा के चुक जाने का. नरेन्द्र मोदी ने इस वक़्त अपने पक्ष में माहौल करने में बहुतेरी ऊर्जा झोंक दी है और वे पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतर कर कांग्रेस की घेरेबंदी करने में लगे हैं. चूंकि लोकसभा चुनाव होने में तक़रीबन सात महीने का लंबा समय है और कांग्रेस को यह लगता है की इस दरम्यान नरेन्द्र मोदी की गति धीमी पड़ जाएगी, साथ ही मुद्दों की कमी भी हो जाएगी. लोकसभा चुनाव आने तक नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए जाने वाले दोहराऊ आक्रामक भाषणों से भी देश की जनता ऊब चुकी होगी. तब लोगों को नयापन चाहिए होगा. ऐसे में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अपने गेम चेंजर प्रोग्राम्स के साथ जनता के सामने आंधी की तरह अवतरित होंगे और देश पर छा जाएंगे. अभी महीने-दो महीने कांग्रेस चुप ही रहेगी और मोदी के लगाए गए आरोपों के जवाब का पुलिंदा तैयार करेगी, ताकि जब राहुल देश के सामने भावी प्रधानमंत्री के तौर पर खड़े हों तो वे सभी आरोपों का जवाब दे सकें. इस दरम्यान सरकार जनहित में की कई और योजनाओं को क्रियान्वित करेगी, साथ ही पहले पास किए जा चुके विधेयकों पर भी अमल किया जाएगा. कोयला घोटाले सहित अन्य कई घोटालों की सीबीआई जांच जिस रफ़्तार से चल रही है और बड़े राजनेताओं सहित प्रधानमंत्री को भी नामज़द किए जाने की बातें उठने लगी हैं. इसमे बहुत मुमकिन है की भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप झेल रही सरकार के मंत्री और नेता सज़ायाफ़्ता होने की कगार पर पहुंच जाएं. यह स्थिति राहुल गांधी के बेहद मुफ़ीद होगी और वे इसे भी जनता के बीच भुना सकते हैं. चूंकि राहुल गांधी ने पहले ही दागी सांसदों-विधायकों के चुनाव लड़ने सम्बन्धी विधेयक के पास होने पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है.

सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पहले ही पास कर दिया है. लोकसभा चुनाव आते-आते इसके लागू हो जाने की पूरी संभावना है. मुद्रास्फीति में हालांकि, वांछित स्तर की तेज़ी नहीं आई है, पर अर्थव्यवस्था के सामने खड़ा संकट फ़ौरी तौर पर टल चुका है. सरकार ने देर से ही सही, चलते-चलते आर्थिक उदारीकरण के फ़ैसले लेने शुरू कर दिए हैं. भूमि अधिग्रहण क़ानून की वजह से दिल्ली के आसपास के इलाकों में निर्माण कार्य शुरू होंगे तो आर्थिक गतिविधियां परवान पर रहेंगी.

कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कारगर होगी इस पर फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कांग्रेस ने अपनी बनाई योजना को सही तरीके से कार्यान्वित कर लिया तो नरेन्द्र मोदी और बीजेपी की दुश्वारियां बढ़ सकती हैं. क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं. और यही चुनाव तय करेंगे कि नरेन्द्र मोदी की गुजरात के बाहर , देश के दूसरे प्रदेशों में कितनी पकड़ है. अगर इन पांच प्रदेशों में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जैसा कि कर्नाटक में हुआ तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी के लिए यह शुभ संकेत नहीं होगा. पहले भी जब पार्टी ने नरेन्द्र मोदी को महाराष्ट्र और गोवा, दमन-दीव की ज़िम्मेदारी दी थी, तब बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक़ सफलता नहीं मिली थी. जबकि उन चुनावों में मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं गए थे, तो वहां पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था. पिछले साल भी नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड नहीं गए, लेकिन पार्टी ने वहां कांग्रेस को ज़ोरदार टक्कर दी. बिहार ने भी पिछले सालों में बीजेपी को कई सीटें दीं हैं. वहां भी नरेन्द्र मोदी कभी प्रचार के लिए नहीं गए थे. 2011 के चुनावों में मोदी का कोई करिश्मा काम नहीं आया. बल्कि उसकी सीटें पहले से भी आधी हो गईं. साल 2007 में भी नरेन्द्र मोदी को संघ ने उत्तर प्रदेश चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा था. वहां बीजेपी चौथे नंबर पर पहुंच गई. देश के चार दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी की कोई ज़मीनी पकड़ नहीं है, जबकि कांग्रेस की जड़ें वहां मौजूद हैं. पूर्वोत्तर राज्यों में भी बीजेपी का लगभग यही हाल है. यूपी, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी क्षेत्रीय पार्टियों का ही बोलबाला रहेगा. ज़ाहिर है परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल नहीं हैं.

> **लोकसभा चुनाव होने में तक़रीबन सात महीने का लंबा समय है और कांग्रेस को यह लगता है की इस दरम्यान नरेन्द्र मोदी की गति धीमी पड़ जाएगी, साथ ही मुद्दों की कमी भी हो जाएगी. लोकसभा चुनाव आने तक नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए जाने वाले दोहराऊ आक्रामक भाषणों से भी देश की जनता ऊब चुकी होगी. तब लोगों को नयापन चाहिए होगा. ऐसे में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अपने गेम चेंजर प्रोग्राम्स के साथ जनता के सामने आंधी की तरह अवतरित होंगे. अभी महीने-दो महीने कांग्रेस चुप ही रहेगी और मोदी के आरोपों के जवाब तैयार करेगी.**

एनडीए भी लगभग बिखर चुका है. जिन क्षेत्रीय पार्टियों से बीजेपी गठबंधन करना चाहती है, उन पार्टियों के साथ बात नहीं बन पा रही है. नरेन्द्र मोदी की ख़ास दोस्त मानी जाने वाली तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता भी एनडीए गठबंधन में शामिल होने की इच्छुक नहीं हैं. वो तीसरे मोर्चे की परिकल्पना के तहत जदयू अध्यक्ष शरद यादव से मिलने-जुलने में मशगूल हैं. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पहले ही कह दिया है कि वे भी मोदी और राहुल में कोई रुचि नहीं रखते. उनकी कोशिश है कि तीसरे मोर्चे का गठन हो. मुलायम, ममता और मायावती को भी नरेन्द्र मोदी से हाथ मिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुलायम सिंह यादव, तीसरे मोर्चे के गठन की भरपूर कोशिशों में लगे हैं. ऐसे में एनडीए के चुनाव पूर्व गठबंधन में कोई जान होगी, इसमे संशय है. हां चुनाव के बाद परिणामों के आधार पर नए समीकरण बन सकते हैं और नए गठजोड़ हो सकते हैं, इसकी गुंजाइश है.

इन हालातों में भी बीजेपी जीत चाहती है तो उसे पूरी तरह अपने कार्यकर्ताओं की एकजुटता और सांगठनिक ढांचे का ही सहारा होगा. लेकिन फ़िलहाल बीजेपी इस मामले में भी बैकफुट पर है. पार्टी के आला नेताओं के बीच आपसी कलह की ख़बरें किसी से छुपी नहीं हैं. लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ही नहीं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह भी नरेन्द्र मोदी के नाम पर ख़ुद को असहज मानते और बताते रहे हैं. लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हो, इसकी ख़ातिर बीजेपी को हर हाल में विधानसभा चुनावों में सफलता हासिल करनी होगी. वरना कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और पार्टी की ख़राब होती स्थिति का ज़िम्मेवार नरेन्द्र मोदी को ही माना जाएगा, जिसकी वजहें भी हैं. जब नरेन्द्र मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की तैयारी हो रही थी, तब पार्टी के एक धड़े के नेताओं का कहना था कि नरेन्द्र मोदी का नाम विधानसभा चुनावों के बाद घोषित किया जाए. वरना बीजेपी को उन राज्यों में हार मिल सकती है, जहां मुस्लिम बहुल आबादी है. मसलन, मध्य प्रदेश और राजस्थान. मध्य प्रदेश की लगभग 39 सीटों पर और राजस्थान की 70 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है. मोदी की मुख़ालफ़त कर रहे इन नेताओं का कहना कि नरेन्द्र मोदी का नाम प्रधानमन्त्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किए जाने से इन जगहों पर मुस्लिम मतदाता छिटक सकता है.

बहरहाल, इस लिहाज़ से देखें तो पार्टी कांग्रेस सांगठनिक स्तर पर फिलहाल बीजेपी से बेहतर नज़र आ रही है. कांग्रेस ने राहुल गांधी को सारी ज़िम्मेदारी दे दी है, पर जानबूझ कर प्रत्यक्ष तौर पर राहुल का नाम कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं किया है. कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में आपसी कलह का वो आलम नहीं है जो बीजेपी में है. लिहाजा संगठन के स्तर पर भी कांग्रेस की स्थिति कुछ बेहतर दिख रही है. कांग्रेस ने हालिया दिनों में कुछ सफलताएं भी हासिल की हैं. कर्नाटक, हिमाचल और उत्तराखंड में वह सफल रही है. यह बात अलग है कि कांग्रेस को ये सफलता, बीजेपी की आपसी गुटबाजी की वजह से मिली है. क्योंकि पिछले नौ सालों से सरकार चला रहे यूपीए पर गंभीर आरोपों की झड़ी है. सरकार भ्रष्ट है. घोटालेबाजों की सरकार है. सरकार राष्ट्रीय और जनहितों की रक्षा नहीं कर पा रही है. सरकार पर लगे यह आरोप बीजेपी और एनडीए के लिए केन्द्रीय सत्ता पर काबिज़ होने का एक बड़ा मौक़ा मुहैया कराते हैं. लेकिन यह तभी संभव है जब बीजेपी इस मौके का इस्तेमाल संघ के प्रभाव में आकर महज़ हिन्दुत्ववादी राजनीति का परचम फहराने के लिए ना करे. इसके लिए बीजेपी को अभी ही लोकसभा चुनावों का अपना राष्ट्रीय एजेंडा घोषित करना होगा, ताकि देश के लोगों के बीच की हिन्दुत्व बनाम धर्मनिपेक्षता की भ्रम की स्थिति ख़त्म हो सके. हिन्दुत्व बनाम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में ज़ाहिर तौर पर दो ही दल आमने-सामने हैं–बीजेपी और कांग्रेस. मौजूदा हालात में बाकी पार्टियों का होना न होना एक जैसा ही है, जब तक कोई सशक्त तीसरा मोर्चा गठित नहीं हो जाता. हालांकि, देश में सन 1967 से ही ऐसे राजनीतिक विकल्पों की तलाश शुरू हो चुकी है, जिसने अलग-अलग वक़्त में अनेक शक्लें भी अख़्तियार की हैं. पर वो कभी भी बीजेपी या कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सके. मौजूदा माहौल में तीसरे मोर्चे के गठन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन क्षेत्रीय, भाषाई, उत्तर-दक्षिण, सांप्रदायिक मसलों पर आकर ये संभावनाएं बिखर जा रही हैं. और आखिर में सारा सियासी खेल फिर आकर मोदी या राहुल पर टिक जा रहा है. जब बात देश भर की हो तो क्या मोदी और क्या राहुल, दोनों एक ही पलड़े में नज़र आते हैं. ऐसे में सवाल फिर वहीं अपनी जगह है कि राहुल या मोदी? किसका जादू चलेगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

बसपा नेता गांव–गांव व कस्बे–कस्बे में जाकर दलित नेता जगजीवन राम को प्रधानमंत्री न बनने देने से लेकर डॉ अंबेडकर की राह में कांग्रेस की ओर से मुश्किलें खड़ी करने के किस्से दलित वोटरों को सुनाएंगे. कांग्रेस शासित राज्यों में से एक में भी दलित मुख्यमंत्री न बनाने की बात भी बताएंगे. बसपा दलित समाज को बताएगी कि किस तरह से कांग्रेस ने दलित नेता जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया.

चुप्पी तोड़कर हमलावर हुई बसपा

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियों पर निगाह डालने पर ऐसा लगता है कि भाजपा, कांग्रेस और सपा वहां पुरज़ोर सक्रियता दिखा रही हैं और बसपा ख़ामोश रहकर राजनीतिक मैदान में उतर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं. राहुल गांधी के माया को दलित विरोधी बताने के बाद मायावती और उनकी पार्टी हमलावर हो गई है. पार्टी नेता उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रणनीतियां बना रहे हैं. मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलने का आदेश भी दे दिया है.

अजय कुमार

बसपा को चुनावी चिंता सताने लगी है. चुनावी सर्वे उसके ख़िलाफ़ आ रहे हैं. यूपी की राजनीति सपा–भाजपा और कांग्रेस में सिमटते देख दलित चिंतकों के पसीने छूटने लगे हैं. आमतौर पर हमलावर रहने वाली माया दंगों के बाद की राजनीति में खामोश रहकर फायदे का सपना देख रही थीं, उसे पूरा न होते देख बसपा नेताओं द्वारा ओढ़ी गई चुप्पी टूटने लगी है. माया अपने चिरपरचित अंदाज में हमलावर हो गई हैं. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने मायावती पर किसी अन्य दलित नेता को नहीं उभरने देने का आरोप क्या लगाया, बसपा की सारी चुनावी रणनीति ही बदल गई. पहले तो बसपा नेताओं ने राहुल पर जुबानी हमला बोलकर उन्हें और उनकी पार्टी को दलित विरोधी करार दिया. उसके बाद दूरगामी रणनीति के तहत बसपा सुप्रीमो दलित वोटरों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए कमर कस कर मैदान में उतर पड़ी हैं. दलित राजनीति का गढ़ माने जाने वाले बुंदेलखंड के रॉठ कस्बे (हमीरपुर) में 22 अक्टूबर को होने वाली राहुल गांधी की रैली का टलना बसपा के लिए सोने में सुहागा जैसा रहा. रैली टलने के बाद कांग्रेसी मुंह छिपाए घूम रहे हैं. कांग्रेसी नेता ऑफ द रिकॉर्ड कहने में हिचकिचा नहीं रहे हैं कि राहुल की रैली की कामयाबी पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा था. इसीलिए ऐन मौके पर कांग्रेस ने विचार बदल दिए. इसका पता था कि रैली अगर असफल हो जाती तो राहुल सवालों के घेरे में आ जाते. उनके विरोधी खासकर बसपा नेता दलित रूपी जिन्न को बाहर निकाल कर राहुल के लिए मुसीबत खड़ी कर देते. बसपा और कांग्रेस के बीच जिस तरह से टकराव देखने को मिल रहा है, उसके बाद उन राजनीतिक पंडितों ने अपना मुंह बंद कर लिया है, जो 2014 के समर में कांग्रेस–बसपा के बीच गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे थे.

बहरहाल, बसपा यूं ही नहीं परेशान है. कांग्रेस काफी शिद्दत के साथ मुसलमानों के साथ–साथ दलितों और अति पिछड़ों को भी अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश में है. दलितों को जोड़ने के लिए राहुल गांधी के इशारे पर पूर्व नौकरशाह और कांग्रेसी सांसद पीएल पुनिया को और अति पिछड़ों को कांग्रेस के पक्ष में लुभाने के लिए बेनी प्रसाद वर्मा को आगे किया गया है. वोटों के गणित को समझा जाए तो विभिन्न राजनीतिक दलों के दलित प्रेम की असलियत का खुलासा हो जाता है. करीब–करीब सभी लोकसभा क्षेत्रों में दलित वोटरों की अच्छी–खासी तादाद है. आंकड़े बताते हैं कि 60–70 हजार दलित वोटर सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपना दबदबा रखते हैं. दलित कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बसपा के उदय के बाद दलित समाज उनके पीछे गोलबंद हो गया. बसपा ने लम्बे समय तक सिर्फ और सिर्फ दलितों की ही राजनीति की, लेकिन उसे यह समझते देर नहीं लगी कि दलित वोटरों के सहारे उसकी राजनीति ज्यादा ऊंचाइयां नहीं छू सकती है. इसके बाद बसपा सर्वजन हिताय की बात करने लगी, मगर इससे उसके दलित वोटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. समय–समय पर विभिन्न दलों के नेता यह कहकर माया पर हमला भी बोलते रहते हैं कि वह दलितों की नहीं, दौलत की बेटी हैं. इसके पीछे का मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरह से कुछ प्रतिशत ही सही, बसपा का दलित वोट बैंक इधर–इधर झटक कर उनके पाले में आ जाए.

यह बात बसपा को समझते देर नहीं लगी. बसपा ने अपने कोऑर्डिनेटरों को कांग्रेस को दलित विरोधी साबित करने के लिए राज्यव्यापी मुहिम चलाने का निर्देश दे दिया है. इसके तहत बसपा नेता गांव–गांव व कस्बे–कस्बे में जाकर दलित नेता जगजीवन राम को प्रधानमंत्री न बनने देने से लेकर डॉ अंबेडकर की राह में कांग्रेस की ओर से मुश्किलें खड़ी करने के किस्से दलित वोटरों को सुनाएंगे. कांग्रेस शासित राज्यों में से एक में भी दलित मुख्यमंत्री न बनाने की बात भी बताएंगे. बसपा दलित समाज को बताएगी कि किस तरह से कांग्रेस ने दलित नेता जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया. डॉ. अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ने में कैसे रोड़े अटकाए. बसपा संस्थापक काशीराम की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया. बसपा शासनकाल में दलित मुख्यमंत्री मायावती को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए किस तरह से सूबे के विकास के लिए पैकेज मांगने पर नहीं दिया. कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया जाएगा कि दरअसल, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में बसपा का जनाधार बढ़ने से कांग्रेस के युवराज परेशान हैं. इसीलिए अचानक उनका दलित प्रेम उजागर हो गया है और वह तथ्यहीन बातें करने लगे हैं.

बसपा, कांग्रेस पर हमला बोलेगी तो अपने कामों का भी ढिंढोरा दलित वोटरों के बीच पीटेगी. वह दलित वोटरों को बताएगी कि उसने गांव–गांव दलित नेतृत्व तैयार करने का काम किया. कोऑर्डिनेटर के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर दलित नेताओं को मजबूत नेतृत्व का मौका दिया. बसपा शासनकाल में दलितों के लिए कई योजनाएं बनाकर उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया गया. इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि पहले मान्यवर काशीराम और उसके बाद बहन मायावती ने दलितों में स्वाभिमान जगाया, उनको समाज में मान–प्रतिष्ठा दिलाई, जो कांग्रेस और अन्य किसी दल ने कभी नहीं चाहा.

सात अक्टूबर को राहुल गांधी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में आरोप लगाया था कि काशीराम ने दलितों को मजबूत करने का काम किया था, वहीं मायावती ने दलित आंदोलन के नेतृत्व पर कब्जा कर रखा है और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती हैं. बसपा सुप्रीमो ने दो दिन बाद पलटवार करते हुए कांग्रेस को दलित विरोधी करार दिया था.

बसपा के एक वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर बताते हैं कि हाल में पार्टी ने प्रदेश भर के कोऑर्डिनेटरों की एक बैठक बुलाई थी. इसमें चुनावी तैयारी की समीक्षा के अलावा निर्देश दिया गया कि गांव–गांव, कस्बा–कस्बा व चट्टी–चौराहों पर पहुंच बढ़ाकर कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता की बखिया उधेड़ी जाए. बसपा प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर से लेकर राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी व स्वामी प्रसाद मौर्य तक ने कई उदाहरण देकर बताया कि किस तरह कांग्रेस ने दलित नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने दिया. अब पार्टी पदाधिकारियों ने इस निर्देश के अनुसार अपनी बैठकों में अपने कार्यकर्ताओं को इस बारे में समझाने व रणनीति के तहत गांव–गांव जाकर इसे मतदाताओं को बताने का काम शुरू कर दिया हैं. माना जा रहा है कि दलितों में बिखराव रोकने के लिहाज से बसपा ने यह योजना बनाई है. उधर, कांग्रेस के सांसद और यूपी में उसका दलित चेहरा बने पीएल पुनिया जो कभी माया के सबसे अधिक वफादार नौकरशाह हुआ करते थे, माया के दावों की हवा निकालते हुए कहते हैं कि दलितों के उत्थान में मायावती ने कोई योगदान नहीं दिया. माया ने दलितों के सहारे सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाई. काशीराम ने ही दलितों में राजनीतिक चेतना पैदा की थी, उनकी बोयी फसल को ही माया ने काटा. दलितों के हितों के जितने भी कानून हैं, वह सबके सब कांग्रेस ने ही बनाए हैं. बसपा के पास जो भी वोट बैंक है, वह सब कांग्रेस का है और एक बार फिर कांग्रेस की तरफ लौट रहा है. इधर, पूर्व कैबिनेट मंत्री वकार अली कहते हैं कि राहुल गांधी खुद के ब्राह्मण होने पर गर्व जताकर अपनी मानसिकता को उजागर कर चुके हैं. बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजबहादुर से लेकर रामधीन तक तमाम दलित नेताओं की कांग्रेस में जो दुर्गति हुई है, इसके बाद कांग्रेस दलितों के लिए भरोसेमंद पार्टी नहीं रह गई है.

कांग्रेस से दलित वोटरों को बचाने के अलावा बसपा, भाजपा पर भी नजरें जमाए हुए है. कांग्रेस को दलित विरोधी तो भाजपा और उसके पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को पिछड़ा विरोधी करार दिया जा रहा है. बसपा नेता बता रहे हैं कि किस तरह से गुजरात का नेतृत्व कर रहे मोदी सर्वाधिक प्रभावशाली जातियों में से एक पटेल बिरादरी के नेताओं के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं. पटेल जाति के नेताओं को हाशिये पर डाल दिया गया है. मोदी की दगाबाजी के कारण हाशिये पर डाले गए दिग्गज नेता केशूभाई पटेल बसपा के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं. पटेल के बहाने बसपा कुर्मी वोटरों को बसपा के करीब लाना चाहती है. ■

> **कांग्रेस से दलित वोटरों को बचाने के अलावा बसपा, भाजपा पर भी नज़रें जमाए हुए है. कांग्रेस को दलित विरोधी तो भाजपा और उसके पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को पिछड़ा विरोधी क़रार दिया जा रहा है. बसपा नेता बता रहे हैं कि किस तरह से गुजरात का नेतृत्व कर रहे मोदी सर्वाधिक प्रभावशाली जातियों में से एक पटेल बिरादरी के नेताओं के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं. पटेल जाति के नेताओं को हाशिये पर डाल दिया गया है. मोदी की दग़ाबाज़ी के कारण हाशिये पर डाले गए दिग्गज नेता केशूभाई पटेल बसपा के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं.**

पिछले चुनाव में बसपा का प्रदर्शन

आगले कुछ महीनों में जिन पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें से चार में बसपा का जनाधार बढ़ रहा है. लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इन चुनावों में बसपा बेहतर प्रदर्शन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. बसपा प्रमुख मायावती मिजोरम को छोडकर चार अन्य राज्यों के चुनाव प्रबंधन में जुटी हैं. पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ और दिल्ली में अपने पिछले प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहती है. इन राज्यों के 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार थी. मुख्यमंत्री रहते मायावती ने इन राज्यों में से मध्य प्रदेश की सात, राजस्थान की छह तथा दिल्ली व छत्तीसगढ़ की दो–दो सीटों पर नीला झंडा लहराया था. पार्टी को दिल्ली में 14 फीसद वोट मिले थे, लेकिन अन्य राज्यों में 6–8 फीसद वोट ही मिल सके थे. हालांकि, जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जनाधार बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी पिछले चुनाव में दहाई का अंक नहीं छू सकी थी. मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने तीसरी शक्ति के रूप में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई थी. हालांकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में बसपा ने महज़ 7 सीटें ही हासिल की थीं, पर 19 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे, जहां बसपा ने कहीं कांग्रेस, तो कहीं भाजपा को पीछे छोड़ कर नंबर दो पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. चौदह विधानसभा क्षेत्र में बसपा ने 25 से 30 हज़ार वोट पाए थे और तकरीबन 70 विधानसभा क्षेत्रों में बसपा के उम्मीदवारों ने 10 से 20 हज़ार तक वोट हासिल कर लिए थे. मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में 143 सीटें हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी. कांग्रेस को 71 सीटें मिलीं थीं और 7 सीटें जीतने वाली बसपा ने 57 अन्य सीटों पर अपनी दमदार उपस्थिति दिखाई थी. राज्य में पार्टी को कुल 8.97 फीसद वोट मिले थे. मध्य प्रदेश में बसपा के पास एक लोकसभा सीट भी है. छत्तीसगढ़ में बसपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उसे मात्र दो सीटें मिल सकीं, लेकिन 6.11 प्रतिशत वोटों के साथ पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी. 2008 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 39.88 प्रतिशत वोट मिले थे. भाजपा को 36.43 प्रतिशत, जबकि 14.5 प्रतिशत वोट बसपा को मिले थे. हालांकि बसपा के खाते में दिल्ली विधानसभा की दो सीटें आईं थीं. यहां कांग्रेस के पास 34 सीटें, भाजपा के पास 10 सीटें, बसपा के पास दो सीटें और दो सीटें अन्य के पास हैं. राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा दो सीटों से छह पर पहुंची. उसे कुछ 7.60 फीसद वोट मिले थे. पंजाब में 35 फ़ीसद से अधिक दलित आबादी है, पर बसपा अभी तक यहां के दलितों में अपनी पैठ नहीं बना सकी है. अभी तक यहां बसपा की भूमिका वोटकटवा तक ही सीमित है. पंजाब की 37 दलित जातियां, अपने–अपने हिसाब से अलग–अलग पार्टियों को समर्थन देकर यहां सरकार बनवाती रही हैं. बसपा के लिए यहां काफी संभावना है. छत्तीसगढ़ में 11.61 प्रतिशत दलित वोट बैंक है, जबकि राजस्थान में 17.09 प्रतिशत दलित मतदाताओं की हिस्सेदारी है, जो बसपा के लिए संभावना है.

feedback@chauthiduniya.com

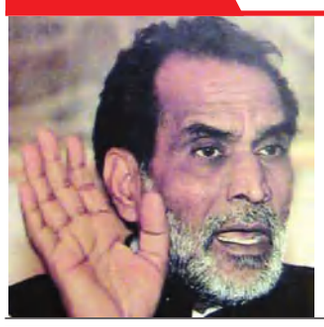

> यह भारतीय मानसिकता है कि अगर ख़ुद को सेक्युलर साबित करना है तो आपको वामदलों के क़रीब रहना होगा या फिर यह दिखाना होगा कि आप कांग्रेस के विरोधी नहीं हैं. इसी होड़ में नीतीश फ़िलहाल दोनों काम कर रहे हैं. नीतीश के क़रीबी भी मानते हैं कि नीतीश हमेशा अपने विकल्प खुले रखते हैं.

राजनीतिक विकल्प की मुश्किलें

तीसरा मोर्चा और नीतीश की दुविधा

शशि सागर

बात समता पार्टी के दिनों की है. तब नीतीश और उनकी समता पार्टी का बिहार में माले के साथ गठबंधन हुआ था. दोनों ने मिलकर चुनाव भी लड़ा था. छह सीटें हाथ लगी थीं. आशा के अनुरूप फल नहीं मिलने पर उन्होंने 1996 में भाजपा के साथ गठबंधन किया. नीतीश और उनकी पार्टी की विचारधारा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कभी एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ गलबहियां कर रहे नीतीश अचानक से एक्सट्रीम राइट के साथ चले गए. दोनों के ही साथ उन्होंने निभाया भी लंबे समय तक. अब अलग हुए हैं तो छाती पीट-पीटकर एक-दूसरे को कोस भी रहे हैं. दोनों एक-दूसरे को विश्वासघाती बताने पर तुले हुए हैं, लेकिन इन सब उठापटक के बीच नीतीश के साथ अब दूसरी समस्याएं आ खड़ी हुई हैं.

अब जब नीतीश अलग हो चुके हैं तो वह अपनी सेक्युलर छवि को और दुरुस्त करने की फिराक में लगे हुए हैं. और यह भी सच है कि नीतीश अब राष्ट्रीय राजनीति में अलग-थलग पड़े हुए नेता हैं. एक चिंता जो उन्हें खाए जा रही है कि अब उनकी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने वाला कोई बड़ा दल उनके पास नहीं है. दूसरी उहापोह कि स्थिति यह है कि अब वे किस आधार पर लोकसभा चुनाव में वोट मांगेंगे. किसके लिए लोकसभा की राजनीति करेंगे और किसके बदौलत करेंगे. इसी का नतीजा है कि वे वाम दलों के कन्वेंशन में शामिल होने दिल्ली भी जा रहे हैं. हालांकि, राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि यह नीतीश की मजबूरी भी है. भाजपा से अलग होने के बाद अब उनके सामने कई तरह के संकट एक साथ आ खड़े हुए हैं. पहला यह कि अब उनके पास कैडर की कमी है और दूसरा यह कि अब उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अपने अस्तित्व को भी बचाए रखने में भी मुश्किल आ रही है. यह भारतीय मानसिकता है कि अगर आपको खुद को सेक्युलर साबित करना है तो आपको वामदलों के करीब रहना होगा या फिर यह दिखाना होगा कि आप कांग्रेस के विरोधी नहीं हैं. इसी होड़ में नीतीश फिलहाल दोनों काम कर रहे हैं. नीतीश के करीबी भी मानते हैं कि नीतीश हमेशा अपने विकल्प खुले रखते हैं. यही वजह है कि भाजपा से अलग होने से पहले से ही कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव दिखने लगा था. यह देखने को मिला कि भाजपा से अलग होने के बाद जदयू सपा की राह पर ही चल पड़ी. संसद के मानसून सत्र में जदयू सपा की तरह ही बयान और चर्चा में तो केंद्र का विरोध करते नजर आई, लेकिन मतदान में सरकार के सहयोग की राह चुन ली. यह गौर करने की बात है कि भाजपा के साथ रहते हुए जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन भाजपा से अलग होते ही पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली. दरअसल, गठबंधन की समाप्ति के बाद नीतीश कांग्रेस और वामदल दोनों को तौल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत पर लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरह ही राज्य में जदयू और राजद को एक साथ साधे रखने की रणनीति पर काम कर रही है.

नीतीश कांग्रेस को प्राथमिकता देंगे, यह दिखता भी है, लेकिन कांग्रेसी यह मानते हैं कि लालू के साथ बनने और निभने का उनका लंबा अनुभव है. ऐसे में नीतीश दुविधा की स्थिति में हैं. नीतीश ने दूसरे कार्यकाल में आने के बाद विधायक फंड को समाप्त कर दिया था. जदयू के कुछ नेता भी स्वीकारते हैं कि यही वजह है कि आज हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी भी है. पिछले दिनों ही जदयू ने सदस्यता बढ़ाने के लिहाज से पेड़ लगाओ अभियान भी चलाया था, लेकिन यह अभियान भी परवान नहीं चढ़ सका. अभी स्थिति यह है कि उन्हें कैडर क्राइसिस के दौर से गुजरना पड़ रहा है. साथ ही हाल के कुछ घटनाओं के बाद उनके फेस वैल्यू में भी गिरावट आई है. नीतीश इन दोनों मुश्किलों से निकलने के लिए वामदलों को साधना चाह रहे हैं. जदयू के एक सांसद ही कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और अगर हमारे मुखिया वामदलों से समझौता करते हैं तो उन्हें कम से कम दस जिलों में बढ़त हासिल हो सकती है. यह सच है कि नीतीश अपनी पार्टी के सेनापति भी खुद हैं और राजा भी और ऐसी स्थिति में उन्हें सूबे में राजद और भाजपा दोनों से लड़ना है. एक सीमा के बाद नीतीश भाजपा को कुछ नहीं कह सकते हैं, भले नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाख बयानबाजी कर लें. ऐसे में उन्हें एक मजबूत साथी की सख्त आवश्यकता है. कांग्रेस विश्वास मत के दौरान नीतीश को समर्थन कर चुकी है, लेकिन नीतीश यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में उनकी हैसियत लालू प्रसाद से अधिक होगी या नहीं. सीपीआई ने भी अपने एक विधायक के साथ उनका समर्थन किया ही है और इसमें कोई शक नहीं है कि सीपीआई सूबे में मजबूत पकड़ रखती है. सीपीएम का राज्य में भले ही मजबूत जनाधार नहीं हो, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से वह नीतीश की मददगार हो सकती है, लेकिन संशय यह है कि तीसरा मोर्चा बनेगा या नहीं.

तीसरे मोर्चे की कल्पना वामदलों के बगैर नहीं की जा सकती है और वामदलों के शामिल होते ही ममता बनर्जी का बिदकना तय है. इसके बाद भी समस्या यह है कि कोई भी क्षेत्रीय क्षत्रप आसानी से किसी को अपना नेता स्वीकार नहीं करेगा. राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं कि अल्पसंख्यक वोट के लिए भाजपा से अलग हो जाना ही काफी नहीं है. लालू कांग्रेस को बिना शर्त ही समर्थन करने को तैयार हैं, जो नीतीश से नहीं होगा, तो दिक्कत नीतीश के साथ है कि वे थर्ड फ्रंट में तो तब जाएंगे, जब बनेगा. अभी तो उसकी संभावना ही क्षीण है. यही वजह है कि नीतीश फिलहाल दो नावों की सवारी कर रहे हैं. वहीं माकपा के भगवान प्रसाद सिन्हा किसी तीसरे मोर्चे की संभावना से ही फिलहाल इन्कार करते हैं. उन्होंने कहा कि तीस अक्टूबर को, जो वाम मोर्चे का कन्वेंशन है, वह किसी तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद नहीं है. हमारा कन्वेंशन तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ लाने की कोशिश मात्र है. उन्होंने स्वीकारा कि तीसरा मोर्चा डिस्क्रेडिट हो चुका है और इसके नेताओं ने अपनी साख गवां दी है. यह वामपंथियों के तीसरे विकल्प की राजनीति है. आगे उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते उभर कर आई सांप्रदायिक ताकतों और उसके तथाकथित गुड गवर्नेंस को उजागर किया जाए.

अब नीतीश के साथ समस्या यह है कि क्या वे उस कांग्रेस के साथ जाएंगे, जिनके विरोध की राजनीति करके ही वे यहां तक पहुंचे हैं? और गैर कांग्रेसवाद की परंपरा ही उनकी पहचान रही है. इसके अलावा, जो दूसरा विकल्प है तीसरे मोर्चे के रूप में, उसके बनने से पहले ही उस पर शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं. ऐसे तीसरे मोर्चे के अन्य आकांक्षियों के साथ-साथ नीतीश की राह भी कठिन नजर आ रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक असफलताओं का तीसरा विकल्प

चौथी दुनिया ब्यूरो

गैर-कांग्रेसवाद का नारा देकर सत्ता में आई जनता सरकार की भी असफलता के बाद भारतीय राजनीति में तीसरे मोर्चे का विचार सामने आया. गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा का नारा लगाने वाला तीसरा मोर्चा जब भी बना, बुरी तरह विफल हुआ. सबसे पहले 1989 में तीसरे मोर्चे के रूप में एक राजनीतिक ताकत ने आकार लिया था. इस मोर्चे में जनता दल, डीएमके, टीडीपी और असम गण परिषद शामिल थीं. विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी. भाजपा और वामपंथियों ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया, हालांकि, सरकार 11 महीने से ज्यादा नहीं चली.

इसके बाद 1996 में आम चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की स्थिति में संयुक्त मोर्चा गठित हुआ. दलों को मिलाकर बने मोर्चे ने सरकार बनाई और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने. देवगौड़ा सरकार को बाहर से कांग्रेस का भी समर्थन था. अंतर्विरोधों के इस मोर्चे में मुलायम सिंह की पहली कोशिश लालू यादव को प्रधानमंत्री न बनने देने की रही. फलस्वरूप कर्नाटक के किसान नेता देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए. इस सरकार ने सीबीआई को खुली छूट दी. नतीजतन चारा घोटाले की जांच ने तूल पकड़ लिया. उधर, बोफोर्स जांच ने रफ्तार पकड़ी, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई और संयुक्त मोर्चा ने प्रधानमंत्री पद से देवगौड़ा को हटा दिया. इंद्रकुमार गुजराल से कांग्रेस नेताओं के रिश्ते अच्छे थे. कांग्रेसियों में उनके भरोसे की वजह से गुजराल प्रधानमंत्री बनाए गए. बावजूद इसके, यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी. जब-जब तीसरा मोर्चा सत्ता में आया, पदों को लेकर ऐसी होड़ मची कि मोर्चा सरकार हर बार अकाल मौत मर गई. कहने को तीसरा मोर्चा गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा के नारे का नतीजा था, लेकिन जनता को मजबूत व्यवस्था देने की जगह इसने हर बार अस्थिरता की स्थिति पैदा की और नेताओं ने सत्ता का भरपूर दुरुपयोग व दोहन किया. संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए जिस तरह के गठजोड़ की राजनीति का प्रयोग हुआ, उसका लाभ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मिला और एनडीए सत्ता में आया.

2009 के आम चुनाव में एडीए और यूपीए को सत्ता से दूर रखने के नाम पर तीसरे मोर्चे का गठन हुआ. देश को नये विकल्प की जरूरत के नाम पर यह इस बार यह मोर्चा वाम दलों ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर बनाया था, जिसमें माकपा, भाकपा, जनता दल सेकुलर, तेलुगू देशम पार्टी, बसपा, एआइएडीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक और जनहित कांग्रेस आदि पार्टियां शामिल थीं. हालांकि, चुनाव में इस मोर्चे को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और यूपीए गठबंधन फिर से सत्ता में लौटा.

दरअसल, तीसरा मोर्चा सत्ता का ऐसा गठजोड़ है, जिसके तहत अल्पमत को बहुमत में बदला जाता है. आज जो भी नेता तीसरे मोर्चे की राजनीति कर रहे हैं, उनमें से एक भी नेता न तो किसी मजबूत विकल्प की बात कर रहे हैं, न ही उनके पास ऐसी कोई राजनीतिक सोच है कि वे जनता को यह समझा सकें कि अगर तीसरा मोर्चा सत्ता में आएगा तो भाजपा या कांग्रेस की अगुआई वाली सरकारों से बेहतर विकल्प देगा. कांग्रेस और भाजपा के इतर राजनीतिक नीतियों और विकल्प का अभाव तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट की पहली खामी है. इसके अलावा तीसरे मोर्चे की राजनीति कर रहे नेता अपने दूसरे सहयोगी को प्रमुखता बख्शने की हालत में नहीं हैं. लालू प्रसाद जेल में हैं. केंद्र में रक्षामंत्री रह चुके मुलायम यादव की येनकेन प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा जगजाहिर है. नीतीश कुमार तो एनडीए में भी अपने को अधिक तवज्जो दिए जाने की आशा पाले बैठे थे. ममता बनर्जी और वामदलों का छत्तीस का आंकड़ा उन्हें साथ नहीं आने देगा. करुणानिधि लंबे समय से केंद्र के खिलाड़ी हैं. जयललिता, नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू भी अपनी दावेदारी कमजोर नहीं समझते, क्योंकि ये सभी अपने-अपने क्षेत्र के क्षत्रप हैं. ऐसे में अगली लोकसभा में कोई तीसरा मोर्चा आकार ले सकेगा, यह कल्पना मात्र ही लगती है. हालांकि, तीसरे मोर्चे के लिए मुलायम सिंह यादव खास तौर से सक्रिय दिखते हैं और बार-बार काठ की हांडी में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं. ■

वीपी सिंह

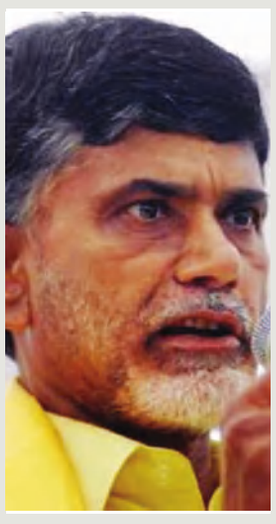

चंद्रबाबू नायडू

एच डी देवगौड़ा

मुलायम सिंह यादव

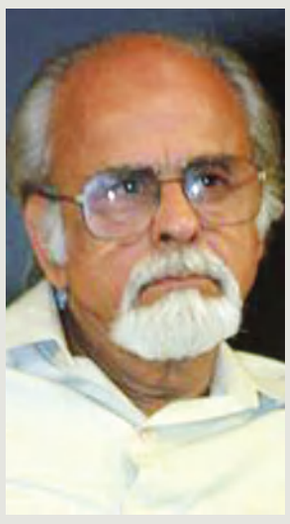

इंद्रकुमार गुजराल

प्रकाश करात

> दरअसल, तीसरा मोर्चा सत्ता का ऐसा गठजोड़ है, जिसके तहत अल्पमत को बहुमत में बदला जाता है. आज जो भी नेता तीसरे मोर्चे की राजनीति कर रहे हैं, उनमें से एक भी नेता न तो किसी मजबूत विकल्प की बात कर रहे हैं, न ही उनके पास ऐसी कोई राजनीतिक सोच है कि वे जनता को यह समझा सकें कि अगर तीसरा मोर्चा सत्ता में आएगा तो भाजपा या कांग्रेस की अगुआई वाली सरकारों से बेहतर विकल्प देगा.

feedback@chauthiduniya.com

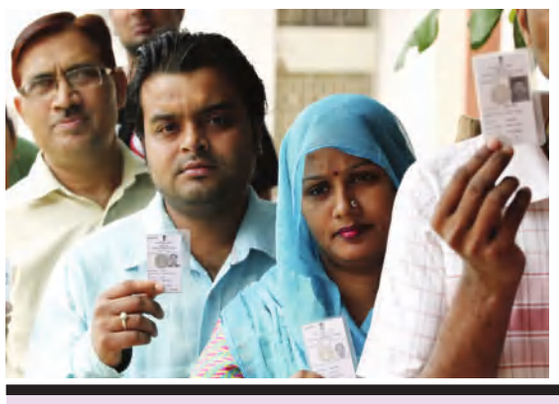

उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की परिणति के तौर पर कई पंथ निकले, लेकिन उन पंथों ने जाति को समाप्त नहीं किया. भक्ति आंदोलन की उपज सिख पंथ को जब गुरुनानक साहिब ने शुरू किया था, तो उसके पीछे जातिगत भेदभाव को दूर करना उनका बहुत बड़ा मकसद था, लेकिन आज खुद सिख समुदाय में अनेक जातियां हैं. जैन धर्म को मानने वाले लोग भी जातियों में बंटे हुए हैं.

कर्नाटक

जातिगत राजनीति का चेहरा

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की पूरी राजनीतिक लड़ाई ही जाति के आधार पर लड़ी जाती है. यहां की राजनीति मुख्यत: लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के बीच केंद्रित रही है. हालांकि, मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस व्यवस्था को तोड़ा और वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने जो राज्य के तीसरे राजनीतिक समुदाय कुरुबा से आते हैं, लेकिन अंतत: वे भी जातीय राजनीति में फंसते नज़र आ रहे हैं. चुनावी माहौल में चौथी दुनिया की यह कोशिश है कि अपने हिंदी पट्टी के पाठकों को गैर हिंदी भाषी राज्यों के राजनीतिक माहौल से अवगत कराए. इस कड़ी के चौथे अंक में आइए समझते हैं दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का राजनीतिक परिदृश्य...

नीरज सिंह

देश की राजनीति पर जातिगत राजनीति सबसे बड़ा धब्बा है. चुनाव सुधार और सुप्रीम कोर्ट की कोशिशों के अलावा आम राजनीतिक बहसों पर भी गौर करें तो जातिगत राजनीति को देश के लिए सबसे मुश्किल कड़ी बताया जाता है. विडंबना देखिए कि पिछले तकरीबन 60 वर्षों से अपने मुल्क की पूरी राजनीतिक तस्वीर ही कमोबेश इसी आधार पर खड़ी है. उत्तर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में यह विचार आम है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की पूरी राजनीति ही जाति के आधार पर लड़ी जाती है. हालांकि, मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस व्यवस्था को तोड़ा और वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने. सिद्धारमैया राज्य के तीसरे राजनीतिक समुदाय कुरुबा से आते हैं. जातीय बंधनों से बंधी इस राजनीति को समझने के लिए पहले वहां की जातीय व्यवस्था को समझना आवश्यक है.

जाति के आधार पर कर्नाटक का सबसे प्रभावशाली वर्ग है लिंगायतों का. गौरतलब है कि जो लिंगायत आज जाति में तब्दील हो गई है, वह किसी ज़माने में एक पंथ था. लिंगायत आंदोलन कर्नाटक में जाति–व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन था. जाति–व्यवस्था को मिटाने के लिए दार्शनिक बसवन्ना ने 12वीं सदी में एक पंथ का निर्माण किया, जिसमें सभी जातियों के लोगों को शामिल किया गया. इस आंदोलन में शामिल होने की शर्त थी कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, अपनी जाति को छोड़ देंगे. इस तरह जो जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे थे वे लिंगायत समुदाय में शामिल हो रहे थे, लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था जाति के बंधनों में इस तरह बंधी है कि कर्नाटक में जाति–व्यवस्था को तोड़ने के लिए चला एक आंदोलन ख़ुद एक जाति में तब्दील हो गया. चूंकि उस लिंगायत आंदोलन में कर्नाटक का एक बड़ा समाज शामिल हुआ था, इसलिए जब वह आंदोलन जाति में तब्दील हुआ तो लिंगायत ही कर्नाटक की सबसे बड़ी संख्या वाली जाति हो गई. इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह देश के किसी एक राज्य या एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समूचे देश में चल रहा है. ऐसा भी नहीं है कि जाति केवल हिंदू समुदाय तक सीमित है, बल्कि भारत में जितने भी धर्म, मजहब या संप्रदाय हैं, सभी में जाति–व्यवस्था व्याप्त है. हमारे देश में पिछले कई सौ सालों से लोग अपना मजहब बदल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जाति नहीं बदलती. भक्तिकाल के हमारे संतों ने जाति–व्यवस्था के ख़िलाफ़ भी आंदोलन खड़ा किया था. जाति व्यवस्था भी भक्ति आंदोलन के भीतर खड़ी थी. भक्ति तो एक आंदोलन के तौर पर स्थापित हो गई, लेकिन जाति को मिटाने के मामले में यह विफल ही रहा.

उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की परिणति के तौर पर कई पंथ निकले, लेकिन उन पंथों ने जाति को समाप्त नहीं किया. सिख पंथ भी भक्ति आंदोलन की ही उपज है. गुरुनानक साहिब ने जब इस सिख पंथ की शुरुआत की थी, तो उसके पीछे जातिगत भेदभाव को दूर करना उनका एक बहुत बड़ा मक़सद था. उन्होंने जाति को कमज़ोर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज ख़ुद सिख समुदाय में अनेक जातियां हैं. जैन धर्म को मानने वाले लोग भी जातियों में बंटे हुए हैं.

बहरहाल, यह पूर्वपीठिका बताना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति इसी जातीय व्यवस्था से तय होती है. यही वजह है कि कर्नाटक में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय न होकर क्षेत्रीय हो जाती है, क्योंकि उनको इन्हीं जातीय मुद्दों के बीच अपने राजनीतिक दांवपेच चलने होते हैं. देश की दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का यहां पर क्षेत्रीयकरण हो चुका है. दोनों पार्टियां स्थानीय जातीय समीकरणों के जाल में अजीब तरह से उलझी हुई हैं. इन पार्टियों के संगठनों में बहुसंख्यक समुदायों की पकड़ मजबूत बनाने की जंग तेज हो चली है. इस जंग में यह पार्टियां खेमों में बंटी हुई दिखने लगी हैं. वास्तव में यही कर्नाटक की राजनीति का असली ट्रेंड है. यहां दो बहुसंख्यक ब्राह्मण समुदाय लिंगायत और वोक्कालिगा का हमेशा सामना होता रहा है. राज्य की साढ़े छह करोड़ की आबादी में से 17 प्रतिशत लिंगायत और 16 प्रतिशत वोक्कालिगा हैं. इनके बीच का राजनीतिक बंटवारा क्या है, पहले इसे समझते हैं. लिंगायत कर्नाटक का सबसे बड़ा जातीय समूह है. इनका प्रभाव मुख्यत: उत्तर कर्नाटक में ज्यादा है. लिंगायत शैव संप्रदाय को मानने वाले हैं. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इसी समुदाय के हैं. 2008 में जब भाजपा पहली बार दक्षिण भारत के किसी राज्य यानी कर्नाटक में सत्ता में आई तो उन्होंने हिंदुत्व के आधार पर इस जातीय समुदाय में सेंध लगाई. हालांकि अब यहां मामला थोड़ा–सा उल्टा हो गया है, क्योंकि येदियुरप्पा ने बीजेपी छोड़कर कर्नाटक जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी बना ली. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे कयास पर गौर करें तो येदियुरप्पा एक बार फिर भाजपा के दामन थामने वाले हैं.

लिंगायत के बाद कर्नाटक दूसरा बड़ा जातीय समूह है वोक्कालिगा. वोक्कालिगा दक्षिणी कर्नाटक का सबसे बड़ा समुदाय है और इनकी पहचान बड़े जमींदारों के तौर पर है. क्षेत्रीय पार्टी जनता दल सेक्युलर पर इनकी पकड़ मजबूत है. पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा वोक्कालिगा समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं. वोक्कालिगा समुदाय राजनीतिक रूप से कांग्रेस और जनता दल सेक्लुयर के बीच बंटा हुआ है. हालांकि, बीजेपी अपनी इस छवि को तोड़ते हुए कि वह केवल लिंगायत समुदाय पर निर्भर है, वोक्कालिगा समुदाय में भी सेंध लगा रही है. तीसरा जातीय समुदाय है कुरुबा. कर्नाटक में स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इन्हें चरवाहा माना जाता है. ये पूरे कर्नाटक में फैले हुए हैं. हालांकि, राजनीतिक तौर पर इन्हें बहुत ताकतवार तो कभी नहीं माना गया है, लेकिन चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसी समुदाय से हैं, इसलिए मौजूदा समय में इनकी ताकत बढ़ी है. सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकबारगी यह दिखने लगा है कि शायद कर्नाटक जातिगत राजनीति के दौर से निकलकर नई अवधारणाएं गढ़ेगा. इस चुनावों में लिंगायत जाति के पचास विधायक जीतकर आए हैं, जिनमें से 29 कांग्रेस के हैं. बीजेपी में केवल दस विधायक लिंगायत समुदाय से हैं. बीएस येदियुरप्पा की पार्टी के केवल 6 विधायक चुने गए हैं. वोक्कालिगा जाति के 53 विधायक हैं, जिनमें से बीस कांग्रेस के पास हैं. अपने आपको वोक्कालिगा नेता बताने वाले देवगौड़ा की पार्टी में केवल 18 विधायक वोक्कालिगा हैं. अनुसूचित जाति के 35 विधायकों में से 17 कांग्रेस में हैं. अनुसूचित जनजाति के 19 विधायकों में से 11 कांग्रेस में हैं. ओबीसी विधायकों की संख्या 36 है, जिनमें से 27 कांग्रेस में हैं, 11 मुसलमान जीतकर आए हैं, जिनमें से 9 कांग्रेस में हैं. ईसाई, जैन और वैश्य समुदाय के सभी विधायक कांग्रेस के साथ हैं. इस तरह से किसी ख़ास जाति का नेता बनने की राजनीति करने वालों को कर्नाटक की जनता ने कोई महत्व नहीं दिया है. इसकी पहल करते हुए सिद्धारमैया ने जाति को प्राथमिकता देने की मुख्यमंत्रियों की रिवायत से साफ़ मना कर दिया है. उन्होंने अपनी जाति के किसी भी आदमी को अपने निजी स्टाफ में जगह नहीं देने की घोषणा कर दी है. अपने मंत्रियों को भी उन्होंने सलाह दी है की जाति के शिकंजे से बाहर आने की कोशिश करें, लेकिन यह सिक्के का एक पहलू है. दूसरे पहलू पर गौर कीजिए तो राजनीतिक प्रबंधन के स्तर पर आकर सिद्धारमैया भी जातियों दायरे में ही फंस जाते हैं. उन्होंने अहिन्दा की राजनीति को अपनी जीत की धुरी बनाया है. अ यानी अल्पसंख्यक, हिन्दुलिगा यानी ओबीसी और दा यानी दलित. इन तीनों वर्गों के नेता के रूप में अगर उनको मान्यता मिल गई तो कर्नाटक में जीत के लिए लिंगायत या वोक्कालिगा होने की जो परंपरा है, वह ख़त्म हो जाएगी.

बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बीच में विकास और दूसरे सामाजिक मुद्दे कहां हैं? कर्नाटक की जितनी पहचान आईटी इंडस्ट्री को लेकर है, उससे कहीं ज्यादा राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हो रही है. हालांकि, वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के दो बार उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. उस दौरान उन्होंने जो वित्तीय सुधार अपनाए, उनके लिए उनको काफी सराहना भी मिली. उन्होंने 2010 में बेल्लारी में खनन माफिया और भाजपा के पूर्व मंत्रियों रेड्डी बंधुओं की चुनौती के बावजूद कांग्रेस की ओर से सफल पदयात्रा आयोजित की. यही नहीं, आज तक उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, लेकिन कर्नाटक में राजनीतिक स्तर पर जो सबसे बड़ी मुश्किल है, वह है एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था. यह कमी राज्य लंबे अर्से से महसूस कर रहा है. इससे जुड़ी जो दूसरी बड़ी मुश्किल है, वह है खनन माफियाओं का सरकार पर हावी होना. इसके दोहरे संकट हैं. पहला तो खनन माफिया सरकार की चाबी के तौर पर होते हैं, इसलिए समूचे देश में खनन माफियाओं और उनके सिस्टम को राज्य सरकारों से ही ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता इनसे त्रस्त है. इसलिए ऐसे में किसी भी सरकार के लिए इस व्यवस्था से निपट पाना मुश्किल होता है.

राज्य में बिजली की भारी किल्लत है, जिसका असर खेती समेत अन्य उत्पादक कार्यों पर पड़ रहा है. राज्य में कृषि विकास दर बेहद कमजोर है. इसकी एक बड़ी वजह बिजली और पानी की किल्लत है. जहां पानी था, वहां लोग बिजली की कमी के चलते बोरवेल नहीं चला सके. हालांकि, भाजपा शासनकाल में राज्य में अनेक ताप बिजली घर स्थापित किए गए थे, जिनका परिचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है. इसके पीछे भी एक राजनीतिक चुनौती है. अगर मौजूदा कांग्रेस सरकार इन बिजली घरों को शुरू कराती है तो विपक्षी दल इसका श्रेय लेने को तैयार बैठा है और अगर नहीं शुरू कराती तो विपक्षी दल इस बात की राजनीति करेंगे कि जिन विकास योजनाओं को राज्य को हमने सौंपा, सरकार उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रही है.

बहरहाल, किसी दौर में रामकृष्ण हेगड़े जैसे नेताओं के साथ पंचायती राज का कर्नाटक मॉडल स्थापित करने वाला यह राज्य इस समय राजनीतिक अव्यस्था से जूझ रहा है, सही है, लेकिन देश की राजनीति में इस राज्य की महत्ता और इसकी चर्चा हमेशा ही लोकप्रिय रही है. ■

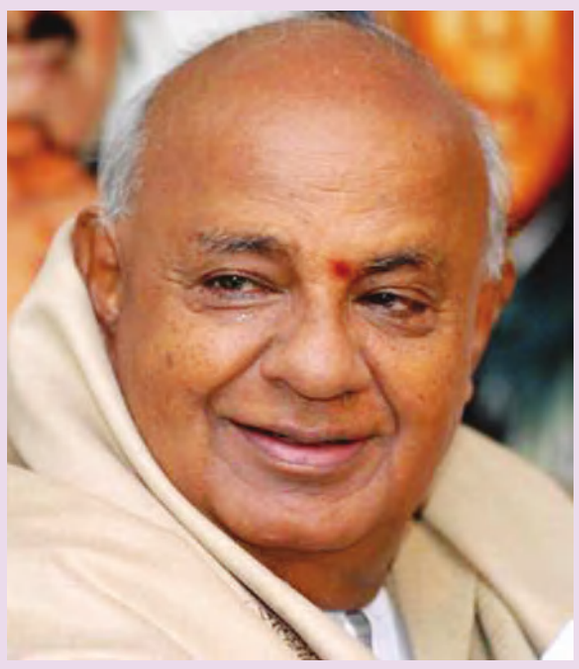

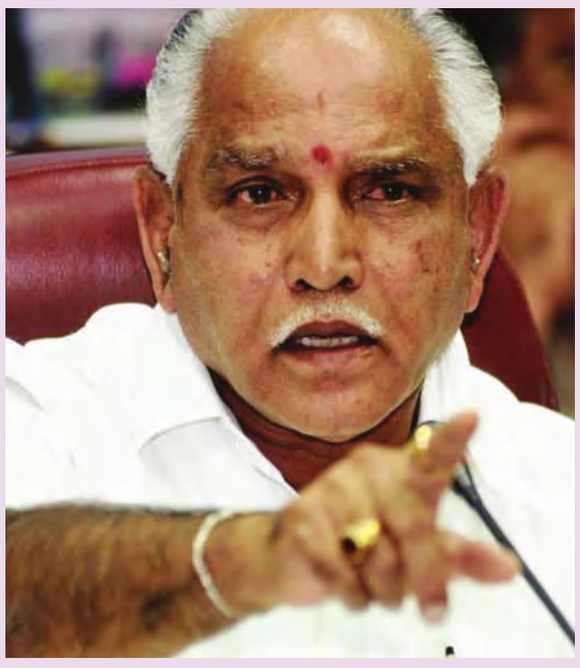

जाति के आधार पर कर्नाटक का सबसे प्रभावशाली वर्ग है लिंगायतों का, लेकिन गौरतलब यह है कि जो लिंगायत आज जाति में तब्दील हो गई है, वह किसी जमाने में एक पंथ था. लिंगायत कर्नाटक में जाति-व्यवस्था के ख़िलाफ़ शुरू हुआ आंदोलन था. जाति-व्यवस्था को मिटाने के लिए दार्शनिक बसवन्ना ने 12वीं सदी में एक पंथ का निर्माण किया, जिसमें सभी जातियों के लोगों को शामिल किया गया.

feedback@chauthiduniya.com

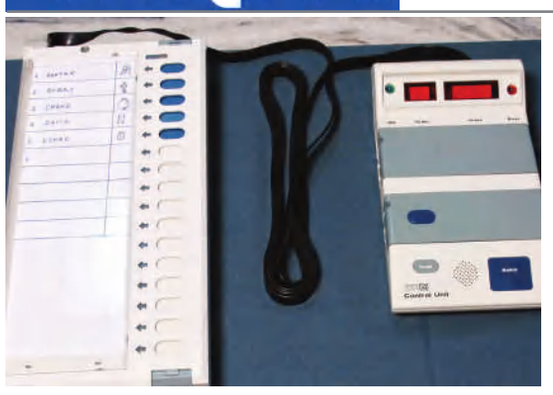

चुनाव पूर्व सर्वे दरअसल, चुनाव के पूर्व लगाया जाने वाला एक अनुमान है कि आगामी चुनाव में जनता किस राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करने जा रही है. ज़ाहिर है कि यह किसी क्षेत्र में पूरे मतदाताओं का मत नहीं होता. यह कुछ मतदाता संख्या में से कुछ लोगों का मत होता है. यह ज़रूरी नहीं है कि आप जिन लोगों के मत प्राप्त कर रहे हों, वे पूरी संख्या की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हों.

चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों का गणित

चुनावों की आहट होते ही राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों के नतीजे अलग-अलग हैं, इसलिए ये भ्रामक भी हैं. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि आख़िर ये चुनाव पूर्व सर्वेक्षण होते कैसे हैं? सर्वे एजेंसियां कौन सी प्रक्रिया अपनाकर किसी पार्टी की जीत-हार की घोषणा करती हैं? जो सर्वेक्षण हमारे सामने पेश किए जाते हैं, क्या वे वास्तविक साबित होते हैं? सर्वेक्षणों की प्रणाली, प्रक्रिया, उनके नतीजे और उनकी विश्वसनीयता पर एक रिपोर्ट.

कृष्णकांत

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम मीडिया संस्थानों की ओर से चुनाव पूर्व सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं, जिसमें किसी राजनीतिक दल को बढ़त मिलती दिखाई जा रही है तो किसी का जनाधार खिसकने का दावा किया जा रहा है. आगामी विधानसभा चुनावों में पांच राज्यों की तस्वीर क्या होगी, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. चुनाव-पूर्व सर्वेक्षणों के आधार पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि कहां कौन सत्ता पर काबिज होगा, तो किसके हाथ से सत्ता जाएगी. चूंकि चुनाव से पहले ऐसे अनुमान चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों यानी प्री-पोल सर्वे पर आधारित होते हैं, इसलिए आम जनता में यह सहज जिज्ञासा उठ सकती है कि आखिर ये चुनावी सर्वे होते किस आधार पर हैं? इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में कोई संस्थान यह कैसे जान लेता है कि अमुक पार्टी को जीत मिलने जा रही है और अमुक पार्टी हारने जा रही है. हालांकि, इन सर्वेक्षणों को न तो राजनीतिक पार्टियां सच मानती हैं, न ही जनता इन पर बहुत भरोसा करती है. ऐसे सर्वे कराने वाली एजेंसियां भी सिर्फ संभावना ही जताती हैं कि चुनावी तस्वीर करीब-करीब ऐसी हो सकती है. आइए जानते हैं कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में क्या तरीके अपनाए जाते हैं.

सर्वे कराने का पहला चरण है कि जिस राज्य में सर्वे कराना है, उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का चुनाव किया जाता है. यदि राज्य में सर्वे कराना है, तो राज्य के विधानसभा क्षेत्र और यदि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे कराना है तो हर राज्य से कुछ क्षेत्रों को सर्वे के लिए चुना जाता है. इसके बाद सैंपल यानी नमूना जुटाने वाली इकाइयां लोगों के बीच जाकर नमूने जुटाती हैं. विधानसभा क्षेत्रों में नमूने प्रोबाबिलिटी प्रपोर्शन टू साइज यानी संभाव्यता प्रणाली से जुटाए जाते हैं. पिछले चुनावों के परिणामों को जनसांख्यिकी से मिलाया जाता है. जनसांख्यिकी संबंधी आंकड़े वही लिए जाते हैं, जो चुनाव आयोग मुहैया कराता है. इसे पूर्व के सभी चुनावों की गणना और उसकी प्रवृत्तियों से मिलाकर अध्ययन किया जाता है. ऐसी परिकल्पना की जाती है कि जिस भी क्षेत्र से नमूने लिए गए हैं, वह पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है.

दूसरे चरण में क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ से सैंपल लिए जाते हैं. पोलिंग बूथों से दोबारा संभाव्यता प्रणाली के आधार पर नमूने लिए जाते हैं. यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि उस इलाके से बड़ी संख्या में नमूने लिए गए हैं और यह इस परिकल्पना को स्थापित करता है कि उस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या उस क्षेत्र की विविधता का प्रतिनिधित्व करेगी. इसके बाद अंतिम चरण में कुछ ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया ली जाती है, जिनके नाम चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में शामिल हैं. इन मतदाताओं को प्रतिक्रिया के लिए रैंडम सैंपलिंग यानी यादृच्छिक नमूना प्रणाली के जरिये चुना जाता है. दो प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया लेने के बीच एक निश्चित अंतराल रखा जाता है. प्रत्येक पोलिंग बूथ से जिन लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गई हैं, उन मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है. इसमें उनके बारे में विस्तृत जानकारी होती है, मसलन-उनके नाम, पता, उम्र और लिंग आदि. सूची में दर्ज इन मतदाताओं से बातचीत करने को विधिवत ट्रेनिंग देकर एक खोजी टीम तैयार की जाती है. इन टीमों के सदस्य सूचीबद्ध मतदाताओं से आमने-सामने सवाल-जवाब करते हैं. यह ध्यान रखा जाता है कि सर्वे प्रणाली में कोई भी प्रक्रिया अपवाद स्वरूप नहीं अपनाई जाती. पूरी सर्वे प्रणाली में अपवाद तभी अपनाया जाता है, जब किसी विशेष समूह को लक्ष्य किया जाए. ज्यादातर सर्वे में मतदाताओं से आमने-सामने बातचीत की जाती है या फिर प्रश्नोत्तर सूची भरवाई जाती है. इसके अलावा सर्वे की भाषा स्थानीय ही रखी जाती है, ताकि मतदाओं से बातचीत में संचार बाधित न हो. सीएसडीएस संस्था की ओर से 2004 राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन किया गया, वह सभी मान्य 22 भाषाओं में किया गया था. मतदाताओं से सारे आंकड़े जुटाने के बाद उसका अध्ययन किया जाता है और संभावित जनादेश के आकलन किए जाते हैं.

चुनाव पूर्व सर्वे दरअसल चुनाव के पूर्व लगाया जाने वाला एक अनुमान है कि आगामी चुनाव में जनता किस राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करने जा रही है. जाहिर है कि यह किसी क्षेत्र में पूरे मतदाताओं का मत नहीं होता. यह कुछ मतदाता संख्या में से कुछ लोगों का मत होता है. यह जरूरी नहीं है कि आप जिन लोगों के मत प्राप्त कर रहे हों, वे पूरी संख्या की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हों. जिन मतदाताओं से बातचीत की गई, वे इत्तेफाकन किसी एक समूह से संबंधित हो सकते हैं या किसी कारणवश सर्वे के लिए अपनी राय देने के बाद उनके पक्ष बदल भी सकते हैं. ऐसी स्थिति आने पर सारे पूर्वानुमान धराशायी हो जाते हैं. इसका एक हालिया उदाहरण रहा है 2004 का लोकसभा चुनाव, जब सभी चुनाव पूर्व सर्वे एनडीए के दोबारा सत्ता में आने की संभावना जता रहे थे, लेकिन जब चुनाव के बाद नतीजे आए तो सारे अनुमानों की धज्जियां उड़ गईं और कांग्रेस की अगुआई वाला यूपीए गठबंधन सत्ता में आया. 2009 के लोकसभा चुनाव में कई घोटालों, भ्रष्टाचार और महंगाई के बाद भी यूपीए गठबंधन फिर से सत्ता में आया.

इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि चुनाव पूर्व किए जाने वाले सर्वे हमेशा सही साबित हों, ऐसा जरूरी नहीं है. ज्यादातर बार सर्वेक्षणों को धता बताते हुए जनता इस तरह से जनादेश देती है, कि सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां और राजनीतिक दल सभी हैरान रह जाते हैं. इसका कारण यह है कि हमारा देश विविधिताओं का देश है. समाज में जाति, धर्म और वर्ग संरचना के आधार पर तमाम परतें हैं, तमाम सामाजिक-राजनीतिक समूह हैं, जिनके एक-दूसरे से एकदम अलहदा हित हैं. वे उन हितों के आधार पर अपना मत व्यक्त करते हैं. देश की मौजूदा सामाजिक संरचना के हिसाब से सर्वे के लिए कोई मुफीद प्रणाली ही तैयार नहीं हो पाती कि हम सर्वेक्षणों के माध्यम जनता का राजनीतिक रुख समझ सकें.

> **भारतीय मतदाताओं में एक आम प्रवृत्ति देखी जाती है कि यहां वोटर प्राय: वोट देने में ओपिनियन लीडर यानी बिचौलियों की मदद लेता है. इसलिए चुनाव के काफी वक्त पहले ही यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि वह किस पार्टी को वोट देगा. चुनाव आयोग का कहना है कि दिल्ली में एक करोड़ दस लाख से ज़्यादा मतदाता इस बार मतदान करेंगे. सर्वे करने वाली कंपनियों और संस्थाओं का दावा है कि वे 70 विधानसभा में से 35-40 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पांच हज़ार से लेकर 16 हज़ार तक मतदाताओं की राय लेकर इस आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं.**

एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह राजनीतिक पार्टियों की विश्वसनीयता मतदाताओं के निगाह में संदिग्ध है, वैसे ही वे सर्वेक्षण करने वालों की भी विश्वसनीयता को लेकर आम मतदाता दिलचस्पी नहीं दिखाते. इन सर्वेक्षणों को प्रसारित करने वाले मीडिया समूह भी इतने फिक्रमंद नहीं हैं कि वे पूरे देश हर मतदाता समूह का बहुसंख्या का मत प्राप्त करें और फिर उस आधार पर चुनावी अनुमान पेश करें. वैसे भी, देखा जाए तो चुनावी सर्वे मीडिया के लिए एक व्यावसायिक कर्म है, जो उनके पाठक या दर्शक वर्ग के लिए कंटेंट मुहैया कराता है. मीडिया समूहों की चिंता इस बात को लेकर नहीं होती कि वे सही पूर्वानुमान पेश करें, बल्कि वे अपने लिए मात्र स्टोरी क्रिएट करते हैं. हालांकि, सर्वेक्षणों को ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने का खूब बढ़-चढ़ कर दावा किया जाता है. दूसरे सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां ज्यादातर अपनी अध्ययन पद्धति को जाहिर नहीं करतीं, न ही कोई उसकी जांच करने की कोशिश ही करता है.

पिछले महीनों के दौरान कई सारे सर्वेक्षण सामने आए, जो भारतीय जनता पार्टी को आगामी चार राज्यों के चुनाव में बढ़त दिखा रहे हैं और कांग्रेस के हारने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं. इन सर्वेक्षणों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में कमोबेश स्पष्ट संभावनाएं जताई गई हैं, लेकिन दिल्ली में चूंकि कांग्रेस, भाजपा और आप पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होना है, इसलिए यहां के चुनाव पूर्व सर्वे भी भ्रामक तस्वीर पेश करते हैं. चूंकि अब आप पार्टी एक बड़े राजनीतिक समूह के रूप में उभरी है. उसने दिल्ली भर में मोहल्ले-मोहल्ले अपना कैडर तैयार किया है. कांग्रेस यहां 15 साल से है. भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है और निकायों में बहुमत में है, लेकिन आप के अचानक उभार ने चुनाव को प्रभावित करने की उसकी सामर्थ्य के चलते पूर्वानुमानों को भ्रामक बना दिया है.

यह गौर करने की बात है कि हाल में चार राज्यों के चुनावों को लेकर जितने तरह के सर्वे आए हैं, वे सभी अलग-अलग तरह के नतीजों की संभावना व्यक्त कर रहे हैं. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों का परिणाम क्या होगा, यह तो बाद की बात है, लेकिन इन अनुमानों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है कि आखिर एक राज्य में चुनाव का नतीजा तो कुछ एक ही होगा. फिर तीन तरह के सर्वेक्षणों में किसे विश्वसनीय और सटीक माना जाए?

मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली चुनाव को लें, तो हाल ही में दिल्ली को लेकर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जारी किए गए. विभिन्न मीडिया समूहों की ओर से तीन सर्वे जारी हुए, जो तीनों ही अलग-अलग तीनों के विपरीत भविष्यवाणी कर रहे हैं. दूसरी ओर आप पार्टी ने योगेंद्र यादव के नेतृत्व में सर्वे कराया, जिसने उसे दिल्ली में बहुमत मिलते हुए दिखाया है. यह ध्यान देने की बात है कि यदि कोई मीडिया समूह का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक है तो अपने सर्वे में उसी पार्टी को बहुमत मिलता दिखा रहा है. इससे साफ है कि चुनाव पूर्व सर्वे भी पूरी तरह पारदर्शी नहीं हैं. आप पार्टी ने इतना किया है कि उसने काफी पारदर्शिता बरती है और अपने सर्वे का कच्चा डाटा भी अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है. आप पार्टी का दावा है कि विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनने जा रही है.

भारतीय मतदाताओं में एक आम प्रवृत्ति देखी जाती है कि यहां वोटर प्राय: वोट देने में ओपिनियन लीडर यानी बिचौलियों की मदद लेता है. इसलिए चुनाव के काफी वक्त पहले ही यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि वह किस पार्टी को वोट देगा. चुनाव आयोग का कहना है कि दिल्ली में एक करोड़ दस लाख से ज्यादा मतदाता इस बार मतदान करेंगे. सर्वे करने वाली कंपनियों और संस्थाओं का दावा है कि वे 70 विधानसभा में से 35-40 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पांच हजार से लेकर 16 हजार तक मतदाताओं की राय लेते हैं और इस आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. हालांकि, किन-किन से सर्वे किया गया, उन्होंने किन-किन सवालों के किस प्रकार के जवाब दिए, इसका खुलासा कभी नहीं किया जाता है. दिल्ली से अलग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गांव में रह रहे मतदाताओं के बारे में ये एजेंसियां किस प्रक्रिया से गुजर कर सर्वे पूरे करती होंगी, ये वही जानती हैं. हम-आप इतना कह सकते हैं कि एक राज्य के करोड़ो लोंगों के रुझान के बारे में कुछ लोगों की राय के आधार पर भविष्यवाणी करना एकदम बेमानी है. यही कारण है कि विभिन्न सर्वेक्षणों पर सवाल उठ रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है

सीबीआई सरकार का ही एक अंग है और ऐसा अंग जो कि अक्षम और भ्रष्ट है. हक़ीक़त तो यह है कि व्यापारिक घरानों को कठघरे में खड़ा करके या तो सीबीआई के अधिकारी पैसा बना रहे हैं या तो बड़े राजनीतिक खिलाड़ी पैसा बना रहे हैं. कोल ब्लॉक आबंटन प्रकरण से देश की छवि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में दांव पर लगी हुई है और इससे निजात पाने का जो सबसे बेहतर तरीक़ा है, वह यह कि पूर्व में किए गए सभी आबंटन को रद्द कर दिया जाए. यदि सरकार यह नहीं कर सकती, तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करना चाहिए.

कोलगेट प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है. इस संदर्भ में एक नई एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें देश के एक बड़े औद्योगिक घराने और उसके चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला का भी नाम शामिल है. पूर्व कोयला सचिव पी. सी. पारेख, जिनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर है, उनका नाम भी इस एफआईआर में शामिल है. पी सी पारेख ने तर्कसंगत ढंग से अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चूंकि उस समय कोयला मंत्रालय की ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास थी, इसलिए उनका नाम भी इसमें शामिल करना चाहिए. यह दुर्भाग्य है कि ऐसी घटनाओं का यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा. देश के हित के लिए यह ज़रूरी है कि इस सिलसिले को सही ढंग से ख़त्म किया जाए और उसका सबसे बेहतर तरीक़ा यही होगा कि तत्कालीन व्यवस्था के तहत किए गए सभी कोल ब्लॉक आबंटन को निरस्त किया जाए. एक नई प्रक्रिया के तहत फिर से निविदाएं आमंत्रित की जाएं या बोली लगाई जाए या दूसरा जो भी सही तरीक़ा हो, उसके माध्यम में नए सिरे से आबंटन किए जाएं. इस प्रकरण से देश को जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, उससे बचने का एक मात्र यही तरीक़ा है. एफआईआर दर्ज करना और सीबीआई को बिना स्वायत्त बनाए उसे इस मामले की जांच अथॉरिटी बनाना, इन सबका कोई मतलब नहीं है.

सभी जानते हैं कि सीबीआई सरकार का ही एक अंग है और ऐसा अंग जो कि अक्षम और भ्रष्ट है. हक़ीक़त तो यह है कि व्यापारिक घरानों को कठघरे में खड़ा करके या तो सीबीआई के अधिकारी पैसा बना रहे हैं या तो बड़े राजनीतिक खिलाड़ी पैसा बना रहे हैं. कोल ब्लॉक आबंटन प्रकरण से देश की छवि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में दांव पर लगी हुई है और इससे निजात पाने का जो सबसे बेहतर तरीक़ा है, वह यह कि पूर्व में किए गए सभी आबंटन को रद्द कर दिया जाए. यदि सरकार यह नहीं कर सकती, तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करना चाहिए. रोज़ एक नई एफआईआर दर्ज कराना वास्तव में बस अख़बारों के लिए सनसनीखेज व अभद्र ख़बरों का माध्यम भर बन जाता है और यह किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है. ऐसा करके हम केवल उन अख़बारों की प्रसार संख्या बढ़ा रहे हैं, जिनके ऊपर यह संदेह किया जाता है कि वे औद्योगिक घरानों से संबद्ध हैं. ऐसा करके देश को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला.

मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री इस मसले पर क्या सोचते हैं. हालांकि, कोल ब्लॉक के आबंटन में जिन्होंने पैसा लगाया है, ज़ाहिर तौर पर उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन हम यहां पर समूचे देश के हित में बात कर रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर. सुप्रीम कोर्ट को चाहिए किसी जांच के आदेश या सीबीआई को कार्यवाही करने का आदेश देने के बजाए वह सभी आबंटन रद्द कर दे और फिर से नई प्रक्रिया के तहत बोली लगाई जाए. इस तरह जिस किसी भी औद्योगिक घरानों ने नौकरशाहों या राजनेताओं को पैसा देकर कोल ब्लॉक हासिल किया था, उनके पैसे डूब जाएंगे और वास्तव में वे इसी के हक़दार हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है, वह असंगत तरीक़े से किया गया था. इस समस्या के हल का नैतिक, वैधानिक या जो कोई भी माना जाए, यही एक तरीक़ा है.

दूसरा, जैसा कि मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में सोने की तलाश में खुदाई हुई. एक साधु ने सपना देखा कि वहां पर सोना गड़ा हुआ है, जिसके चलते यह खुदाई हुई. मुझे नहीं पता इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने कितना पैसा ख़र्च किया होगा. साथ ही यह भी आश्चर्य की बात है कि 21वीं सदी के इस दौर में केवल किसी के सपना देखने पर कि कहीं पर ज़मीन में सोना गड़ा है, उस पर विश्वास कर लिया जाता है और सरकार उसे सही मानते हुए उस पर कार्रवाई करने लगती है.

चुनाव नजदीक आ रहे हैं और देश में जो माहौल बन रहा है, उसे वास्तव में बेहतर नहीं कहा जा सकता. अर्थव्यवस्था संकट में है. राजनीतिक स्थितियां बिगड़ रही हैं. अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह कोशिश करे कि अब भ्रष्टाचार का कोई नया प्रकरण सामने न आए. सरकार जो भी कर रही है, वास्तव में उसे सही ढंग से करने की ज़रूरत है.

मुझे यक़ीन है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक योग्य व्यक्ति हैं और चीज़ों को सुचारु ढंग से चलाने के लिए उन्हें और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. राजनीतिक ताक़तें, जो एक दिन यह तय करती हैं कि अध्यादेश लाया जाए और उनके अपने ही लोग सार्वजनिक रूप से अध्यादेश का मज़ाक उड़ाकर यह समझते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार का मज़ाक उड़ाया है, वास्तव में अपनी पार्टी का ही मज़ाक उड़ा रहे हैं. पार्टी की कोर कमेटी सही ढंग से काम नहीं कर रही है. पार्टी अध्यक्ष एक बात कहती हैं तो पार्टी उपाध्यक्ष दूसरी बात कहते हैं. अगर उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दोषपूर्ण है, यह क़ानून के मुताबिक नहीं है, तो पार्टी को इस पर बैठकर विचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश भी यह कह चुके हैं कि निर्णय क़ानून के आधार पर विधिसंगत नहीं हैं.

हां, जनता का मत है कि दोषी राजनेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो. संसद को चाहिए कि वह पहल करे न कि कोर्ट. संसद का काम देश की सुप्रीम कोर्ट कर रही है और यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अनुशासनहीनता एक राष्ट्रीय समस्या है

ठाकुर दास बंग

देश की स्थिति की इस समीक्षा के संबंध में कुछ रुचिकर प्रश्न पूछे गए हैं, जिन्हें समझने की ज़रूरत है. हम उन पर संक्षिप्त में विचार कर रहे हैं:

प्रश्न: चारों तरफ इतनी अनुशासनहीनता है कि देश सचमुच जहन्नुम में जाता दिखाई पड़ता है. औद्योगिक श्रमिक, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, तथा अन्य सभी बड़ी ग़ैरज़िम्मेदारी का व्यवहार कर रहे हैं. क्या यह ज़रूरी नहीं है कि अधिकारों की बात करने के पहले लोगों में उनके कर्तव्यों का भान पैदा किया जाए? क्या इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए कड़े क़ानूनों और मजबूत सरकार की ज़रूरत नहीं है?

उत्तर: अनुशासनहीनता और ग़ैरज़िम्मेदारी एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है, लेकिन हम इन चीज़ों को कड़े क़ानूनों से नियंत्रित नहीं कर सकते. सारे सामाजिक वातावरण में ही एक परिवर्तन की ज़रूरत है. इसके लिए अन्य चीज़ों के साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि शक्ति और सार्वजनिक महत्व की जगहों से ऐसे लोगों को नीचे उतार दिया जाए, जिन्होंने प्रारम्भिक नैतिकता के भी सारे सिद्धांतों को त्याग कर झूठ, भ्रष्टाचार, धोखे और हिंसा को जीवन-नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है.

आश्चर्य की बात है कि ऊपरी तबके के लोगों द्वारा सक्रिय रूप से समाज विरोधी भावना बढ़ाने पर भी इसका कोई बहुत बड़ा रूप दृष्टिगत नहीं होता. उदाहरण के लिए आपातकाल के दौरान भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से यह विनिर्णय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी कि चूंकि मौलिक अधिकार निरस्त हो गए थे. इसलिए नागरिकों का जीने का अधिकार समाप्त हो गया था और यदि कोई सरकारी अधिकारी एकदम ग़ैरक़ानूनी व अनैतिक रूप से भी किसी को मरवा देता तो भी कोई समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता था. फिर भी आश्चर्य यह है कि

आश्चर्य की बात है कि ऊपरी तबके के लोगों द्वारा सक्रिय रूप से समाज विरोधी भावना बढ़ाने पर भी इसका कोई बहुत बड़ा रूप दृष्टिगत नहीं होता. उदाहरण के लिए आपातकाल के दौरान भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से यह विनिर्णय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी कि चूंकि मौलिक अधिकार निरस्त हो गए थे. इसलिए नागरिकों का जीने का अधिकार समाप्त हो गया था और यदि कोई सरकारी अधिकारी एकदम ग़ैरक़ानूनी व अनैतिक रूप से भी किसी को मरवा देता तो भी कोई समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता था.

सरकारी अधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत दुश्मनों से निबटने के लिए इस पूर्णाधिकार-पत्र का कोई बड़े तौर पर इस्तेमाल नहीं किया. उनकी सुबुद्धि प्रबल रही.

मामलों को उलझाने के लिए अक्सर अधिकारों और कर्तव्यों का आह्वान किया जाता है. इसे बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेने की ज़रूरत है कि एक कठोर अपराधी के भी, जो समाज के प्रति अपना कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं करता, कुछ अधिकार हैं, जो उससे छीने नहीं जा सकते. उसके चलने-फिरने पर बंधन लगाए जा सकते हैं या क़ानून की सही प्रकिया से उसे कैद भी किया जा सकता है, लेकिन उसे अपना बचाव करने का अधिकार मिलेगा.

उसे अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है. कुछ समय पहले बम्बई हाईकोर्ट ने कत्ल के एक मुजरिम का अपना संस्मरण प्रकाशित करने के अधिकार को अनुमोदित किया है. उसे अपनी इच्छा अनुसार कोई धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आदि-आदि. ऐसे आदमी को मौत की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन हत्या, राजद्रोह आदि के किसी विशिष्ट जुर्म पर ही. जिन अभियोंगो पर किसी को मृत्युदण्ड दिया जा सकता है, उनकी संख्या भी अब कम हो गई है और अब सारी दुनिया में मृत्युदण्ड समाप्त करने के लिए आंदोलन चल रहा है, क्योंकि इसका मानवीय अधिकारों और अहिंसा से मेल नहीं बैठता. यूरोप के पचीस देशों ने इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया है.

जब गांधी जी उनकी ही तरह के बड़े लोग अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की बात करते थे, तब उनके दिमाग़ में कर्तव्य सिर्फ़ दफ्तर समय से जाने या अपने वृद्ध मां-बाप की सेवा तक ही सीमित नहीं थे. उनके दिमाग़ में अन्य आवश्यक कर्तव्य भी थे, जैसे निडर होकर सत्य बोलना और निरकुंश सरकार का विरोध करना. इसलिए कर्तव्यों और अधिकारों में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध है, वह यह है कि यदि लोग किसी निरकुंश सरकार का विरोध करने के अपने कर्तव्य में असफल रहते हैं तो वे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, न कि वे लोग जो समय पर दफ्तर नहीं आते हैं या उन्हें एस्मा (आवश्यक सेवा संरक्षण कानून) के अंतर्गत हवालात में बंद कर दिया जाना चाहिए.

प्रश्न: ग्रेट ब्रिटेन के नमूने पर निर्धारित अपने देश की न्यायपालिका अपने देश की आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुकूल नहीं है. इसे पूरी तौर से बदलने की ज़रूरत है. यह ख़र्चीली है और सिर्फ़ पैसे वाले लोग इससे कई फ़ायदा उठा सकते हैं. इसे आमूल बदलने की ज़रूरत है. यदि मौजूदा सरकार इसमें कुछ फेरफार करती है तो परेशानी की क्या बात है?

उत्तर: ख़र्चीलापन और दिखावटीपन ज़रूर ऐसी विषिष्टताएं हैं, जो बाहर से लाई गई हैं, लेकिन न्यायापालिका की स्वतंत्रता और क़ानून के आगे समानता मूल्यवान आदर्श है, जो ब्रिटेन होकर ही हम तक पहुंचे हैं. प्राचीन भारत में दार्शनिक विचारों की ऊंची-से-ऊंची उड़ानों के बावजूद, जिसमें सभी के लिए बराबर सम्मान निहित था, क़ानून के आगे सभी बराबर नहीं थे. मनुस्मृति तक में अलग-अलग वर्णों के लिए अलग-अलग दण्डविधान हैं. इसलिए विदेशी लगने वाली हर चीज़ अस्वीकार्य नहीं है. यहां भी सत्तारूढ़ पार्टी का विचार सामान्य आदमी के लिए न्याय सुलभ कराने की दिशा में नहीं है, बल्कि अपने इशारों पर जजों को नचाने की ओर है.

ग़रीबों की मदद के लिए क़ानूनी सहायता कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यह वास्तविक राहत न देकर प्रचार के लिए अधिक है. आज मुकदमों में काफी बड़े अनुपात में विरोधी नागरिक व सरकार होते हैं. ऐसे मुकदमों में या जिनमें सत्तारूढ़ दल प्रार्थी के विरुद्ध होगा. कोई क़ानून सहायता प्राप्त नहीं हो पाएगी.

आज ग़रीब अकेले अदालतों तक पहुंच सकने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनकी शिकायतें उनके ट्रेड यूनियन जैसे संगठन और पी. यू. सी. एल (पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज) और पी. यू. डी. आर. जैसे माध्यमों द्वारा भी हाथ में ली जा रही है और वे उनके लिए राहत प्राप्त कर रही हैं, जैसे मुंबई के झोपड़पट्टी निवासियों या दिल्ली के भवन-निर्माण कामगारों के मामलों में. इसलिए यह सोचना ग़लत है कि मौजूदा अदालतें ग़रीबों के लिए किसी काम की नहीं हैं. इसके अतिरिक्त वे संवैधानिक व क़ानूनी उन बिंदुओं के संबंध में निर्णय देती हैं, जो सामान्य आदमी के समझ के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जो उसके अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता और उसके जीवन तक से भी गंभीर रूप से संबंधित होते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

आज ग़रीब अकेले अदालतों तक पहुंच सकने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनकी शिकायतें उनके ट्रेड यूनियन जैसे संगठन और पी. यू. सी. एल (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) और पी. यू. डी. आर. जैसे माध्यमों द्वारा भी हाथ में ली जा रही है और वे उनके लिए राहत प्राप्त कर रही हैं, जैसे मुंबई के झोपड़पट्टी निवासियों या दिल्ली के भवन-निर्माण कामगारों के मामलों में. इसलिए यह सोचना ग़लत है कि मौजूदा अदालतें ग़रीबों के लिए किसी काम की नहीं हैं. इसके अतिरिक्त वे संवैधानिक व क़ानूनी बिंदुओं के संबंध में निर्णय देती हैं, जो सामान्य आदमी के समझ के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जो उसके अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता और उसके जीवन तक से भी गंभीर रूप से संबंधित होते हैं.

पाठकों की दुनिया

प्रधानमंत्री कब तक बचेंगे

चौथी दुनिया में प्रकाशित लेख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं, में कही गईं बातें, अब सच होती नजर आ रही हैं. कोयला घोटाले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए जाने के बाद पूर्व कोयला सचिव प्रकाश चंद्र पारेख ने सवाल किया है कि यदि मैं आरोपी हूं और कोयला घोटाले में कोई साजिश हुई है तो इसमें कई साजिशकर्ता हैं. उस समय कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था. आबंटन पर अंतिम मुहर उन्होंने ही लगाई थी तो प्रधानमंत्री साजिशकर्ता में शामिल क्यों नहीं? जिस प्रकार अब तक इस मामले में जो बातें सामने आई हैं, उससे एक बात जरूर साफ हो गई है कि कोयला खदानों को किस प्रकार से लुटाया गया है. प्रधानमंत्री के पास इस मामले में कुछ बताने को है तो वह खुद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वह इस मामले पर चुप क्यों बैठे हैं? जिस प्रकार सीबीआई की जांच रिपोर्ट को बदलने की कोशिश की गई और कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गुम हुईं, यह सब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए ही साजिश के तहत किया गया. यह सब कोयला मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने किया. कोई सीबीआई पर अभी भी कैसे विश्वास करे कि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम नहीं कर रही है. अब यह देखना होगा की सीबीआई (तोता) खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद.

–राहुल, बलिया

चुनाव एजेंडे पर होना चाहिए

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के नेता महमूद मदनी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के प्रति मुसलमानों में डर पैदा कर कांग्रेस को वोट नहीं मागना चाहिए. उन्होंने सही कहा कि जो पार्टियां अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, उन्हें किसी व्यक्ति विशेष का सत्ता में आने का भय दिखाकर वोट नहीं हासिल करना चाहिए, बल्कि अपने एजेंडों को लोगों के सामने रखना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए की उन्होंने जो वादे किए थे, वो अब तक पूरे क्यों नहीं किए गए? कांग्रेस मदनी के इस बयान पर खूब तिलमिलाई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि नरेन्द्र मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने से उनको फायदा होगा और उनका काम आसान हो गया है. अब वह 2014 लोकसभा चुनाव को मोदी बनाम राहुल के बजाय धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता का रूप दे देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने सबके साथ धोखा किया है. उसके पास न ही कोई एजेंडा है, न हीं कोई विकास का फार्मुला है, जिस पर वह चुनाव लड़ सके. भारत की जनता ने यूपीए के नौ साल के कार्यकाल में सब देख लिया है. कांग्रेस को लगता है कि यदि हिन्दू समर्थक वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो उसे हिन्दुत्व विरोधी वोटों की गोलबंदी उसके खाते में होगी. मदनी के कहे गए बातों पर पार्टियों को ध्यान देना चाहिए. उन्हें अब अपने एजेंडे पर वोट हासिल करना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति वोटरों को भय दिखाकर.

–विनीत, सीतामढ़ी

सबक सीखने की ज़रूरत

फैलिन ने केवल उड़ीसा और आंध्रप्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, झारखण्ड में भी अपने निशान छोड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार कुशलतापूर्वक इससे निपटा गया है, इससे लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगी है और लगता है कि भविष्य में भी ऐसी आपदाओं से साहसपूर्वक निपटा जा सकेगा. जब उड़ीसा में विशेष रडार लगाकर और खतरे वाले इलाकों से लाखों लोगों को निकाला जा सकता है तो ऐसा दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? ऐसा ही उत्तराखण्ड मामले में क्यों नहीं हुआ? वहां भी पहले से पता चल सकता था और हजारों जानें बचाई सकती थीं. मध्यप्रदेश के दतिया में रतनगढ़ मंदिर में महानवमी के दिन हुए भगदड़ में सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत को भी रोका जा सकता था, क्योंकि वहां एक बार ऐसा हादसा हो चुका था, जिसमें कई लोग मारे गए थे. सरकारों को पहले के हादसों से सबक न सिखना सरकार की लापरवाही को ही दर्शाता है. सरकारों को इन सबकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए. सरकारों को आपदाओं से बचने के लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए.

–अमित, वाराणसी

राज्यों में विधानसभा चुनाव

दिल्ली समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है. कई विशेषज्ञ इसे 2014 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं. विधानसभा चुनाव जरूर यह तय करेंगे कि कौन पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग-अलग होते हैं. यह विधानसभा चुनाव नरेन्द्र मोदी के लिए उनकी परीक्षा है. कांग्रेस भी चुनाव में जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है. जो भी सर्वे आए हैं, उनमें मिजोरम को छोड़ दें तो मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है और दिल्ली में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

ग़लती स्वीकारने का साहस दिखाएं प्रधानमंत्री

कहावतें अक्सर सही उतरती हैं, क्योंकि कहावतें हज़ारों साल के अनुभव के बाद दो या तीन लाइनों में सिद्धांत के रूप में निकलकर आती हैं. ऐसी ही एक कहावत फिर सही साबित होने जा रही है. कहावत है कोयले की दलाली में हाथ काला. जो कोयला बेचता है, उसके बारे में कहावत कहीं नहीं बनी. यह कहावत उसके बारे में है, जो कोयले की दलाली करता है.

अब तक सुप्रीम कोर्ट जांच की बात करता रहा और जांच की दिशा कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर की तरफ़ जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन साफ़ तौर पर यह नहीं पता था कि यह दिशा उनके घर तक जाएगी ही. हालांकि, कोयला मंत्रालय की फाइलें गायब हुईं, जिस पर प्रधानमंत्री का पहला बयान आया कि वे फाइलों के कस्टोडियन नहीं हैं. यह बयान ज़िम्मेदार आदमी का बयान नहीं है. प्रधानमंत्री देश के कस्टोडियन हैं और वे फाइलें जब गायब हों, जिन फाइलों का रिश्ता सुप्रीम कोर्ट की जांच से है, सीबीआई की जांच से है और सुप्रीम कोर्ट की चिंता से है, तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि उन्हें भी चिंता हो रही है कि फाइलें कैसे मंत्रालय से ग़ायब हो गईं, लेकिन उन्होंने कहा इसके ठीक उल्टा कि वो फाइलों के कस्टोडियन नहीं हैं. फाइलें ग़ायब होती हैं या नहीं ग़ायब होतीं, इसकी ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है. प्रधानमंत्री का यह बयान खटका और बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लगा कि चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका है, लेकिन देश की तक़रीबन 120 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री लगातार बयान पर बयान बदलते जाएं, यह विश्वास से परे है, पर हिंदुस्तान में ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है. सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं और सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को जांच का निर्देश एक ऐसी चीज़ है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और उन चिंताओं को समझा जा सकता है. अब एक नया बयान आया है और यह बयान है तत्कालीन कोयला सचिव पीसी पारेख का. उन्होंने कहा कि अगर मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है तो प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कोई फ़ैसला अपने आप नहीं किया. मैंने यह फ़ैसला प्रधानमंत्री के निर्देश पर किया है. पूर्व कोयला सचिव का यह बयान सीधे-सीधे यह बता रहा है कि कोयले का सौदा जानबूझ कर किया गया और तत्कालीन कोयला मंत्री श्री मनमोहन सिंह की जानकारी में हुआ. पूर्व कोयला सचिव श्री पारेख ने यह भी कहा कि शिबू सोरेन इस तरह की कार्रवाई के ख़िलाफ़ थे और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह कोल ब्लॉक का आबंटन हो. शिबू सोरेन के बारे में आमतौर पर यह मान्यता है कि वे भ्रष्टाचार के दलदल में काफ़ी हद तक धंसे हुए हैं. उन्हें कई तरह की जांच का सामना करना पड़ा. पैसा लेकर सरकार बचाने का आरोप भी उन पर लगा. कई तरह के मुक़दमे उन पर चले और अभी भी चल रहे हैं. यह माना जा सकता है कि शायद इस सब की जड़ में कहीं शिबू सोरेन हो सकते हैं, लेकिन श्री पारेख ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि शिबू सोरेन इस मसले में बिल्कुल पाक-साफ हैं और प्रधानमंत्री ने कई तरह की आपत्तियों को दरकिनार कर कोल ब्लॉक आबंटन की मौजूदा नीति पर चलने की अनुमति दी. यह नीति न तो संसद में पास हुई और न ही यह नीति कैबिनेट में पास हुई. भारत सरकार की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में झूठ कहा गया कि इसके ऊपर कैबिनेट में फ़ैसला हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट की उस मीटिंग की कार्यवाही रिकॉर्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाए. भारत सरकार यह क्यों नहीं समझती है कि अगर कुछ ग़लत हो गया है, तो उसे स्वीकार करके उसकी ज़िम्मेदारी लेकर, उस ग़लती को सुधारने की कोशिश करे. बजाए इसके कि हर चीज़ के ऊपर एक ऐसा बयान दे जो कि अगले कुछ दिनों में ही ग़लत साबित हो जाता है और सरकार की छीछालेदर होती है. यही हो रहा है. अटार्नी जनरल जी. ई. वाहनवती को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिस झुंझलाहट और डांट की भाषा के साथ संबोधित कर रहे हैं, वह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को वाहनवती के बयानों पर बहुत भरोसा नहीं है. दरअसल, वाहनवती लगातार झूठ बोल रहे हैं. सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी. बाद में सीबीआई ने हलफ़नामा दायर करते हुए कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट चार लोगों ने देखी है और उन चार लोगों में एक वाहनवती स्वयं हैं. वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने बयान में अब तक मांफ़ी नहीं मांगी है और शायद यह सुप्रीम कोर्ट को नागवार भी गुज़र रहा है.

श्री पारेख, जो कोयला आबंटन के समय कोयला मंत्रालय में सचिव थे और जिन्होंने मौजूदा नीति का विरोध किया था, उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप इसी नीति पर चलिए. उनका यह बयान कि अगर मैं दोषी हूं तो प्रधानमंत्री भी दोषी हैं, वास्तव में एक बहुत बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है. इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने जानबूझ कर इस स्कैम को होने दिया. इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और अगर यह स्कैम सही साबित होता है, तो स्पष्ट है कि इसकी इजाज़त प्रधानमंत्री ने स्वयं दी है. यह संयोग नहीं है कि जब आज के प्रधानमंत्री 1992 से 1996 तक की नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे, तब पहला बड़ा विदेशी बैंकों का घोटाला हुआ, जिसमें विदेशी बैंकों ने 5000 करोड़ रुपये हड़प लिए थे. तत्कालीन वित्त मंत्री ने इस स्कैम की पुष्टि की थी, लेकिन उन रुपयों को वापस लाने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया गया, बल्कि उन पैसों की भरपाई भारत सरकार ने अपनी तरफ़ से की और जनता का पैसा एक स्कैम को छिपाने में लगा दिया. इसके बाद तो घोटालों की भरमार सी हो गई और 10 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार से आगे बढ़ते हुए एक लाख करोड़ तक के घोटाले सामने आए. जिस बात की ओर श्री पारेख इशारा कर रहे हैं कि अगर मैं दोषी हूं, तो प्रधानमंत्री भी दोषी हैं, यह घोटाला 26 लाख करोड़ का घोटाला है. 26 लाख करोड़ यानी आज़ादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा घोटाला और उसमें सीधे जो शख़्स शामिल है, उनका नाम मनमोहन सिंह है. मनमोहन सिंह का बचाव करने वाले लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने तो केवल दस्तख़त किए, पैसा तो कहीं और चला गया. क्या इस बात से देश को या सुप्रीम कोर्ट को कोई राहत मिलेगी कि दस्तख़त मनमोहन सिंह ने किए और पैसा कहीं और चला गया. क्या इस पैसे को 2009 के चुनाव में ख़र्च किया गया? क्या यह पैसा विदेशी बैंकों में गया? क्या इस पैसे का पता कभी चल पाएगा? घोटाला हुआ भी है या नहीं हुआ है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री का बचाव करने वाले लोग सवाल उठाते हैं. बड़े अफ़सोस की बात है कि हर ऐसे मुद्दे, जिन पर जनता का विश्वास और उनकी आशाएं टिकी होती हैं, उन पर सरकार कभी कोई क़दम नहीं उठाती, सुप्रीम कोर्ट को क़दम उठाना पड़ता है. चाहे राइट टू रिजेक्ट जैसा छोटा-सा मसला हो, जिस पर हमारा चुनाव आयोग चाहता, तो आसानी से फ़ैसला ले सकता था. हमारा चुनाव आयोग पाकिस्तान के चुनाव आयोग से तुलनात्मक ढंग से ज्यादा ज़िम्मेदार है. लेकिन राइट टू रिजेक्ट का फ़ैसला पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने लिया, वो भी बिना किसी अदालती निर्देश के. बिना किसी सरकारी दबाव के. हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा. अब सुप्रीम कोर्ट कोल आबंटन की विस्तार से जांच कर रहा है और उसने कहा है कि दिसंबर तक जांच पूरी हो जानी चाहिए. यह सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को निर्देश है. अगर यह जांच दिसंबर तक पूरी होती है, तो इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि जनवरी में कोई फ़ैसला आ सकता है.

»» प्रधानमंत्री देश के कस्टोडियन हैं और वे फाइलें जब ग़ायब हों, जिन फाइलों का रिश्ता सुप्रीम कोर्ट की जांच से है, सीबीआई की जांच से है और सुप्रीम कोर्ट की चिंता से है, तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि उन्हें भी चिंता हो रही है कि फाइलें कैसे मंत्रालय से ग़ायब हो गईं, लेकिन उन्होंने कहा इसके ठीक उल्टा कि वो फाइलों के कस्टोडियन नहीं हैं.

यह सब लिखते हुए हमें कतई हर्ष नहीं महसूस हो रहा है. बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ़ कोयला आबंटन का नहीं है. सवाल उससे भी बड़ा है. वह बड़ा सवाल यह है कि उन ख़तों का क्या हुआ, जिन ख़तों को भूतपूर्व थलसेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखा था और जिनमें से कुछ ख़त स्वंय रक्षा मंत्रालय ने या प्रधानमंत्री कार्यालय ने लीक किए थे और जिसके चलते भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष के ऊपर कांग्रेसी नेताओं की तोपें चल पड़ी थीं. किसने लीक किया, महत्वपूर्ण यह नहीं है. उसमें जो कहा गया, वो महत्वूर्ण है और क्या सरकार ने उन ख़तों के ऊपर भारत की सेना की दशा सुधारने के लिए कोई क़दम उठाया? यह सवाल देश के लोगों के मन में है. और हमें यह कहते हुए डर लग रहा है कि अगर कहीं युद्ध की स्थिति आई तो हम अपने से बहुत कमज़ोर दुश्मन से सिर्फ़ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से न हार जाएं. बेवकूफ़ी! वक्त के साथ चलते हुए क़दम न उठाना. बेवकूफ़ी! सही हथियार न ख़रीदना, बेवकूफ़ी! हथियारों के सौदों में बेबाक़ी से दलालों का हस्तक्षेप होना और उसे प्रभावित करना.

यह सवाल हैं, जिनके ऊपर ध्यान तो दिया जाएगा, लेकिन शायद तब, जब सुप्रीम कोर्ट इन सवालों को सरकार के सामने डांट के रूप में पेश करेगा. कोयला आबंटन मामले की जांच दिसंबर में पूरी हो जाएगी, लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर जो सवाल भूतपूर्व थलसेनाध्यक्ष ने खड़े किए थे, उन सवालों को सुप्रीम कोर्ट अपने सवाल कब बनाएगा? ये सवाल कोयला घोटाले से बड़े घोटाले की ओर इशारा करते हैं. क्या हम आशा करें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी आंख और कान थोड़ा और खोले, ताकि इस देश को उस संभावित ख़तरे से निजात मिल सके, जो युद्ध के तौर पर चीन और पाकिस्तान के रूप में खड़ा दिखाई दे रहा है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

तेलंगाना की भूल

»» भारत हमेशा से एक बहुराष्ट्रीय राजतंत्र रहा है. इस प्रकार बने ज़्यादातर क्षेत्रीय राष्ट्र भाषाई आधार पर ही पहचाने गए. इसका अपवाद सिर्फ़ ख़ालिस्तान रहा. इस अलगाववादी आंदोलन को भाषा, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर खड़ा किया गया था.

काफी समय पहले एक गांव में एक ब्राम्हण लड़का रहता था. वह कोई काम नहीं करता था. पूरा दिन गांव में इधर-उधर घूमकर व्यतीत किया करता था. वह अक्सर एक बैल की तारीफ करता था जिसकी सींगें खूबसूरत और वृत्ताकार थीं. लड़के ने बैल की सींगों के बीच से छलांग लगाने का विचार किया. लेकिन वह एक बुद्धिमान लड़का था इसलिए उसने ऐसा तुरंत नहीं किया. बैल पर लगभग एक साल तक निगाह रखने के बाद उसने एक दिन छलांग लगा दी. ऐसा करते ही बैल ने उसे पटक दिया और तब तक मारता रहा जब तक दूसरों ने उसे आकर बचाया नहीं. लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा विचारहीन काम क्यों किया तो उसने कहा यह काम विचारहीन नहीं था, मैं इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था.

पृथक तेलंगाना राज्य के निर्माण पर कांग्रेसी सरकार का निर्णय कुछ इसी प्रकार का है. पी चिदंबरम द्वारा तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने कि घोषणा किए हुए तकरीबन तीन वर्ष हो गए. इसके बाद भ्रम और खंडन का दौर जारी रहा. राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया, लेकिन उसकी संस्तुतियों की चुपचाप उपेक्षा कर दी गई. इसमें और समय बर्बाद हुआ और मुद्दा गरमाता गया. राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश को अनाथ छोड़कर मर गए. जगनमोहन की सत्ता के उत्तराधिकार की आशाएं धरी की धरी रह गईं और मुख्यमंत्री दूसरे को बना दिया गया. जगन को रास्ते से हटा दिया गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन तेलंगाना का मुद्दा जस का तस बना रहा.

और आख़िर में जब सारी सीमाएं पार हो गईं तो पृथक राज्य के निर्माण की मांग को संस्तुति दे दी गई और फिर सब तरफ़ से मुसीबतें टूट पड़ीं. सड़कों पर क्रोधित लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. कई मंत्रियों ने इस्तीफ़े दिए और मुख्यमंत्री भी बाहर निकलने को अकुलाए हुए हैं. आंध्र प्रदेश के भीतर दो पुराने डिवीजन, रॉयलसीमा और सीमांध्र, नई क्षेत्रीय पहचान बन गए हैं. तेलंगाना के पैरोकार खुद को बाहरी बताते हैं. यहां तक कि वे ख़ुद को विदेशी बताते हैं. मामले पर कई राजनेता अनशन पर भी बैठे.

»» पृथक तेलंगाना राज्य के निर्माण पर कांग्रेसी सरकार का निर्णय कुछ इसी प्रकार का है. पी चिदंबरम द्वारा तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा किए हुए तकरीबन तीन वर्ष हो गए. इसके बाद भ्रम और खंडन का दौर जारी रहा. राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया, लेकिन उसकी संस्तुतियों की चुपचाप उपेक्षा कर दी गई. इसमें और समय बर्बाद हुआ और मुद्दा गरमाता गया.

कुछ इसी तरह का काम 60 साल पहले भी हुआ था. जब पहली बार पोट्टी श्रीरामुलू ने भाषाई आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अनशन किया था. उन्होंने कुछ ऐसा किया जो ज़्यादातर अनशन करने वाले लोग करने से बचते हैं. उनकी मौत हो गई. आंध्र प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मज़बूत गढ़ होने के बावजूद पंडित नेहरू भाषाई आधार पर पृथक राज्य निर्माण के ख़िलाफ़ थे. लेकिन उन्हें मांग स्वीकार करनी पड़ी. राज्य के गठन के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया.

नेहरू ने भले ही भारत की खोज की हो, लेकिन वे इसकी विविधता की पूरी तरह से प्रशंसा नहीं कर पाते थे. एक बात उन्हें माननी पड़ी कि भारतीय ख़ुद को एक ही समय में भारतीय होने के साथ-साथ पंजाबी, मलयाली और तमिल भी मानते हैं और भारतीयों में इस बात को लेकर मतभिन्नता भी नहीं है. इसके विपरीत चीन के पूरे इतिहास में सभी देशवासी ख़ुद को सिर्फ़ देशवासी मानते हैं.

भारत हमेशा से एक बहुराष्ट्रीय राजतंत्र रहा है. इस प्रकार बने ज़्यादातर क्षेत्रीय राष्ट्र भाषाई आधार पर ही पहचाने गए. इसका अपवाद सिर्फ़ ख़ालिस्तान रहा. इस अलगाव-वादी आंदोलन को भाषा, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर खड़ा किया गया था. जिसे इंदिरा गांधी द्वारा बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर सही तरीके के दबाया दिया गया. लेकिन राजीव गांधी ने उत्तर पूर्व में आसानी से नए राज्य बनाए. वहीं भाजपा ने तो हमेशा से नए राज्य बनाने में आसानी महसूस की है.

हालांकि, तेलंगाना का मामला अलग है. यहां के लोगों की आंध्र के दूसरे इलाक़े के लोगों से भाषाई आधार पर कोई भिन्नता नहीं है. लेकिन इसमें राष्ट्रवाद जैसी भावना तब से है, जब से यह पुराने हैदराबाद राज्य का हिस्सा था. भारत के निर्माण में यह एक और पेच था कि राज्यों को देश में मिलाने के साथ ही उनके अधीन राज्यों को भी मिला लिया गया. लेकिन दिक्कत यह कि अगर तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया है तो अब आख़िर हम कहां जाकर रुकेंगे. इस तरह तो पूरे राजस्थान को कई पुराने राजसी प्रदेशों में बांटा जा सकता है. उत्तर प्रदेश के अवध को अलग राज्य का दर्जा देना पड़ेगा. कुल 600 राजसी प्रदेशों को सरदार पटेल ने भारत में मिलाया था. धन्यवाद देना चाहिए उनको. क्या अब इन सभी राजसी प्रदेशों को पृथक राज्यों का दर्जा दिया जाएगा?

इस तरह के रास्ते में कई दिक्कतें और व्यवधान हैं. तेलंगाना की समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना आवश्यक है. ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि एक महाआंध्र बनाया जाए, जिनमें तीन स्वायत्त प्रदेश हों तेलंगाना, रॉयलसीमा और सीमांध्र. और तीनों की एक ही राजधानी हो. इसके लिए हमें बेल्जियम की तरफ देखना चाहिए. पूरे देश में सिर्फ़ दो भाषाएं हैं- फ्लेमिश और फ्रेंच और तीन प्रदेश फ्लैंडर्स, वैलोनी और ब्रुसेल्स. ये सभी प्रदेश क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विषयों के अलग-अलग विधायी सत्र लगाते हैं. यह महाआंध्र के लिए एक सीख हो सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

अभी और आगे जाना है

इंदिरा आवास योजना के तहत 25,000 रुपये देने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर (बीडीओ) के दफ्तर में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी. लाचार, अनपढ़ और ग़रीब मज़लूम तीन सालों से बीडीओ के दफ्तर के चक्कर लगा रहा था. मज़लूम की मदद गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का आवेदन बनाकर की.

चौथी दुनिया ब्यूरो

मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के 78 में से 71 मंत्री महज़ साढ़े तीन सालों में 786 बार विदेश यात्राओं पर रहे. इन मंत्रियों ने कुल मिलाकर एक करोड़ दो लाख किलोमीटर की हवाई यात्राएं कीं. 15 दिनों के कॉमनवेल्थ खेल तमाशे के लिए जनता के टैक्स के वे 725 करोड़ रुपये भी लगा दिए गए, जो अनुसूचित जाति–जनजाति कल्याण के लिए बजट में रखे गए थे. कश्मीर में तैनात एक मेजर की मां जानती है कि उसके बेटे की आत्महत्या की कहानी झूठी है और अब उसकी जानकारी के आगे मजबूर भारतीय सेना को मामले की पुन: जांच करानी पड़ रही है. गाज़ियाबाद ज़िले के सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे अध्यापक अपनी पहुंच और पैसों के बल पर अपनी तैनाती ज़िला मुख्यालय में ही करा लेते हैं, यह जानकारी जनता को जब होती है तो पहुंच और पैसों की ताक़त कमज़ोर पड़ जाती है.

ये सारे खुलासे सूचना क़ानून के ज़रिए ही हुए हैं. आप ज़रा सोचें कि क्या ये खुलासे आज से पांच साल पहले तक संभव थे? और अगर थे भी, तो क्या ये खुलासे आम आदमी कर सकता था? गुलामी के लंबे इतिहास के बाद इस देश में परिवर्तन की बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं और इनका आधार बन रहा है 2005 में लागू सूचना का अधिकार क़ानून. 13 अक्टूबर, 2010 को यह कानून पांच साल पुराना हो गया. बिहार के झंझारपुर गांव (जिला मधुबनी) में रिक्शा चालक मज़लूम ने 2006 में ही जिस तरह इस क़ानून का इस्तेमाल किया, उससे इसकी ताक़त एवं उपयोगिता को लेकर एक नया भरोसा पैदा होता है. इंदिरा आवास योजना के तहत 25,000 रुपये देने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर (बीडीओ) के दफ्तर में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी. लाचार, अनपढ़ और ग़रीब मज़लूम तीन सालों से बीडीओ के दफ्तर के चक्कर लगा रहा था. मज़लूम की मदद गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का आवेदन बनाकर की. सवाल पूछते ही एक सप्ताह के भीतर मज़लूम को 15 हज़ार रुपये का चेक मिल गया. एक महीने बाद जब बाक़ी के 10,000 रुपये लेने गए मज़लूम से रिश्वत मांगी गई तो अनपढ़ मज़लूम ने बीडीओ से साफ–साफ कह दिया कि अगर मेरा पैसा नहीं दोगे तो फिर से सोचना की अर्जी लगा दूंगा. सोचना और सूचना में फ़र्क़ न समझने वाले निरक्षर मज़लूम को एक ही अनुभव में मालूम हो गया कि यह कोई बड़ा परिवर्तन हो गया है. ज़ाहिर है, यह परिवर्तन समाज के सशक्तिकरण में सहायक साबित हुआ है. बस ज़रूरत इस क़ानून के इस्तेमाल करने की है, बिना किसी डर के. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बाटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

स्ट्रीट लाइट के संबंध में आवेदन

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

निम्नलिखित स्ट्रीट लाइट काफी दिनों से काम नहीं कर रही है.....

इसके लिए कई शिकायतें की जा चुकी हैं (प्रति संलग्न है), लेकिन उन शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. नगर निगम ने इस क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का ठेका किसे दिया है? उस ठेके की प्रति दें.

2. नागरिकों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद कितने दिनों के अंदर खराब लाइटों की मरम्मत हो जानी चाहिए?

इससे संबंधित कांट्रैक्ट या यदि कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.

3. यदि लाइटों की मरम्मत उपरोक्त समय सीमा के अंदर नहीं होती है तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? इससे संबंधित कांट्रैक्ट या यदि कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.

4. किन परिस्थितियों में ठेकेदार के भुगतान में कटौती की जाती है? इससे संबंधित कांट्रैक्ट या यदि कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.

5. क्या मेरे द्वारा की गई शिकायतों के संदर्भ में ठेकेदार के भुगतान में कोई कटौती की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

6. यदि हां, तो कितने दिनों के भीतर नगर निगम ठेकेदार के भुगतान में से कटौती कर लेगा?

7. किन परिस्थितियों में कांट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है? इससे संबंधित नियमों या यदि कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.

8. क्या मेरे द्वारा की गई शिकायतों के संदर्भ में कांट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है?

9. यदि हां, तो कितने दिनों के भीतर नगर निगम कांट्रैक्ट रद्द कर देगा?

10.अगर ठेकेदार अपना काम सही तरीके से नहीं करता है तो नगर निगम के पास कौन-कौन सी शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग करके वह ठेकेदार को सही तरीके से काम करने के लिए बाध्य कर सकता है?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)

इस सप्ताह शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप परेशान न हों. आप संयम से काम लें और क्रोध से बचें. ज्यादा अधिक काम के कारण थका हुआ महसूस करेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों के लिए यह सप्ताह खुशी देने वाला होगा. किसी फिजूल कामों में अपना समय व्यर्थ न करें. समय उपयोगी है, इसका सदुपयोग करें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)

इस सप्ताह आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे. सामाजिक गतिविधियों के कारण लोगों के नजर में रहेंगे और आपकी प्रशंसा होगी. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. दांपत्य जीवन और संतान सुख में वृद्धि होगी. धार्मिक कार्यो में रुचि बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बितेगा और खुशी का अनुभव करेंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)

इस सप्ताह किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचें. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अन्य कार्यो की योजनाएं बनाएंगे. धार्मिक कार्यो में आपकी रुचि बढ़ेगी और जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे. आपको पारिवारिक सहायता प्राप्त होगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)

इस सप्ताह अपने ज्ञान से ज्यादा कार्य करेंगे. नई संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतें और सारे कानूनी दस्तावेजों की जांच कर लें. अपने सहयोगियों के साथ तालमेल रखें और धैर्य से कार्य करें. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. अपने मानसिक स्थिति को मजबूत रखें और दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी निर्णय लें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)

इस सप्ताह आपका समय सामाजिक कार्यों में ज्यादा व्यतीत होगा. तनाव से बचें, क्योंकि कुछ परेशानी हो सकती है. आर्थिक लेन-देन करते समय सावधानी बरतें. व्यवसायियों के लिए समय अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा वाले लोग संयम से काम लें, अन्यथा हानि हो सकती है. जीवनसाथी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करेंगे. किसी भावना में आकर कोई भी कार्य न करें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)

इस सप्ताह कलात्मक चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आर्थिक मामलो में सावधानी पूर्वक कार्य करें. सबकी बात सुनें, लेकिन निर्णय लेते समय अपने मन की सुनें. आपसी प्रेम में कोई नकारात्मकता न आने दें और कोई भी पारिवारिक मामला उलझने न दें. अपने जमा किए हुए पैसे का दुरुपयोग न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)

इस सप्ताह थोड़ा संघर्ष करने के बाद सफलता मिलेगी. आपके सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होगी. लेन-देन के मामलों में काफी सतर्कता बरतें. संपत्ति खरीदने की संभवना है. संतान और दांपत्य सुख भी बढ़ेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों अपने कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे. किसी के द्वारा दिए गए सलाह से कोई निर्णय न लें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)

यह सप्ताह काफी अच्छा फल देने वाला होगा. दौड़-भाग रहेगी. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. व्यवसायियों को कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी. परिवार के लोगों से थोड़ी नाराजगी हो सकती है. नौकरीपेशा वाले लोग अपने साथ कार्यरत लोगों से सदभावना बनाकर रखें. अचानक यात्रा पर जाने का योग है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)

इस सप्ताह आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी वाद-विवाद से बचें. स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा. तनाव से बचें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. व्यापारियों को अपने व्यापार का विस्तार करने में सफलता प्राप्त होगी. पारिवारिक जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)

इस सप्ताह आपके कई अनसुलझे कार्य सुलझ सकते हैं. आपको लाभ का प्रबल योग है. नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए समय मिला-जुला फल देने वाला होगा. आपके कुछ नये लोगों से संपर्क बढ़ेगें. विद्यार्थी भी अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे. व्यापारियों को जोखिम भरा कार्य करने से बचने की जरूरत है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)

इस सप्ताह आपके कार्य में बाधा आने से मन चिंतित रहेगा. नौकरी-पेशा और व्यापारी दोनों के लिए समय आर्थिक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. खर्चों में वृद्धि रहेगी. संपत्ति खरीदने सम्बंधित बात आगे बढ़ सकती है. आप लम्बी दूरी की यात्रा पर जाने से बचें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)

इस सप्ताह आप अपने व्यवसाय में किसी भी तनाव से बचें और नकारात्मक सोच के साथ आगे न बढ़ें. आर्थिक मामलों में इस समय किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मौसम के बदलाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. आपके साथ कार्यरत लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

ज़रा हट के

करोड़ों का पानदान

भारतीय वस्तुओं की पहली नीलामी में 18वीं सदी के हीरा का सेट, स्वर्ण पानदान लगभग 7 करोड़ में नीलाम हुआ. यह नीलामी सूदबीज की ओर से की गई. भारतीय कला संग्रह को ख़रीदने के लिए दुनिया भर से बोली लगाने वाले आए थे. भारत की 500 साल की सजावटी कला का प्रतिनिधित्व करने वाली 90 से ज्यादा बेशकीमती वस्तुएं नीलामी में रखी गईं थीं.

नीलामी में लगभग 20 करोड़ की बिक्री हुई. नीलामी बिक्री के मध्य पूर्व के निदेशक बेनेडिक्ट कार्टर ने एक बयान में कहा कि भारतीय कलाकृति में हाल के सालों में रुचि बढ़ी है. भारतीय जगत से संबंधित सराहनीय काम की मांग बढ़ी है. टीपू सुल्तान के समय की 11 चीजें लगभग 4 करोड़ में बिकीं. एक बोली लगाने वाले ने टीपू सुल्तान की तलवार 98 हजार 500 पाउंड में खरीदी. ■

बच्चे ने नींद उड़ाई

कोई बच्चा इतना शरारती हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते. मिनिपोलिस में 9 साल के एक बच्चे ने पुलिस और प्रशासन की हवा निकाल कर रख दी. मिनिपोलिस के डेल्टा एयरलाइंस की लॉस वेगास जाने वाले हवाई जहाज में यह बच्चा सवार हो गया. गौर करने वाली बात तो यह है कि उसने किसी भी कर्मचारी को भनक तक नहीं लगने दी कि वह अकेला है और उसके पास यात्रा के लिए टिकट भी नहीं है. एयरपोर्ट को इसकी जानकारी हवाई जहाज के उड़ान भरने के बाद चली. हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहाज में बैठने से पहले उसने लगेज कारसोल से एक लगेज बैग लिया और एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाया. रेस्टोरेंट में एक अनपेड चेक और बैग छोड़कर वह फिर जहाज में बैठ गया. बाद में लास वेगास में जहाज के उतरते ही बच्चे को हिरासत में ले लिया गया. इस घटना ने वहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है. बच्चे को कुछ दिनों पहले ही उसे कार चलाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस का कहना है कि बच्चा कार भी चुराकर ही चला रहा था. बच्चा अब पुलिस की हिरासत में है, लेकिन नाबालिग होने के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. बच्चे के इस कारनामे ने पूरे प्रशासन को एक बार फिर से सकते में डाल दिया है. ■

प्लेन का दरवाज़ा होटल पर गिरा

अमेरिका में एक चौंकाने वाला हादसा हुआ. एक पैसेंजर प्लेन का दरवाजा टूटकर मोंटेरे शहर में बने एक होटल पर गिर पड़ा. इस प्लेन ने मोंटेरे रीजनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी.

75 पाउंड वजनी का यह दरवाजा करीब 1 हजार फुट की ऊंचाई से एल कैसल होटल की छत पर गिर पड़ा. उस वक्त नीचे कोई नहीं था, इसलिए इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली. बाद में इसे वहां से हटाया गया. पायलट का कहना है कि उसने आवाज सुनी थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि यह प्लेन का दरवाजा है. पायलट जहाज समेत सकुशल एयरपोर्ट पहुंचा. अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी इस मामले की जांच कर रही है. ■

जब मृतक हज यात्री ज़िंदा मिला

दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की बदरुन्निसा और बरकतुल्लाह हज करने मक्का गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के पहले ही दिन दोनों एक–दूसरे से बिछड़ गए. सऊदी अरब के समाचार पत्र (अरब न्यूज) के अनुसार, बदरुन्निसा के चार दिनों तक बरकतुल्लाह की तलाश करने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो उसने मान लिया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है. उसके साथ हज यात्रा पर गए अन्य तीर्थ यात्री भी बरकतुल्लाह को मृत मान चुके थे. बरकतुल्लाह के परिवार वालों ने भारत में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां तक कर ली थीं. उन्होंने आगे बताया कि वह अपने पति की आत्मा की शांति की दुआएं कर रही थी और भारत में भी अपने परिवार वालों को ऐसा ही करने के लिए कहा, लेकिन एक स्वयंसेवी संगठन (इंडिया फ्रैटर्निटी फोरम) ने बरकतुल्लाह को मक्का के किंग अब्दुल्लाह मेडिकल सिटी अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में जीवित खोज निकाला. समाचार पत्र के मुताबिक सऊदी आपात दल बरकतुल्लाह को हज के लिए एंबुलेंस से अराफाह ले गया और बाद में वापस चिकित्सा केंद्र पहुंचा दिया. बाद में सऊदी चिकित्सा अधिकारियों ने बदरुन्निसा को तलाश कर उन्हें और चेन्नई में उनके बेटे को बरकतुल्लाह के जीवित होने का समाचार दिया. अपने पति को जीवित पाकर बदरुन्निसा ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हम तो उन्हें मरा हुआ मान चुके थे. ■

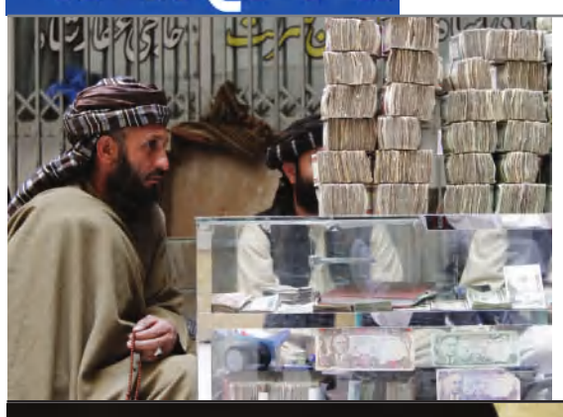

महिलाएं भी आतंकी संगठनों के आर्थिक नेटवर्क में शामिल हैं. प्रमुख आतंकी संगठन अल–शहाब के आर्थिक ढांचा को मजबूत करने के लिए कुछ महिलाएं भी काम करती हैं. ये महिलाएं अल–शहाब की मदद के लिए मिनिसोटा में डोर–टू–डोर गईं और चैरिटी और गरीबों के नाम पर पैसा इकट्ठा कीं.

भारत-अमेरिका की नई पहल

आतंकी संगठनों की आर्थिक नाकाबंदी

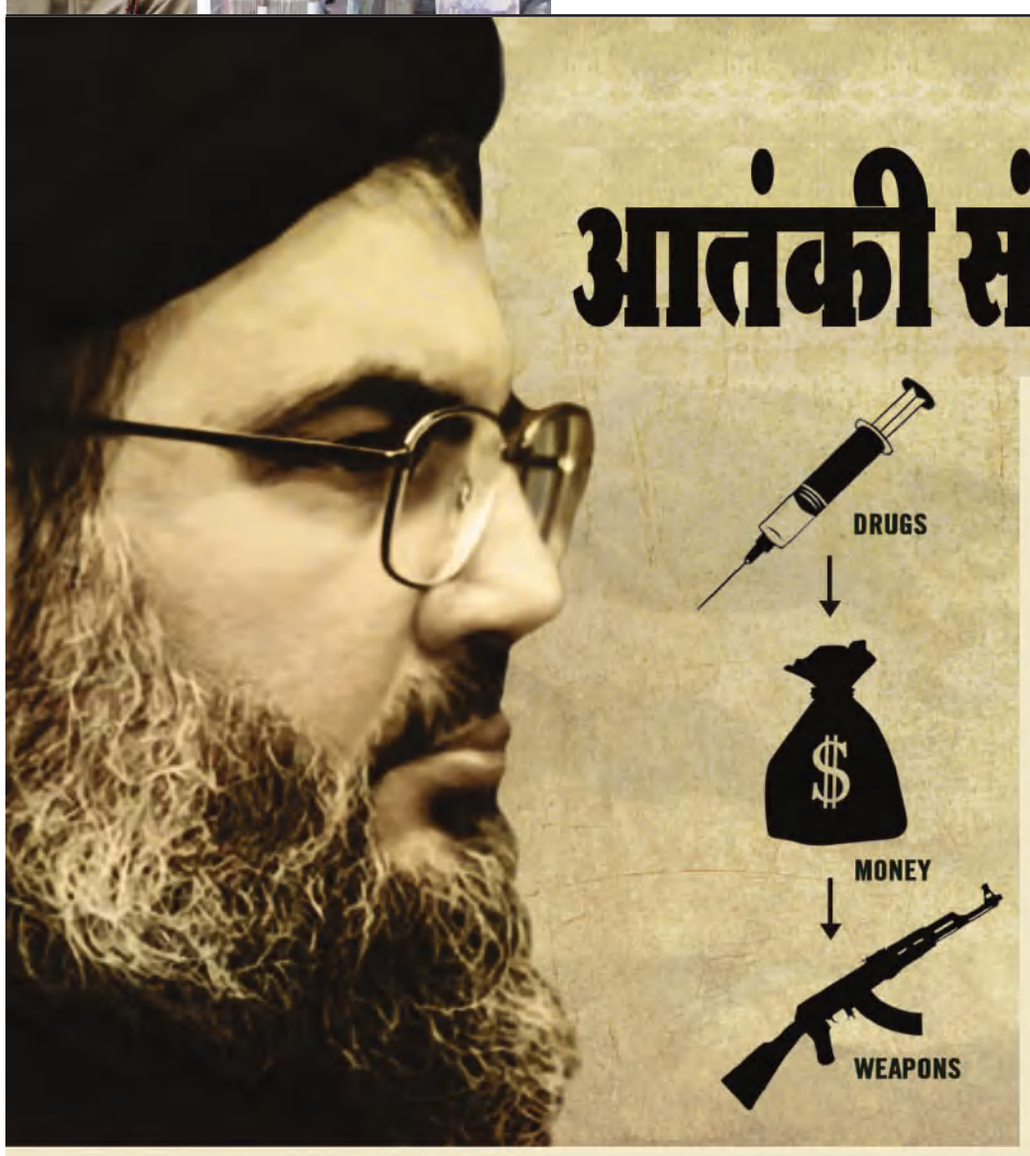

भारत और अमेरिका ने आतंकियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक नई पहल की है. हालांकि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर भारत के साथ हमेशा ही दोहरा मापदंड अपनाता रहा है, जिससे पाकिस्तान में विश्व के लगभग सभी बड़े आतंकी संगठनों को पनाह मिलती रही है. ऐसे में भारत को अमेरिका से सतर्क रहना होगा और अपने स्तर से आतंकियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रयास करना होगा.

राजीव रंजन

भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों देश मिलकर लश्कर–ए–तैयबा, जमात–उद–दावा, हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों व उनसे जुड़े आतंकियों के वित्तीय संपर्क को तोड़ेंगे. इन देशों ने यह भी तय किया है कि वे इन आतंकी संगठनों के धन उगाही की गतिविधियों को भी रोकेंगे.

भारत का नजरिया आतंकवाद को लेकर हमेशा से ही बहुत सख्त रहा है. इसीलिए वह आतंकवाद के मसले पर एकजुट होने का हमेशा से ही दुनिया का आह्वान करता रहा है, लेकिन भारत का प्रयास उस समय विफल हो जाता है, जब अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते और परोक्ष रूप से आतंक का हाथ मजबूत करते हैं. ये सब तब होता है, जब विश्व के लगभग सारे देश आतंकवाद से किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं. आतंकियों के आर्थिक संजाल को तोड़ने की चिंता आज इसी का नतीजा है.

अमेरिका गंभीर नहीं

बड़बोले और दोहरे मापदंड का वाहक अमेरिका भारत के साथ मिलकर किस तरह से आतंकी नेटवर्क और उसको मिलने वाली मदद को रोकेगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आतंकवाद को लेकर अमेरिका भारत का हाथ कितना मजबूत करता आया है, कितना उसने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देने के लिए ठोस कार्रवाई की है, यह पूरी दुनिया जानती है. आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भारत के साथ अमेरिका पहले से ही जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता रहा है, वह इस बात की तस्दीक करता है कि भारत के साथ अमेरिका आतंकवाद रोकने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है, बल्कि यह समझौता सिर्फ अमेरिका का दिखावा मात्र है. ऐसा नहीं कि भारत अमेरिका की चाल को समझता नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझता है, लेकिन वह आतंकवाद के मसले पर किसी भी समझौते को आशा और उम्मीद की नजरों से देखता है. ये भारत की आतंकवाद के खात्मे के प्रति गंभीरता को दर्शाता है.

खैर, अमेरिका अगर भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहा है, तो आतंकवाद के खात्मे के लिए यह सराहनीय प्रयास होगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, जिनकी पड़ताल किए बिना अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता. इस कड़ी में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकियों को सारे संसाधन जुटाने के लिए पैसे कौन मुहैया कराता है. कहां से आते हैं आतंकियों के पास उनके आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पैसे. कैसे ओसामा बिन लादेन अमेरिका जैसे देश से दो–दो हाथ करने की सोच लेता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद भी अमेरिका आतंक के खिलाफ क्यों नहीं कोई ठोस नीति तैयार नहीं कर पाता. कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है. एक तरफ तो वह आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंक को लेकर कोई सख्ती भी नहीं बरतता. यही कारण है कि पाकिस्तान और वहां की सेना लश्कर ए तैयबा जैसे जेहादी गुटों को लगातार आर्थिक और अन्य तरह की मदद देते जा रहे हैं. दुनिया जानती है कि पाक सेना के अफसरों ने डेविड कोलमैन हेडली के जासूसी प्रशिक्षण, भारत आने, उसके ठहरने और अन्य खर्चों की फंडिंग भी पाक सेना के अफसरों ने ही की थी. एक मीडिया ग्रुप द्वारा कराई गई स्वतंत्र जांच में भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया था कि हेडली को हमले का षड़यंत्र रचने के लिए पाकिस्तान द्वारा ही आर्थिक मदद पहुंचाई गई थी.

भारत को पता है

ऐसा नहीं कि अमेरिका के पास पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और उसको होने वाले फंडिंग के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है. कई बार अमेरिका को किसी आतंकी वारदातों में हाथ होने के सबूत दिए गए. बावजूद इसके, अमेरिका पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता करने से बाज नहीं आता. अगर अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना बंद कर दे तो आतंकवाद को पाकिस्तान फंडिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिका से जो पैसा पाकिस्तान को मिलता है, उसे पाकिस्तान अपने यहां के आधारभूत संरचनाओं को सुधारने या विकास में न लगाकर आतंक को पनाह देने में लगा देता है. यही कारण है कि विश्व के लगभग सारे बड़े आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के समय–समय पर पाकिस्तान में उपस्थिति के बारे में पता चलता रहता है. अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में गंज मदरसे के नाम से मशहूर जामिया तालीम उल कुरान वल हदीत मदरसे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे आतंक के लिए पैसा उगाहने वाला संगठन करार दिया. इस मदरसे पर इन आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग करने का भी आरोप है.

भारत कुछ भी कहे, अमेरिका को तब तक फर्क नहीं पड़ता, जब तक उसके अपने हित प्रभावित न हों. यहीं अमेरिका अपनी दो–गली नीतियों का सहारा लेने लगता है और आतंकवाद के प्रति दृढ़ता का उसका असली मुखौटा दुनिया के सामने आ जाता है.

फंडिंग के रास्ते

पिछले साल भारतीय वित्त मंत्रालय ने आतंक को फंडिंग को लेकर जो रिपोर्ट जारी की थी, वह चौंकाने वाली है. मंत्रालय के तहत काम करने वाली फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू की रिपोर्ट के मुताबिक, आतंक से जुड़ी फंडिंग में 300 फीसद की बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट बताती है कि साल 2010–11 और 2011–12 के बीच लेन–देन के 1016 संदिग्ध मामलों की बढ़ोतरी हुई. मतलब साफ है कि आतंकवाद को लेकर कोई भी देश गंभीर नहीं है. अब हम एक नजर डालते हैं इन आतंकी संगठनों के फंडिंग के बारे में.

इन आतंकी संगठनों को हवाला और टैक्स चोरी के जरिये बड़े पैमाने पर पैसा हासिल होता है. गंभीर चिंता की बात ये है कि खाड़ी देशों के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल के माध्यम से हवाला के जरिये पैसा भारत आ रहा है. भारत के वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली एफआईयू ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हवाला और टैक्स चोरी के मामले में 100 फीसद की बढ़ोतरी हुई है. साल 2010–11 और 2011–12 के बीच 49 हजार नये मामले सामने आए, जो गंभीर बात है. एक साल के अंदर आंकड़ों में यह बदलाव सरकार और उनके देशों की आतंक के प्रति गंभीरता की पोल खोल कर रख देता है. दूसरी ओर यह बात भी साफ हो जाती है कि किस तरह से आतंकी संगठन आतंक के प्रति सरकारों की उदासीनता का फायदा उठाकर अपना पांव मजबूत करते जा रहे हैं. आतंक को फंडिंग सिर्फ इन्हीं दोनों रास्तों से नहीं होता, बल्कि फंडिंग के नये रास्ते भी खुल गए हैं, जो चौंकाने वाले हैं. देश में नकली नोट के मामले में भी 30 फीसद बढ़ोतरी हुई है. सिर्फ साल 2010–11 और 2011–12 के बीच ही नकली नोट के 75,934 नये मामले सामने आए हैं. आतंक की फंडिंग से लेकर नकली नोट के बढ़ते मामले देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. हालांकि न तो नकली नोट का मामला नया है और न ही आतंक की फंडिंग का, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, वो यह कि इन दोनों के बीच गठजोड़ नया है, जो देश–दुनिया के लिए खतरनाक है. आतंकी संगठनों को फंडिंग में टूर ऑपरेटर भी काफी सहायक साबित हो रहे हैं, जिसका पता लगाने में खुफिया एजेंसियों को काफी मुश्किलें आ रही हैं. आतंकी संगठनों को चैरिटी के रास्ते भी फंडिंग हो रही है. कनाडा का समाचार पत्र टोरंटो स्टार की मानें तो आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन को पाक की एक एजेंसी से फंडिंग हो रही है, जिसके तार कनाडा के एक इस्लामिक चैरिटी से जुड़े हैं. आतंकी संगठन फिरौती के माध्यम से अरबों डॉलर की कमाई करते हैं. वे यूरोप, पूर्व एशिया के देशों, उत्तर अमेरिका, सोमालिया, अफगानिस्तान, अफ्रीका सहित अन्य देशों के व्यवसायियों का पहले अपहरण करते हैं, फिर बाद में मोटी रकम लेकर उन्हें छोड़ते हैं.

कैसे कसेगी नकेल

भारत और अमेरिका ने आतंकी संगठनों की आर्थिक नाकेबंदी के लिए जो संकल्प लिया है, वह तभी सफल होगा, जब यह पता चले कि इनके फंडिंग के रास्ते क्या हैं, कहां से होती है इन्हें फंडिंग और फंडिंग कौन कर रहा है और जो फंडिंग कर रहा है, उसे यह पता है भी या नहीं कि वह आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा है या सामाजिक कार्यों के लिए किसी नेक संगठन को. मतलब फंडिंग करने वालों का मकसद क्या है, यह जानना जरूरी है. एक दूसरी बात, जो बड़ी चिंता बनती जा रही है, वह यह कि भारत या किसी भी देश की खुफिया एजेंसियां आतंकी संगठनों की आर्थिक नाकेबंदी को लेकर आज तक न तो सख्त हो सकी हैं और न ही कोई रोडमैप तैयार कर सकी हैं. यही कारण है कि आतंकी संगठनों की फंडिंग में सिर्फ एक साल में 300 फीसद की बढ़ोतरी हुई है. आतंकी संगठनों को पैसा हवाला, फिरौती, चैरिटी, नकली नोट, टैक्स चोरी, टूर ऑपरेटिंग सहित अन्य रास्तों से आता है. इसके अतिरिक्त आतंकवाद को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने वाले देशों द्वारा भी आतंकवाद को खूब आर्थिक मदद दी जाती है. फंडिंग को रोकने के लिए भारत को अपने यहां के आधारभूत वित्तीय संरचनाओं को समझना होगा और उसे लेकर एक रोड मैप तैयार करना होगा. इसे खुफिया एजेंसियों को भी समझना होगा, ताकि वे आतंकी संगठनों के वित्तीय संजाल को तोड़ सकें. भारत में जाली नोटों का बड़े पैमाने पर जाल फैला हुआ है. आरबीआई भी इस पर रोक नहीं लगा पा रही है. खुफिया एजेंसियां, आर्थिक संगठन और प्रशासन सहित सरकार के अन्य विभाग मिलकर काम करें तो हमें इस काम में सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी. फंडिंग का मामला देश में हो या देश के बाहर, यह जरूरी है कि भारत इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अपने स्तर से प्रयास करे, अमेरिका का मुंह न देखे, क्योंकि अमेरिका की कोई भी कार्रवाई उसके हितों पर निर्भर करती है, न कि भारतीय हितों पर. ऐसा अन्य देशों पर अमेरिकी हमले से साफ हो भी गया है. जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान और चीन को परोक्ष रूप से हमारे खिलाफ उकसाता है, वह हमें सतर्क करने के लिए काफी है. हवाला के जरिये सिर्फ आतंकी ही नहीं, बल्कि भ्रष्ट नेता और देश के लोग भी बड़े पैमाने पर पैसा इधर से उधर करते हैं. ऐसी स्थिति में आतंकियों की आर्थिक नाकेबंदी की कल्पना नहीं की जा सकती. सचमुच अमेरिका भारत के साथ मिलकर आतंकियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना चाहता है तो उसे दोहरे मापदंड से बचना होगा. ओसामा बिन लादेन का हाथ अमेरिका ने ही मजबूत किया था. सीएनएन डॉट कॉम की मानें तो अल–शहाब आतंकी संगठन को अमेरिका से आर्थिक मदद मिलती रही है. ऐसे में अमेरिका भारत का साथ कैसे दे सकता है.

देश में आतंकियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना होगा. इस मामले में हम इंडोनेशिया को फॉलो कर सकते हैं. इंडोनेशिया में हाल ही में एक कानून पास हुआ है, जिसमें आतंकियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए यह प्रावधान है कि जो आतंकियों या उनके संगठनों को फंडिंग करेगा, उसे आजीवन कारावास होगा. इसके अतिरिक्त वहां यह भी प्रावधान है कि आतंक को फंडिंग करने वाली कंपनियों को 10.3 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरना होगा. साथ ही उस कंपनी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. भारत में अगर सख्त कानून बनता है तो एक बड़ी विडम्बना है कि उसको लागू कैसे किया जाए, क्योंकि अक्सर कानूनों की आड़ में पुलिस और प्रशासन निर्दोषों को गिरफ्तार कर लेता है. मतलब बिना पारदर्शिता के यह काम संभव नहीं है. अगर आतंकियों की आर्थिक नाकेबंदी करनी है तो यह भी जरूरी है कि पुलिस और प्रशासन और साथ ही सरकार के अन्य विभाग, जो इस काम में लगे हैं, में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े आतंकी छोटे–छोटे मुहल्लों या कॉलोनियों में पकड़े गए हैं. बिना जनता के सहभागिता के और जनता से संपर्क बनाए ऐसी कॉलोनियों या मुहल्लों की तंग गलियों या घरों तक पहुंचना मुश्किल है.

एक और चिंता की बात यह है कि महिलाएं भी आतंकी संगठनों के आर्थिक नेटवर्क टीम में शामिल हैं. प्रमुख आतंकी संगठन अल–शहाब के आर्थिक ढांचा को मजबूत करने के लिए कुछ महिलाएं भी काम करती हैं. ये महिलाएं अल–शहाब की मदद के लिए मिनिसोटा में डोर–टू–डोर गईं और चैरिटी और गरीबों के नाम पर पैसा इकट्ठा कीं. वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के तहत भी आतंकी नेटवर्क करोड़ों रुपये भारत मंगाते हैं, इस पर भी नकेल कसनी होगी. इसके लिए बैंकिंग सिस्टम को समझना होगा और गलत ट्रांजेक्शन पर रोक लगाना होगा. भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी सकरार के सिस्टम पर भी लोगों का भरोसा नहीं है. इसलिए जरूरी है कि लोगों में सिस्टम के प्रति विश्वास कायम किया जाए. आतंकियो द्वारा किए जाने वाले फिरौती के मामले में भी सरकार को चाहिए कि उसके प्रति जनता का विश्वास बना रहे. प्राइवेट कंपनी और एनजीओ के लोगों का जब ये आतंकी अपहरण कर लेते हैं तो ये सरकार से मदद लेने के बदले अपने लोगों को छुड़ाने के लिए फिरौती के पैसे देकर अपने स्तर पर ही मामला को रफा–दफा कर देते हैं. यह साफ जाहिर करता है कि लोगों में सरकार को लेकर विश्वास की कमी है. अब अमेरिका और भारत आतंकियों की आर्थिक नाकेबंदी कैसे करते हैं, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन यह तय है कि समझौते से ज्यादा जरूरी है उसको अमल में लाना, जो फिलहाल दिखता नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं

आठ मील चलने पर जब आप नीमगांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दिखाई देने लगता है. कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थस्थान गाणगापूर, नरसिंहवाडी और औदुम्बर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है. जिस प्रकार दामाजी ने मंगलवेढ़ा को (पंढरपुर के समीर), समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्रीनरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतरित होकर उसे पावन बनाया.

एक बार...

शिरडी के दाता सबसे महान

चौथी दुनिया ब्यूरो

भगवद् गीता के (चौथे अध्याय 7–8) में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब–जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब–तब मैं अवतार लेता हूं. धर्म–स्थापना दुष्टों का विनाश तथा साधुजनों के कल्याण के लिए मैं युग–युग में जन्म लेता हूं. साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं. वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्यप्रणाली द्वारा अपना अवतार–कार्य पूर्ण करते हैं. अर्थात जब ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब धार्मिक उपदेशों की उपेक्षा होने लगती है, जब प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब विभिन्न जाति–धर्म के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जब जनसाधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है तथा इस प्रकार जब लोग सत्य–मार्ग से विचलित होकर अध:पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रगट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं. वे हमें उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं. इसी मार्ग पर अनेक संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, सावंत माली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य–मार्ग का दिग्दर्शन कराने के लिए भिन्न–भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में साई बाबा का अवतार हुआ.

पवित्र स्थान शिरडी

अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म लिया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया. ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे. शिरडी, अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है. गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है. आठ मील चलने पर जब आप नीमगांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दिखाई देने लगता है. कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाणगापूर, नरसिंहवाडी और औदुम्बर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है. जिस प्रकार दामाजी ने मंगलवेढ़ा को (पंढरपुर के समीर), समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्रीनरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतरित होकर उसे पावन बनाया. साई बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया. अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे. उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना कठिन है. शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे. वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे. दान–वीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे. सदा आत्मस्वरुप में मग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था. अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं सकता था. उनका हृदय शीशे के सदृश उज्ज्वल था. उनके मुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी. अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे. मान–अपमान की उन्हें तनिक भी चिंता न थी. वे निर्भय होकर कर उपदेश देते. भांति–भांति के लोंगो से मिल–जुलकर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते कव्वालियां भी सुनते थे. यह सब करते हुए भी उनकी समाधि भंग नहीं होती थी. अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर था. जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे. उनका अन्त:करण प्रशान्त महासागर की तरह शांत था. न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्यप्रणाली का अन्त पा सकता था. कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, लेकिन विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली–भांति ज्ञान था. उनके दरबार का रंग ही निराला था. वे प्रतिदिन अनेक किवदंतियां कहते थे, लेकिन उनकी अखंड शांति तनिक भी विचलित नहीं होती थी. वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रात:, मध्याह और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की ओर वायु–सेवन करने जाते तो भी सदा आत्म–स्थित ही रहते थे. स्वत: सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे. वे विनम्र, दयालु तथा अभिमानरहित थे. उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया. ऐसे थे साईबाबा, जिनके श्री–चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई. उसका महत्व असाधारण हो गया. जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वही स्थान साई बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुआ. शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें साई की चरण–रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस (काशी), महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई. श्री साई का दर्शन करना ही भक्तों का वेदमंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आत्म दर्शन का पथ सुगम होता था. उनका दर्शन ही योग–साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे. उनकी आज्ञा ही वेद सदृश थी. प्रसाद तथा उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी. वे ही राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की और वे ही परम ब्रह्मा थे. वे कभी निराश व हताश नहीं होते थे. वे सदा आत्म–स्थित, चैतन्यघन तथा आनन्द की मंगलमूर्ति थे. कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केन्द्र था, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोकण तक विस्तृत था. साईबाबा की कीर्ति दिन–प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह–जगह से उनके दर्शनार्थ आकर भक्त लाभ उठाने लगे. केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों, उनके चित्त को परम शांति मिल जाती थी. उन्हें उसी आनन्द का अनुभव होता था, जैसा कि पंढरपुर में श्री विठ्ठल के दर्शन से होता है. साई के लिए सब एक समान हैं. वे सबके चित्त को शान्ति प्रदान करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

स्वस्थ रहने के लिए श्रम ज़रूरी है

डॉ. अभय बंग

व्यायाम की आदत न होने से तेज गति से चलने पर(10 मिनट में एक कि.मी.) मेरी हृदयगति 140 तक पहुंच जाती थी. इस कारण इतनी गति यथेष्ट थी. परन्तु आगे जैसे–जैसे व्यायाम की आदत पड़ी और हृदय मजबूत हुआ, वैसे–वैसे हृदय को बहुत तेज होने की जरूरत नहीं पड़ी. उसकी गति 125 पर ही डेरा डाल देती थी. यह हृदय की फिटनेस सुधरने का संकेत था. परन्तु मुझे फिटनेस और बढ़ाने के लिए हृदयगति 80–85 प्रतिशत अर्थात 140 तक बढ़ाने का व्यायाम करना था. फिर मुझे एक नई पद्धति मिली. एरोबिक वॉकिंग अर्थात अतिजल्द चलना. इससे करीब–करीब दौड़ने जितना व्यायाम मिलता था तथा हृदय गति 150 तक पहुंचती थी. छह महीने बाद, नवम्बर 1995 में मैंने शरीर की आगे की परीक्षा ली. साइकिलिंग के लिए निकल पड़ा. पहले दिन में 4 कि.मी. से प्रारम्भ कर, रोज उसे बढ़ाता गया. जिस दिन 10 कि.मी. साइकिल चलाने लगा उस दिन रिश्तेदारों व मित्रों को फोन करके विजय की यह खबर दे डाली. फिर चलते समय थोड़ा–थोड़ा दौड़ने लगा. उस दरमियान मेरी हृदयगति 180 तक आराम से चली जाती थी. गढ़चिरौली के जंगलों में रोज ही मानो मेरा ट्रेडमिल टेस्ट हो रहा था और रोज ही मैं उसमें निरोगी सिद्ध हो रहा था. सच पूछें, तो इतने तीव्र व्यायाम की आवश्यकता नहीं थी. परन्तु अपने हृदय के संबंध में मैं पूर्णत: निश्चिंत होना चाहता था. वह परीक्षा पास हो जाने पर मेरे मन से बोझ उतर गया. मैं निरोगी हो गया हूं. यह मुक्ति की भावना बड़ी सुखदायी थी.

रोजमर्रा की जिंदगी में व्यायाम दाखिल करने के लिए विश्व में अलग–अलग तरीके ढूंढे गए हैं. इंग्लैंड में बच्चों को कार से स्कूल तक पहुंचाना यह पालकों की एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है. बच्चों को भी व्यायाम का अवसर नहीं मिलता. इसलिए हाल ही में एक राष्ट्रीय नारा दिया गया–वाक चिल्ड्रेन सेफली टू स्कूल–बच्चों को सुरक्षित रूप से स्कूल तक चलने दें. भारतीय शहरों में सायंकाल रिक्शा अथवा ऑटोरिक्शा में ठूंसकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह बहुत अच्छी आदत होगी. बच्चों के खेल भी व्यायाम का अच्छा तरीका हैं. बस, इतना आवश्यक है कि जोर खेल पर ही रहे, उसकी भी स्पर्धा बनाकर बच्चों पर एक और स्पर्धा का बोझ न लादा जाए.

व्यायाम के लिए चलने वालों को उत्साहित करने के लिए रास्तों पर जगह–जगह आप कितना चले हैं ऐसे साइन बोर्ड लगाने का चलन आयरलैंड में विकसित हुआ. हॉलैंड सरकार इससे भी आगे निकल गई. यदि लोग मोटर की बजाय साइकिल इस्तेमाल करने लगें, तो व्यायाम भी मिलेगा और शहर में कार पार्किंग की समस्या भी हल हो जाएगी. हॉलैंड में लोग साइकिल खूब इस्तेमाल करने लगे हैं. परन्तु रास्तों पर रखी हुई साइकिलें चोरी होने की समस्याएं सामने आने लगीं. साइकिल चोरी की खोज में पुलिस को साइकिल की कीमत से अधिक खर्च आने लगा. हॉलैंड की सरकार ने इसका बहुत ही सकारात्मक उपाय सोचा. एक दिन अम्स्टरडम शहर में जगह–जगह 4000 नई साइकिलें रख दी गईं और जो चाहे वह ले जा सकता है ऐसी स्वतंत्रता दे दी गई. साइकिलों का उपयोग भी बढ़ गया और चोरियां भी रुक गईं. व्यायाम के लिए घर के बाहर ही चलना या साइकिल चलाना आवश्यक नहीं है. कई शहरों में यह संभव नहीं होता. फिर सिवाय व्यायाम के उसमें से कुछ और निकलता भी नहीं है. पचास–साठ वर्ष पहले विनोबा जी ने अपने तीन गृह देवता नामक लेख में चूल्हा, चक्की और चरखा इन तीन गृहदेवता की आराधना करें, ऐसा सुझाव दिया था. चक्की केवल आटा ही नहीं पीसती घर का आलस्य एवं रोग भी पीसकर फेंक देती है. श्रम बचाकर क्या करोगे? प्राण नहीं बचेंगे. परन्तु प्राण न बचे तो कोई हर्ज नहीं, श्रम बचना चाहिए, हम श्रम से इतना जी चुराने लगे हैं.

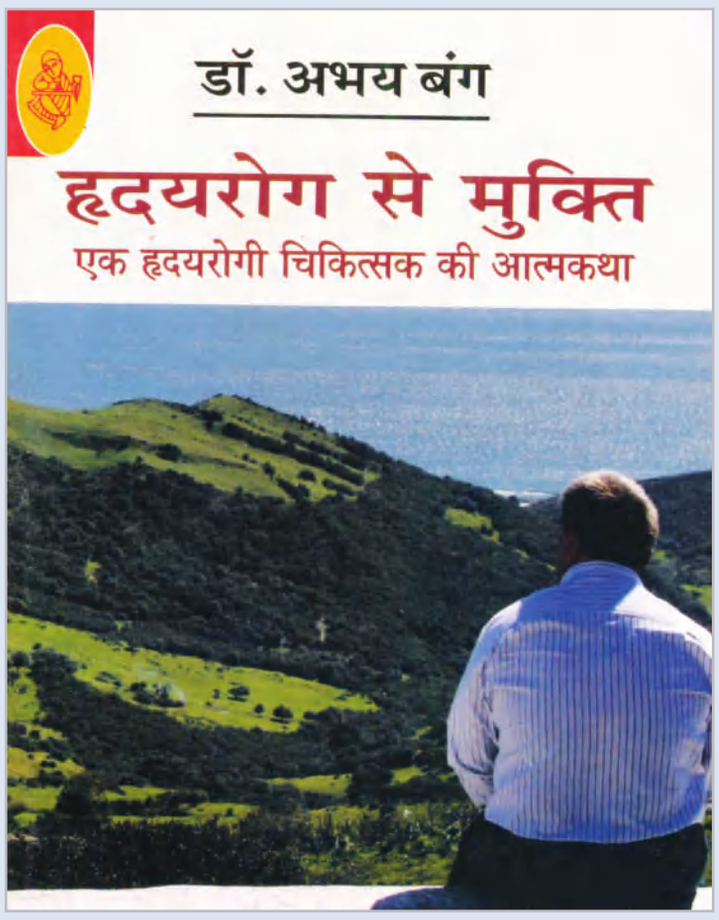

आधुनकि संदर्भ में विनोबा जी की गृहदेवता वाली वैचारिकता में थोड़ा बदलाव करके मुझे झाड़ू, चक्की और कुदाल–ये तीन देवता व्यायाम के लिए दिखाई देते हैं.

झाड़ू से घर आंगन झाड़कर स्वच्छ करना–हल्का व्यायाम, चक्की से परिवार के लिए आटा पीसना–मध्यम व्यायाम और कुदाली अथवा फावड़े से जमीन की सेवा करके पेड़ लगाना–तीव्र व्यायाम है. भरपूर व्यायाम, उपयोगी काम और मन लगाकर करने पर मिलने वाला ध्यान सदृश्य अनुभव.

अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रोज कम–से–कम 30 मिनट व्यायाम करें. तीनो प्रकारों को मिलाकर 30 मिनट करना भी चलेगा.

अब इस विषय में अंतिम सिफारिश पढ़कर लगेगा कि विनोबा जी की है, परन्तु वास्तव में अमेरिका के नेशनल इंस्टीयूट ऑफ हेल्थ की है. जो काम करते हुए मुझे पसीना आए और हल्की सांस आने लगे वह है मध्यम तीव्रता का व्यायाम. ऐसा व्यायाम हर कोई रोज कम–से–कम आधा घंटा करे. घर में रोजमर्रा के गृहसेवा के काम करना उत्तम व्यायाम है. मैं फिर उसी कुड़कवाही के रास्ते पर जंगल में रोज घूमने जाने लगा. साथ में हमारे पांच कुत्ते विशेष रूप से आते थे. मुझसे लाड़ करवाने तथा अपना प्रेम व वफादारी प्रकट करने का उनका यह समय होता है. उगते सूर्य से मेरी भेंट का यह समय होता है. रास्ते का हर पेड़ मेरी बाट जोहता है. पेड़ों के बदलते रंग, रूप–गंध का इन तीन वर्षों में मैंने जितना अनुभव किया, उतना क्या पहले कभी अनुभव किया था? हेनरी थोरो का एक प्रसंग हाल ही में पढ़ने को मिला. अच्छी पोशाक पहनकर उन्हें जल्दी–जल्दी से जंगल की ओर जाते देख एक मित्र ने पूछा, क्यों कहां जा रहे हैं? उस पर अपनी ही धुन में मग्न थोरो ने उत्तर दिया–मुझे जल्दी जाना चाहिए. जंगल के एक पेड़ से मिलने का वादा है. मेरे पेड़ भी क्या कभी मुझसे ऐसे बोलेंगे? परन्तु अभी तो मुझे वे जितना प्रेम देते हैं, वही काफी है.

घूमते समय आंखें आसपास का सौंदर्य निहारतीं. ऋतु बदलतीं. रूप बदलते. फिर मैं साथ कैमरा ले जाने लगा. पलाश, महुआ और कुंभी के खिलते हुए अनेक रूप मैंने अपने कैमरे में उतार लिए. वृझों के लिए विविध रूपों के कई सुंदर फोटो लिए. वे एनलार्ज करके शोधग्राम में सब जगह लगा दिए. अब तो बारहों मास पुष्पदर्शन होने लगा. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

नि:शुल्क सेवा

एक समय की बात है. एक शहर में एक धनी आदमी रहता था. उसकी लंबी–चौड़ी खेती–बाड़ी थी. वह कई तरह के व्यापार करता था. विशाल क्षेत्र में उसके बगीचे फैले हुए थे, जहां पर भांति–भांति के फल लगते थे. उसके कई बगीचों में अनार के पेड़ बहुतायत में थे, जो दक्ष मालियों की देख–रेख में दिन दूनी–रात चौगुनी फल–फूल रहे थे. उस व्यक्ति के पास अपार संपदा थी, किंतु उसका हृदय संकुचित न होकर विशाल था. शिशिर ऋतु आते ही वह अनारों को चांदी की थाली में सजाकर अपने द्वार पर रख देता था. उन थालों पर लिखा होता था कम से कम आप एक तो ले ही लें. मैं आपका स्वागत करता हूं. लोग इधर–उधर से निकलते, किंतु कोई व्यक्ति फल को हाथ तक नहीं लगाता था. तब उस आदमी ने गंभीरतापूर्वक इस पर विचार किया और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा. अगली शिशिर ऋतु में उसने अपने घर के द्वार पर उन चांदी के थालों में एक भी अनार नहीं रखा. बल्कि उन थालों पर उसने बड़े–बड़े अक्षरों में लिखा, हमारे पास अन्य सभी स्थानों से अच्छे अनार मिलेंगे, किंतु उनका मुल्य भी अन्य अनारों के अपेक्षा अधिक लगेगा और तब उसने पाया कि न केवल पास–पड़ोस के, बल्कि दूरस्थ स्थानों के नागरिक भी उन्हें खरीदने के लिए टूट पड़े. कथा का संकेत यह है कि भावना से दी जाने वाली अच्छी वस्तुओं को हेय दृष्टि से देखने की मानसिकता गलत है. वस्तुत: आवश्यकता वह दृष्टि विकसित करने की है, जो भावना और व्यापार में फर्क कर सके और वस्तुओं की गुणवत्ता का ठीक–ठाक निर्धारण कर सके.

शिक्षा: *सभी सस्ती या नि:शुल्क वस्तुएं या सेवाएं निकृष्ट नहीं होतीं.*

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

नोबेल पुरस्कार

> एलिस मुनरो के लेखन की विशेषता है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और स्त्री–पुरुष संबंधों की जटिलता. अपने गर्माहट भरे बेहतर शिल्प और सुंदर कथानक के ज़रिये दुनिया भर में पहचान पाने वाली मुनरो के प्रशंसक पूरे विश्व में हैं. लेकिन चूंकि मुनरो प्रचार से दूर रहती हैं, इसलिए उनके नाम से साथ बेस्टसेलर जैसा तमगा नहीं लगा है.

विवादों से घटती साख़

विवाद से शर्मसार हिंदी साहित्य

हिंदी में साहित्यिक पुरस्कारों को लेकर जिस तरह का विवाद उठ खड़ा हुआ है, वह बेहद चिंताजनक स्थिति है. अनर्गल आरोपों–प्रत्यारोपों से हिंदी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. लमही सम्मान पर उठे विवाद को पीढ़ियों की टकराहट की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है. लमही सम्मान को लेकर उठे शर्मनाक विवाद के बाद हिंदी के कर्ताधर्ताओं की यह ज़िम्मेदारी है कि वो इस वक्त आगे आएं और टुटपुंजिए पुरस्कारों को चिह्नित कर उसके बहिष्कार का उपक्रम करें ताकि हिंदी में पुरस्कारों के कारोबार पर रोक लगाई जा सके.

अनंत विजय

हिंदी साहित्य में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे छोटे से पुरस्कार लमही सम्मान को लेकर इन दिनों शर्मनाक विमर्श हो रहा है. पुरस्कार के ऐलान, अर्पण से लेकर उसके लौटाने तक बेहद निर्लज्जता के साथ जिस तरह का खेल खेला जा रहा है उसने तो राजनीतिक बेशर्मी को भी पीछे छोड़ दिया है. परोक्ष और प्रत्यक्ष आरोपों–प्रत्यारोपों से हिंदी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. लमही सम्मान पर उठे विवाद को पीढ़ियों की टकराहट की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है. इस कोशिश में वरिष्ठ लेखकों के बारे में उलूल–जुलूल और अनर्गल प्रलाप शुरू हो गए हैं. व्यक्तिगत टिप्पणियों से हिंदी साहित्य शर्मसार हो रहा है. व्यक्तिगत खुंदक को मंच मुहैया करवाया है सोशल नेटवर्किंग साइट्स की अराजक आज़ादी ने. अगर फेसबुक पर इस तरह की अराजक आज़ादी जारी रही और लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए कोई औजार ढूंढ लाए. और तब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी का नारा लगाते रह जाएं. पुरस्कार की इस साहित्यिक लड़ाई पर व्यक्तिगत कुंठा बुरी तरह से हावी है. न वरिष्ठों का सम्मान और न ही ख़ुद की प्रतिष्ठा का ख़्याल. हालात यह हो गए हैं कि फेसबुक पर गाली–गलौज से जो लाइक्स मिल रहे हैं, उससे लोग गदगद हो रहे हैं.

आज की इस हालत के लिए हिंदी के अधिकांश लेखकों की पुरस्कार पिपासा ज़िम्मेदार है. हिंदी साहित्य में तक़रीबन चालीस पचास खुदरा पुरस्कार दिए जा रहे हैं. अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार के थोक साहित्यिक पुरस्कारों को नज़रअंदाज़ भी कर दें तो क्योंकि वहां तो पुरस्कार की बजाए रेवड़ी बंटती है जो अपनों अपनों को मिलती है. कुछ खुदरा पुरस्कार तो ऐसे हैं जो बाक़ायदा लेखकों से एक निश्चित राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन मांगते हैं. हिंदी के पुरस्कार पिपासु लेखक बड़ी संख्या में इस तरह के पुरस्कारों के लिए आवेदन भेजते हैं. कहना नहीं होगा कि हिंदी के ज़्यादातर नए लेखक/लेखिकाओं में हल्का काम करके भी प्रसिद्धि की ललक ऐसे पुरस्कारों को प्राणवायु प्रदान करती है. कई पुरस्कारों की धनराशि तो पांच से दस हज़ार रुपये तक है, लेकिन उन पुरस्कारों की आड़ में कई तरह के विमर्श आकार लेते हैं . सवाल यह उठता है कि हिंदी के लेखकों में पुरस्कार को लेकर इतनी भूख क्यों है. क्यों कर वो हज़ार दो हज़ार के पुरस्कार के लिए सारे दंद–फंद और पुरस्कार देने वालों की चापलूसी तक पर उतारू हैं. इसकी पड़ताल करने पर बेहद निराशाजनक तस्वीर दिखाई देती है. हिंदी के लेखकों में मेहनत करने की प्रवृत्ति का लागातार क्षय हो रहा है. बगैर व्यापक शोध के और कल्पना के आधार पर यथार्थ लिखने की प्रवृत्ति ने साहित्य का बड़ा नुकसान किया है. विचारधारा वाले साहित्य ने तो नुकसान किया ही. नई पीढ़ी में एक और प्रवृत्ति रेखांकित की जा सकती है वह है– जल्दबाजी, धैर्य की कमी, कम वक्त में सारा आकाश छेक लेने की तमन्ना और वह भी किसी क़ीमत पर. सुरेन्द्र वर्मा के उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका सिलबिल की तरह जो सफलता के शिखर पर पहुंचने की हड़बड़ी में सभी तरह के समझौते करती है. इस चाहत का फ़ायदा उठाकर कुछ साहित्यिक कारोबारी पुरस्कारों में संभावनाएं तलाशते हैं. हिंदी के नए लेखक शुरू से ही आसमान पर चढ़ने की तमन्ना पाले बैठे रहते हैं. महात्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है. हर किसी को महात्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन उसमें अति के जुड़ने से जो ख़तरनाक रोमांच जुड़ता है, वह बेहद ख़तरनाक है. पुरस्कार के कारोबारी इस प्रवृत्ति को बढ़ाकर ख़तरा और बढ़ा देते हैं.

दरअसल, हिंदी में पुरस्कारों की महत्ता और प्रतिष्ठा लगातार कम होती जा रही है. हिंदी में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य अकादमी सम्मान को माना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक से जिस तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बंदरबांट हुई है, उससे अकादमी पुरस्कारों की साख़ पर बट्टा लगा है. दो हज़ार एक से लेकर दो हज़ार दस तक की साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए बनाई गई पुस्तकों की आधार सूची पर नज़र डालने से यह बात और साफ़ हो जाती है. दो हज़ार तीन में जब कमलेश्वर को उनके उपन्यास–कितने पाकिस्तान–पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था तो उस वक्त की आधार सूची में इकतीस लेखकों के नाम थे, जिसे मृदुला गर्ग ने तैयार किया था. इस सूची में तेजिन्दर, गौरीनाथ, हरि भटनागर, संजना कौल और जयनंदन आदि के नाम शामिल थे. तब अकादमी पर यह आरोप लगा था कि कमलेश्वर का नाम पहले से तय था. दो हज़ार चार में जब वरिष्ठ कवि वीरेन डंगवाल को उनके कविता संग्रह दुश्चक्र में स्रष्टा पर पुरस्कार मिला तो शक का कोहरा और घना हो गया था. उस वक्त हिंदी के संयोजक थे गिरिराज किशोर और आधार सूची तैयार की थी कहानीकार प्रियंवद ने. हद तो तब हो गई थी जब निर्णायक मंडल के तीन सदस्यों में से दो कमलेश्वर और श्रीलाल शुक्ल बैठक में उपस्थित ही नहीं हो सके थे.

अपनी टिप्पणी में निर्णायक मंडल के तीसरे सदस्य से. रा. यात्री ने लिखा– दुश्चक्र में स्रष्टा– काव्य कृति को हम सभी निर्णायक मंडल के सदस्य एक समान प्रथम वरीयता देते हैं और साहित्य अकादमी के दो हज़ार चार के पुरस्कार के लिए सहर्ष प्रस्तुत करते हैं. लेकिन संस्तुति पत्र पर सिर्फ़ उनके ही दस्तख़त थे. उसी जगह हिंदी भाषा के तत्कालीन संयोजक गिरिराज किशोर ने लिखा–श्रीलाल शुक्ल एवं कमलेश्वर जी उपस्थित नहीं हो सके. उन्होंने अपनी लिखित संस्तुति बंद लिफ़ाफ़े में भेजी है. श्रीलाल जी ने ज्यूरी के उपस्थित सदस्य से. रा. यात्री से फोन पर लंबी बातकर दुश्चक्र में स्रष्टा को 2004 के पुरस्कार के लिए समर्थन दिया. हालांकि, साहित्य अकादमी के दस्तावेजों में श्रीलाल जी की संस्तुति मौजूद नहीं है. कमलेश्वर का बीस दिसंबर का ख़त है जो इक्कीस दिसंबर की बैठक के पहले प्राप्त हो गया था. वीरेन डंगवाल की प्रतिष्ठा पर किसी को कोई शक नहीं है. वो साहित्य अकादमी पुरस्कार डिजर्व भी करते थे लेकिन जिस अफरा–तफरी में पुरस्कार का ऐलान किया गया, उससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई थी. कालांतर में अकादमी पुरस्कारों के चयन को लेकर कई गंभीर आरोप लगे. नतीजा यह हुआ कि अकादमी पुरस्कार को हिंदी जगत में उस तरह का उत्साह नहीं रहा जो नब्बे के दशक में हुआ करता था.

लमही सम्मान को लेकर उठे शर्मनाक विवाद के बाद हिंदी के कर्ताधर्ताओं की यह ज़िम्मेदारी है कि वो इस वक्त आगे आएं और टुटपुंजिए पुरस्कारों को चिह्नित कर उसके बहिष्कार का उपक्रम करें ताकि हिंदी से पुरस्कारों के कारोबार पर रोक लगाई जा सके. अंत में मैं कात्यायनी की कविता से ख़त्म करूंगा– दो कवि थे/बचे हुए अंत तक/वे भी पुरस्कृत हो गए/इस वर्ष/इस तरह जितने कवि थे/सभी पुरस्कृत हुए/और कविता ने खो दिया/सबका विश्वास. चुनौती इसी विश्वास को बचाने की है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

मैं कहीं नहीं हूं

अपराजिता मिश्रा

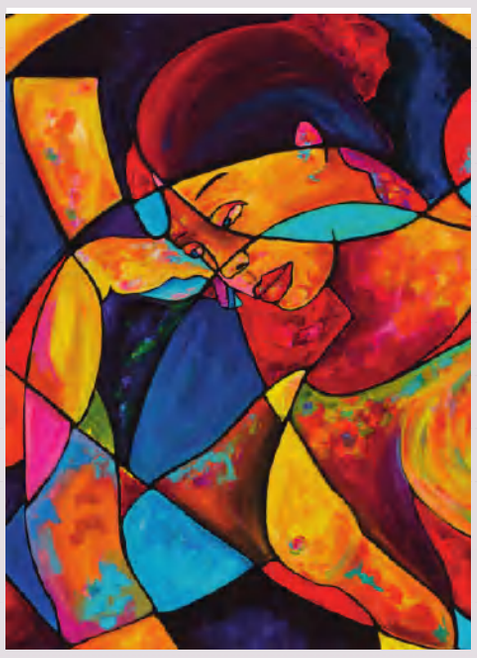

मैं सपनों में जीने वाली लड़की थी
अपना दामन सजा रखा था
तमाम छोटे-छोटे, सितारों से टांककर
वक़्त ने चाल चली और तुम निरपेक्ष रहे
वे सपने मर गए अचानक
जाने कब, कि मुझे ख़बर ही नहीं
सब के कुचले गए बेरहमी से
अब मैं हूं पर
मेरे होने का एहसास नहीं है
संभावना भी नहीं
मेरे बाहर, भीतर कुछ मर गया
जो अब नहीं लौट सकता
जो कुछ शेष देखते हो
वो उलझा हुआ, द्वंद्व में सना हुआ
अधूरा हिस्सा है मेरा
अब मैं ही उसे नहीं पहचानती
तुम मेरे दुःख को अपनी मात मत समझना
मै थी ही कब, मैं कभी नहीं थी
मैं अब भी नहीं हूं...

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
गांधी और नेहरू भारतीय सर्वधर्मसमभावी राष्ट्रवाद की साझी विरासत	प्रो. दीपक मलिक
प्रकाशक	**मूल्य**
राजकमल प्रकाशन	400 रुपये

प्रो. दीपक मलिक ने *गांधी और नेहरू: भारतीय सर्वधर्मसमभावी राष्ट्रवाद की साझी विरासत* शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने गांधी और नेहरू की विचारधारा को रेखांकित किया है. गांधी विमर्श तो भारत समेत पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन नेहरू के बारे में इस दौर में बहुत कम लिखा जा रहा है. ऐसे में गांधी ओर नेहरू पर साझा विमर्श एक मौजूं सिलसिला है. तेरह अध्यायों में लिखी गई इस पुस्तक में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी और नेहरू की विचारधारा पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला गया है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक चर्चा

लघु कथाओं की मल्लिका को नोबेल

कृष्णकांत

कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो को साहित्य का नोबेल देने की घोषणा की गई है. बेहद प्रभावशाली लघुकथाएं लिखने वाली मुनरो, कनाडा का चेखव और लघु कहानी की मल्लिका आदि नामों से जानी जाती हैं. यह पहली बार है जब किसी कनाडाई नागरिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है. नोबेल के लिए मुनरो के नाम की घोषणा करते हुए नोबेल पुरस्कार समिति ने उन्हें समकालीन लघु कहानी का सिद्धहस्त रचनाकार कहा है.

इस बार साहित्य का नोबेल लघु कथा की मल्लिका के नाम से मशहूर कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो को दिया जा रहा है. दुनिया भर में साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार के तहत 12 लाख डॉलर यानी लगभग साढ़े सात करोड़ रुपये दिए जाते हैं. नोबेल पुरस्कार समिति ने मुनरो को समकालीन लघु कहानी का सिद्धहस्त रचनाकार कहा है. कुछ आलोचक मुनरो को कनाडा का एंटन चेखव कहते हैं. 82 वर्षीय मुनरो बहुत छोटी उम्र से ही कहानियां लिख रही हैं. मुनरो ऐसी लेखिका हैं जो मीडिया के सामने बहुत कम आती हैं और सिर्फ़ चुपचाप रचते रहने में विश्वास करती हैं. आगामी दस दिसंबर को स्टॉकहोम में एक कार्यक्रम आयोजित कर मुनरो को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.

10 जुलाई, 1931 को कनाडा के विंघम में जन्मी एलिस मुनरो ने 1950 में लिखना शुरू किया था. इसी साल उनकी कहानी *द डाइमेंशंस ऑफ ए शेडो* प्रकाशित हुई थी. उनका पहला कहानी संग्रह *डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स* 1968 में प्रकाशित हुआ, जिसके लिए उन्हें कनाडा का सर्वोच्च सम्मान द गर्वनर जनरल अवॉर्ड दिया गया था. यह सम्मान उन्हें तीन बार मिल चुका है. पिछले साल उनका नया कहानी संग्रह *डियर लाइफ* प्रकाशित हुआ. 2006 में मुनरो की एक लघुकथा पर *अवे फ्रॉम हर* नाम से फिल्म भी बनी है. मुनरो को 2009 में मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है. मुनरो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली कनाडाई नागरिक हैं.

साहित्य का नोबेल 1901 से लेकर अब तक 109 लेखकों को दिया जा चुका है, जिनमें से मुनरो के अलावा 12 अन्य महिलाओं को मिला है. 1909 में यह पुरस्कार जीतने वाली स्वीडन की सेल्मा लागेर्लाफ पहली महिला थीं. सात बार ऐसा हुआ है जब यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि किसी को उपयुक्त नहीं पाया गया था. यह पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें *द जंगल बुक* के लिए 1907 नोबेल दिया गया था. उस समय उनकी उम्र मात्र 42 साल थी. 1913 में भारतीय कवि रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध रचना *गीतांजलि* के लिए साहित्य का नोबेल मिला था. टैगोर नोबेल पाने वाले एकमात्र भारतीय लेखक हैं.

स्वीडिश अकादमी ने एलिस मुनरो को पुरस्कार देने की घोषणा के दौरान कहा कि मुनरो अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, स्वीडिश, स्पेनिश और जर्मन में भी लिखती हैं. मुनरो की कहानियां अक्सर गांव–कस्बों के माहौल पर आधारित होती हैं. उन्होंने अस्तित्व की सामाजिक स्वीकार्यता का संघर्ष, तनावपूर्ण संबंधों और नैतिक द्वंद्व के परिवेश को बख़ूबी रचा है. यह ऐसी समस्याएं जो पीढ़ियों के अंतर और महत्वाकांक्षा के टकराव से पैदा होती हैं. वह सिद्धहस्त किस्सागो हैं, उन्होंने पात्रों की रचना स्पष्टता और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के धरातल पर की. अपने एक साक्षात्कार में एलिस मुनरो ने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि मैं लेखन में इसलिए कामयाब रही, क्योंकि मेरे पास और कोई प्रतिभा नहीं थी. मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूं. मैं एक अच्छी पत्नी थी, लेकिन इतनी महान भी नहीं थी. लेखन से अलग कभी किसी चीज़ में मेरी दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए कभी कोई चीज़ रास्ते में नहीं आई.

एलिस मुनरो का रचना संसार

डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वोमेन, समथिंग आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू, हू डू यू थिंक यू आर, बेगर मेड, द मून्स ऑफ जूपिटर, द प्रोग्रेस ऑफ लव, फ्रेंड ऑफ माई यूथ, ओपेन सीक्रेट, द लव ऑफ अ गुड वोमेन, क्वीन: अ स्टोरी, रनअवे, द व्यू फ्रॉम कैसल रॉक, टू मच हैपीनेस, डियर लाइफ

एलिस मुनरो के लेखन की विशेषता है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और स्त्री–पुरुष संबंधों की जटिलता. अपने गर्माहट भरे बेहतर शिल्प और सुंदर कथानक के ज़रिये दुनिया भर में पहचान पाने वाली मुनरो के प्रशंसक पूरे विश्व में हैं. लेकिन चूंकि मुनरो प्रचार से दूर रहती हैं, इसलिए उनके नाम से साथ बेस्टसेलर जैसा तमगा नहीं लगा है. कनाडाई लेखिका मार्ग्रेट ऑटवुड ने मुनरो के बारे में हाल ही में कहा था, लेखक समुदाय में मुनरो का नाम बहुत दबे स्वर में लिया जाता है लेकिन बहुत से लेखकों की तरह, जो लेखकों के लेखक समझे जाते हैं, मुनरो की यथार्थपूर्ण–सी दिखने वाली स्पष्टवादी और गल्प आधारित कहानियों ने अपना पाठक वर्ग तैयार किया है, बावजूद इसके कि वे सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा नहीं दिखतीं और साक्षात्कार देने से इन्कार करती हैं.

ब्रिटिश अख़बार द गार्जियन ने मुनरो की डियर लाइफ की समीक्षा में लिखा, मुनरो की कहानियां स्मार्ट और जवान महिलाओं से भरी होती हैं जो बहुत ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से मर्दों की हावी होने की प्रवृत्ति का अवलोकन करती हैं. हालांकि, मुनरो पुरुषों का भी बख़ूबी चित्रण करती हैं. उन्होंने अपनी कहानियों में ज़्यादातर ऐसी युवा महिलाओं का चित्रण किया है, जो प्रेम, शादी और अन्य प्रसंगों में ठगी जाती हैं. एलिस मुनरो ने द न्यूयॉर्कर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे जीवन का मुख्य किरदार मेरी मां हैं, जो कि एक बहादुर महिला थीं, जिनका जीवन बहुत दुखद था. पुरस्कार मिलने के बाद मुनरो ने कहा, मैं दौड़ में थी यह तो पता था लेकिन मुझे नोबेल के लिए चुना जाना मेरे लिए एक आश्चर्य है. यह एकदम अप्रत्याशित है. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. मुनरो को अपने सम्मानित किए जाने पर भले न विश्वास हो रहा हो, लेकिन उनके प्रशंसक स्वीडिश अकादमी के इस निर्णय से बहुत ख़ुश हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मेहरनामा में शहजादा सलीम (जो बाद में बादशाह जहांगीर बने) और मेहरुन्निसा (नूरजहां) की प्रेम कहानी को दिखाया गया. इस प्ले का सेटअप देखकर ऐसा लग रहा था, मानो आप उसी काल में आ गए हों. इस प्ले का निर्देशन जाने–माने रंगमंच निर्देशक आमिर रजा हुसैन और उनकी पत्नी विराट हुसैन ने किया. मेहरनामा बादशाह जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां की प्रेम कहानी पर आधारित है.

फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ एचटीसी का फोन

एचटीसी ने वन मैक्स नाम से 5.9 इंच डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला स्मार्टफोन पेश किया है. यह फैबलेट (फोन+टैबलेट) सैमसंग गैलक्सी नोट 3, एलजी जी2 और नोकिया के आने वाले फैबलेट को टक्कर देगा. कंपनी ने अभी इसकी कीमत नहीं बताई है, लेकिन एशिया और यूरोप में यह फोन लॉन्च हो गया है, जबकि अमेरिका में इसे नवंबर में उतारा जाएगा. एचटीसी वन मैक्स में 368 पीपीआई (पिक्सल्स/इंच) पिक्सल डेंसिटी वाला फुल एचडी डिस्प्ले है. यह एचटीसी वन और वन मिनी जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका बैक कवर आसानी से अलग किया जा सकता है. इसमें 1.7 गीगाहर्ट्ज क्वॉड–कोर स्नैपड्रैगन 600 प्रोसेसर और 2 जीबी रैम है. यह एचटीसी सेंस यूज़र इंटरफेस के साथ ऐंड्रॉयड 4.3 जेली बीन पर चलेगा. वन मैक्स में पीछे की तरफ 4 एमपी अल्ट्रापिक्सल्स कैमरा है.

हालांकि इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टैबिलाइजेशन नहीं है, जो कि एचटीसी वन में है. इसमें 16 और 32 जीबी इंटरनल स्टॉरेज के ऑप्शंस हैं. 64 जीबी तक का माइक्रो–एसडी कार्ड लगाया जा सकता है. इसमें ड्यूल बूमसाउंड स्पीकर्स और इंफ्रारेड ब्लास्टर है, लेकिन बीट्स ऑडियो साउंड टेक्नोलॉजी नहीं है. एचटीसी वन में फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे की तरफ कैमरे के नीचे है. इस पर उंगली स्वाइप करके फोन अनलॉक किया जा सकता है. कुछ दिन पहले एप्पल ने भी आईफोन 5 एस में फिंगरप्रिंट स्कैनर पेश किया गया है. फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला पहला फोन मोटोरोला अट्रिक्स था. एचटीसी वन सीरीज गैजेट प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है. ऐसे में खास खूबियों वाले नये स्मार्टफोन का आना एक और खुशखबरी साबित हो सकती है. इस फोन की सीधी टक्कर सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 और एप्पल के आईफोन 5 एस से होगा. यह सिर्फ सैमसंग के लिए ही नहीं, नया एचटीसी वन मैक्स एप्पल के लिए भी टक्कर देने वाला साबित हो सकता है. इसके पहले मॉडल्स में एक खास फीचर नहीं था, जो खबरों के मुताबिक नये वन मैक्स में है. एप्पल आईफोन 5 एस का सबसे खास फीचर –फिंगरप्रिंट स्कैनर अब नये एचटीसी वन मैक्स में मिलेगा. यह फीचर लेटेस्ट आईफोन में इंट्रोड्यूस किया गया था. अब यह फीचर नये एचटीसी में भी मिलेगा.

यह एप्पल को टक्कर देने के लिए कंपनी का सबसे अहम कदम साबित हो सकता है. एचटीसी के पेज के मुताबिक नये वन मैक्स में कैमरा के साथ बीएसआई सेंसर लगे होंगे. इन सेंसर की वजह से फोटो क्वालिटी काफी अच्छी होगी. इसी के साथ एलईडी फ्लैश कम लाइट में भी फोटो खींचने के लिए लगाया गया है. अगर नये फीचर की बात करें तो इस फोन की इमेजचिप (जिसके द्वारा फोटो ली जाती है) में स्मार्ट फ्लैश है. इसका मतलब 5 लेवल तक फ्लैश की ताकत बढ़ गई है. यह यकीनन शानदार फोटो क्वालिटी देगा. ■

स्पाइस पिनैकल स्टाइलस

स्पाइस पिनैकल स्टाइलस (एमआई-550) 15,999 रुपये में लॉन्च किया गया है. ड्यूल सिम सपोर्ट करने वाला यह फैबलेट (फोन+टैबलेट) स्पाइस की उस पिनैकल सीरीज में आया है, जिसमें पहले से पिनैकल एफएचडी, पिनैकल प्रो और पिनैकल एमआई-530 मौजूद हैं. स्पाइस पिनैकल प्रो स्टाइलस में 720-1280 पिक्सल्स रेजॉलूशन वाला 5.5 इंच का टीएफटी एलसीडी एचडी डिस्प्ले है. यह ऐंड्रॉयड 4.2 जेली बीन पर चलता है. इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉड-कोर प्रोसेसर और 2 जीबी रैम है. 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है और 32 जीबी तक का माइक्रो-एसडी कार्ड लगाया जा सकता है. इसके दोनों सिम 3जी सपोर्ट करते हैं. यह फीचर ड्यूल सिम वाले ज्यादातर डिवाइस में नहीं मिलता. पीछे की तरफ ड्यूल-एलसीडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल्स का कैमरा है. 2 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा है. बैटरी 2,500 एमएच की है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जीपीआरएस, एज, 3जी, ब्लूटुथ, वाई-फाई और जीपीएस शामिल हैं. जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस स्मार्टफोन के साथ एक स्टाइलस भी है. स्पाइस इस फोन के साथ एवरनोट प्रीमियम का एक साल का सब्स्क्रिप्शन मुफ्त में दे रही है, जिसकी कीमत 3000 रुपये है. कुछ दिन पहले ही स्पाइस ने स्मार्ट फ्लो पेस 3 नाम का बजट फैबलेट 7,499 रुपये में लॉन्च किया था. ■

खाना बनाना हुआ आसान

खाना बनाना अब सिर्फ महिलाओं का काम नहीं रह गया है. जहां यह एक जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ खाना बनाना लोगों का पसंदीदा काम भी होता है. हालांकि अकेले रहने वाले नौकरी-पेशा और पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी काफी है, जिन्हें खुद ही खाना बनाना पड़ता है. आज के युवा पर्यावरण के प्रति भी काफी सजग हैं. ऐसे में उनके लिए देश के सबसे पुराने ब्रांड वर्ष 1986 में स्थापित विनोद कुकवेयर ने माइक्रो कंप्यूटर इंडक्शन कुकटॉप आइएनसीओ-004 पेश की है, जिससे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होगी. इस आंच रहित कुकिंग उपकरण में भारतीय मेन्यू के सभी फंक्शन मौजूद हैं. इसके अंदर विशुद्ध कॉपर क्वायल का प्रयोग किया गया है, जिससे खाना तेजी से पकता है. विनोद के कुकटॉप में आठ प्रिसेट कुकिंग मोड्स दिया गया है, जो कि इंडक्शन को पानी उबालने, दूध गर्म करने, फ्राय करने, पकाने, हॉट पॉट में सक्षम बनाते हैं. आइएनसीओ-004 में कुकिंग सर्फेस के रूप में सिरेमिक प्लेट का उपयोग किया गया है, जिससे इसे साफ करना बेहद आसान है. माइक्रो कंप्यूटर इंडक्शन कुकटॉप की पेशकश कंप्यूटर-नियंत्रित परिचालन, विभिन्न खाद्य पदार्थों के समय एवं तापमान के समायोजन के साथ की गई है. यही नहीं, इसमें उपयोग करने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिल्ट-इन ऑटोमेटिक पॉवर ऑफ की भी सुविधा है. विनोद कुकवेयर के संस्थापक सुनील अग्रवाल ने इस नये उपकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा नया माइक्रो कंप्यूटर इंडक्शन कुकटॉप आइएनसीओ-004 डीईकेआरए द्वारा प्रमाणित है (आइईसीइइ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड और ईयू की सीई मार्किंग). यह नई तकनीक और सर्वोत्कृष्ट उपयोगिता का उचित मिश्रण है. पहली बार हमने ऐसा कुक टॉप बनाया है, जो कीटाणुओं को भी दूर भगाएगा. स्वच्छता पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए यह विशेषता बेहद अहम होगी. इसमें बिजली बहुत कम खर्च होती है और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है. यह विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए समय एवं तापमान समायोजित करता है और खुद बंद भी हो जाता है. ग्राहकों के लिए 12 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध आइएनसीओ-004 की कीमत 4,930 रुपये है. आइएन-सीओ-004 इस श्रेणी के अन्य उत्पादों की तुलना में विनोद कुकवेयर बेहतर होने के साथ-साथ खाना पकाने के अनुभव को आनंददायक बनाने का वादा करता है. ■

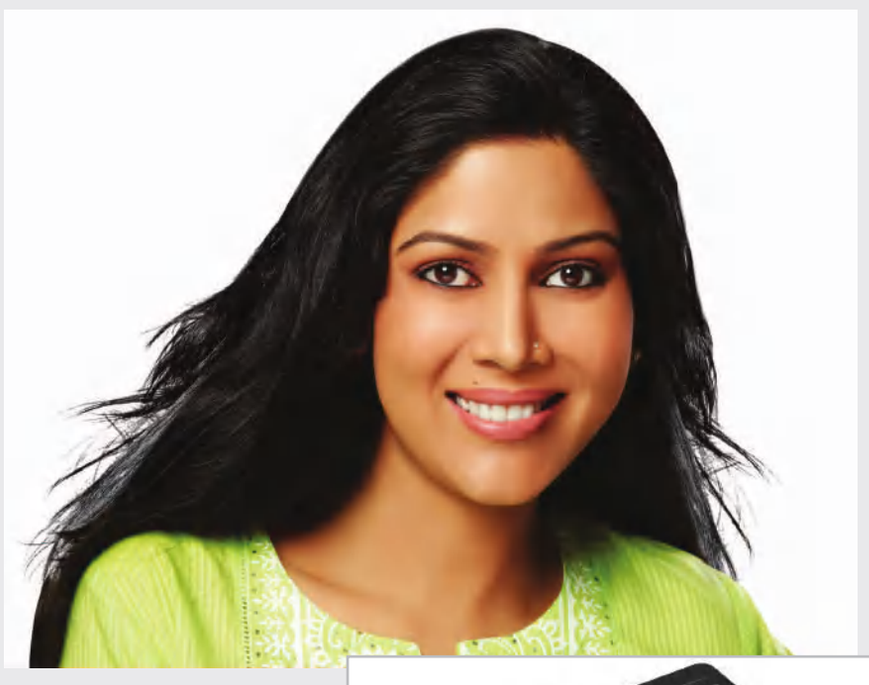

ज्यादा सीटों वाली वैगनआर

भारतीय बाजार में अगले साल 7 सीटर एमपीवी कार लॉन्च होने वाली हैं. कई कार कंपनियां तो अपनी-अपनी कॉन्सेप्ट कारों का प्रदर्शन भी कर चुकी हैं. काफी समय से सुजुकी की वैगनआर 7 सीटर एमपीवी कॉन्सेप्ट की चर्चा चल रही थी. फिलहाल अब कंपनी ने इस कार से पर्दा उठा दिया है. हाल ही में इंडोनेशिया इंटरनेशनल मोटर शो 2013 में कंपनी ने अपनी 7 सीट की वैगनआर को शोकेस किया है. इस कार के अंदर बैठने वालों के लिए सीट की तीन कतारें बनाई गई हैं. ये काफी कुछ डैटसन गो+ की ही तरह दिखाई देती है, लेकिन वैगनआर की तीसरी सीट को डैटसन गो+ के मुकाबले छोटा बताया जा रहा है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

पॉवरबज की 5वीं वर्षगांठ पर

मेहरनामा का मंचन

मशहूर वेबसाइट पॉवरबज ने अपनी पांचवीं सालगिरह के उपलक्ष्य में मशहूर प्ले मेहरनामा का मंचन किया. इस मौके पर 300 से अधिक ब्यूरोक्रेट्स ने हिस्सा लिया. मेहरनामा में शहजादा सलीम (जो बाद में बादशाह जहांगीर बने) और मेहरून्निसा (नूरजहां) की प्रेम कहानी को दिखाया गया. इस प्ले का सेटअप देखकर ऐसा लग रहा था, मानो आप उसी काल में आ गए हों. इस प्ले का निर्देशन जाने-माने रंगमंच निर्देशक आमिर रजा हुसैन और उनकी पत्नी विराट हुसैन ने किया. मेहरनामा बादशाह जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां की प्रेम कहानी पर आधारित है. इस नाटक में तीन पीढ़ियों को दिखाया गया, जिसमें मुगल-ए-आजम अकबर से लेकर शाहजहां तक शामिल हैं. यह कहानी युद्ध और प्रेम पर आधारित है. पॉवरबज डॉट इन की नींव 2008 में रखी गई थी और इसका मकसद इंडियन ब्यूरोक्रेसी में होने वाली हर घटना को पूरे खोजपरक रिपोर्टिंग के जरिये उजागर करना है. यह वेबसाइट 2010 में चर्चा में तब आई, जब इसने नीरा राडिया के टेप को 2जी स्कैम मामले में उजागर किया. पॉवरबज के सफलतम पांच साल पूरे होने पर वेबसाइट के एडिटर इन चीफ अंजुम जैदी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि हमने काफी अच्छा काम किया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस वेबसाइट को और विस्तार मिलेगा. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

आमतौर पर खिलाड़ी संन्यास के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से खेल से जुड़े रहना चाहते हैं. वे सामान्य तौर पर कोच, कॉमेंट्रेटर, अंपायर या खेल प्रशासक के रूप में खेल को आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी लेते हैं, ताकि खेल को और भावी पीढ़ी के खिलाड़ियों को आने वाले समय के अनुरूप तैयार किया जा सके और खेल की लोकप्रियता में और इज़ाफा किया जा सके.

क्रिकेट के आगे जहां और भी है...

दुनिया में हर खिलाड़ी को एक न एक दिन संन्यास की हक़ीकत से रू-ब-रू होना पड़ता है. संन्यास का निर्णय ज़िंदगी के लिए सबसे कठिन लम्हा होता है. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ज़ेहन में भी इस निर्णय के दौरान सवाल था कि क्रिकेट के बिना मैं कैसे ज़िंदा रहूंगा. पहले भी संन्यास के बाद खिलाड़ियों ने क्रिकेट से इतर कई क्षेत्रों में काम करना शुरू किया और यह बात सिद्ध की कि क्रिकेट के आगे जहां और भी है...

फोटो-सुनील मल्होत्रा

नवीन चौहान

आज से दो-तीन दशक पहले क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी रोजी-रोटी और परिवार के भरण-पोषण के लिए अन्य संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था. जिन खेलों में व्यावसायिकता का प्रवेश हुआ, उन खेलों के खिलाड़ियों के अलावा अन्य खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को तंगहाल जीवन जीना पड़ता था, लेकिन अब समय बदल गया है. अब खिलाड़ी अपने खेल करियर के दौरान ही भविष्य की योजनाओं पर काम करना शुरू कर देते हैं. ऐसे खिलाड़ियों की सूची बहुत लंबी है.

25 साल तक देश का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहे हैं. लोगों के ज़ेहन में सचिन को लेकर बहुत उत्सुकता है कि वे आगे चलकर क्या करेंगे. सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर के बाद के लिए तैयारियां एक से डेढ़ दशक पहले ही शुरू कर दी थी. सचिन ने संजय नारंग के साथ मिलकर मुंबई के कोलाबा में तेंदुलकर्स नाम के रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी. तब सचिन द्वारा तेंदुलकर्स रेस्टोरेंट की शुरुआत करने का उद्देश्य अपने और फैंस के बीच की दूरी को कम करना था. एक बिजनेसमैन के रूप में सचिन ने हाल ही में वीरेंद्र सहवाग और स्पोर्ट्स मेकेनिक्स के साथ मिलकर तैयार किए गए स्पोर्ट्स एजुकेशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसका मुख्य लक्ष्य स्कूली बच्चों को विश्वस्तरीय शारीरिक और खेल शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे कि भविष्य में भारत का खेल शक्ति बनने में मदद मिल सके.

आमतौर पर खिलाड़ी संन्यास के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से खेल से जुड़ा रहना चाहते हैं. सामान्य तौर पर कोच, कॉमेंट्रेटर, अंपायर या खेल प्रशासक के रूप में खेल को आगे ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं, ताकि खेल को और भावी पीढ़ी के खिलाड़ियों को आने वाले समय के अनुरूप तैयार किया जा सके. इसके साथ ही खेल की लोकप्रियता में और इज़ाफा किया जा सके. जिस तरह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने पहले मैच रेफरी के रूप में काम किया. अनिल कुंबले के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद दोनों ने कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ा, जिसमें कुंबले अध्यक्ष और श्रीनाथ सचिव चुने गए. पूर्व भारतीय कप्तान एस वेंकटराघवन, श्रीलंका के कुमार धर्मसेना, अशोक डिसिल्वा, पाकिस्तान के अहसान रजा, इंग्लैंड के मार्क बेंसन, ऑस्ट्रेलिया के पॉल रैफल जैसे खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद अंपायरिंग को नये करियर के रूप में चुना.

बहुत से क्रिकेट खिलाड़ी संन्यास लेने के बाद राजनीति की ओर रुख करते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को यह मुकाम खेल में रहते हुए ही हासिल हो गया. सचिन तेंदुलकर को पिछले साल भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया. सचिन ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद कहा था कि अब मैं बहुत ही सुखद स्थिति में पहुंच गया हूं. अब मैं क्रिकेट के अलावा देश में अन्य खेलों के विकास में मदद कर सकूंगा. मुझे इस बात से बेहद खुशी होगी कि मुझे एक ऐसे सख़्श के रूप में याद किया जाए, जिसने देश में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के विकास में अपना यो-गदान दिया. क्रिकेट के मैदान से राजनीति में आने वाले खिलाड़ियों में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है. इमरान संन्यास लेने के तत्काल बाद पाकिस्तान की सक्रिय राजनीति में उतर गए. उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ नाम की राजनीतिक पार्टी का गठन किया. उन्हें तत्काल राजनीति के मैदान में अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली, लेकिन दो दशक बाद वे पाकिस्तानी राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं. वर्तमान में तीन भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद, मोहम्मद अज-हरुद्दीन और नवजोत सिंह सिद्धू लोकसभा सांसद के रूप में राजनीतिक गलियारों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं. कीर्ति आजाद के पिता भगवत झा आज़ाद 1988-89 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे. कीर्ति ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और क्रिकेट के बाद राजनीति को अपना करियर बनाया. आज आजाद दरभंगा से लोकसभा सांसद हैं. वह संसद में देश की समस्याओं पर बड़ी मुखरता से सवाल उठाते नज़र आते हैं. इनके अलावा श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा, सनथ जयसूर्या, हसन तिलकरत्ने अपने देश के संसदीय चुनावों में जीत दर्ज कर राजनीतिक सफर तय कर रहे हैं. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पहले अश्वेत कप्तान और बल्लेबाज फ्रैंक वारवेल जमैका की सीनेट के सदस्य के रूप में चुने गए थे. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में पूर्व तेज गेंदबाज नाथन ब्रेकेन न्यू साउथवेल्स सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ते दिखे.

समाज सेवा भी खिलाड़ियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र रहा है. इसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है. संन्यास लेने के बाद से ही स्टीव कोलकाता में कुष्ठ रोग से जूझ रहे बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था उदयन के लिए फंडिग करते रहे हैं. सचिन भी हमेशा से ही बच्चों की शिक्षा को लेकर काम करते रहे हैं. वह चैरिटी के दूसरे कामों मे भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं खासकर अपनालय की गतिविधियों में. अपनालय सचिन की सासू मां अनाबेल मेहता द्वारा चलाया जाने वाला एक एनजीओ है, जो कि मुंबई की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए काम करती है. इसी तरह सचिन एक निजी टीवी चैनल द्वारा चलाए गए सपोर्ट माई स्कूल कैंपेन से जुड़े, जिसके अंतर्गत देश के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जैस लक्ष्य शामिल थे, जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट बनाना और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना प्रमुख था. सचिन के इस कैंपेन से जुड़ने के कारण लक्ष्य से दो करोड़ ज्यादा राशि इस कैंपेन के जरिये जुटाए जा सके. हाल ही में सचिन ने महाराष्ट्र के अंधेरे में डूबे गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए काम शुरू किया है. यदि सांसद निधि से मिली राशि इस काम में कम पड़ती है तो सचिन इस प्रोजेक्ट को अपने पैसों से पूरा करेंगे.

एक कॉमेंट्रेटर के रूप में सचिन को तात्कालिक क्रिकेट से जोड़े रखने के लिए ईएसपीन-स्टार स्पोर्ट्स ने उनके साथ वर्ष 2007 में ही अनुबंध कर लिया था. जहां तक संभावना दिखती है, सचिन अपने पूर्व साथियों रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के साथ कॉमेंट्री करते दिखाई देंगे. हर कोई सचिन को इस नये रोल में देखना चाहता है और यह जानना चाहता है कि सचिन अपने पूर्व साथी खिलाड़ियों के खेल पर कितनी बेबाक और स्वतंत्र टिप्पणी करते हैं. वह मृदुभाषी तो हैं ही, उन्हें अब तक किसी के ऊपर जुबानी तौर पर हमला करते नहीं देखा गया है. उन्होंने अब तक अपने आलोचकों को बल्ले से मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन करके जवाब दिया है, लेकिन लोग अब उनके बल्ले के बाद उनके एक्स्पर्ट कमेंट और बोली का आक्रामक रुख देखना चाहते हैं. सबसे जिज्ञासा का विषय तो यह है कि सचिन किस तरह अपनी लच्छेदार भाषा से दर्शकों को लुभाएंगे. जिस तरह टोनी ग्रेग की कॉमेंट्री के साथ सचिन को बल्लेबाजी करते देखना कई गुना मजेदार हो जाता था, क्या कुछ वैसी ही छाप सचिन अपनी कॉमेंट्री से छोड़ पाएंगे. कॉमेंट्री के क्षेत्र में रवि शां ी, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू, संजय मांजरेकर ने अपने को स्थापित किया है. सचिन के लिए क्रिकेट के इस नये मैदान पर पैर जमाना आसान नहीं होगा.

इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज़ जैक रसैल को एक बेहतरीन विकेटकीपर और टीम प्लेयर के रूप में जाना जाता था. इसके वाबजूद वह खेल के मैदान के बाहर एकांत जीवन जीना पसंद करते थे. क्रिकेट के अलावा आर्ट उनका दूसरा पैशन था. क्रिकेट से रिटायर होने के बाद उन्होंने एक आर्ट गैलरी खोली. इसके बाद उनके एक निर्णय ने सभी को चौंका दिया. उन्होंने एक फुटबॉल एकादमी में गोलकीपर कोच के रूप में काम करना शुरू किया. 2008 में वह ग्लूस्टरशायर काउंटी टीम में नये खिलाड़ियों के कोच बन गए. इंग्लैंड के पूर्व एकदिवसीय कप्तान एडम होलिओक ने 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मीडिया को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, लेकिन अचानक उनके भाई बेन होलिओक की मृत्यु हो गई. इसके बाद एडम ने बेन होलिओक चैरिटी की स्थापना की और समाज सेवा के काम में लग गए. इसके साथ ही एडम ऑस्ट्रेलियाई प्रॉपर्टी के व्यापार में हाथ डाला, लेकिन उन्हें वहां अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने मिक्सड मार्शल आर्ट्स की दुनिया में भी अपने हाथ आजमाए. इसी तरह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और हरफनमौला खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बॉक्सिंग रिंग में नज़र आए. इसी तरह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑल राउंडर एंड्रयू सायमंड क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद रग्बी खेलने के अपने बचपन के शौक को पूरा कर रहे हैं. पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव और अजय जडेजा भी गोल्फ कोर्स में अपना भाग्य आजमाते दिखाई दिए. अब दोनों ही कॉमेंट्री करते या टीवी चैनलों पर भारतीय क्रिकेट का विश्लेषण करते दिखाई देते हैं.

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज सलिल अंकोला और अजय जडेजा संन्यास लेने के बाद फिल्मों में नज़र आए. सलिल अंकोला ने कई टीवी धारावाहिकों और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया. पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह पंजाबी फिल्मों का जाना-माना नाम है. योगराज सिंह 30 पंजाबी और 10 हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं. योगराज ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह के कोच की भूमिका अदा की. पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहसिन खान ने कई भारतीय फिल्मों में काम किया. उन्होंने अभिनेत्री रीना रॉय से निकाह किया था. संदीप पाटिल, सैय्यद किरवानी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सलीम दुर्रानी भी फिल्मों में अभिनेता के रूप में नज़र आए, लेकिन इन्हें यहां सफलता नहीं मिल पाई.

भारतीय कप्तान महेंद्र सिह धोनी ने भी हाल ही में कई बिजनेस शुरू किए हैं. उन्हें बाइक से बेहद लगाव है. उन्होंने अपने इस लगाव को एक मूर्त रूप दे दिया है और एक मोटो बाइक रेसिंग टीम खरीदी और उसे माही रेसिंग नाम से लॉन्च किया. इसके साथ ही उन्हें कुछ महीने पहले इंडिया सीमेंट में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है. उनकी इन सभी गतिविधियों को पोस्ट रिटायरमेंट प्लान के रुप में देखा जा रहा है.

सचिन को बीसीसीआई किसी भी तरह भारतीय क्रिकेट से सक्रिय रूप में जोड़े रखना चाहेगा, क्योंकि सचिन की ड्रेसिंग रूम में उपस्थिति मात्र से खिलाड़ियों में जोश भर जाता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सचिन मुंबई के लिए इस सीजन में क्रिकेट खेलते दिख सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मुंबई के कोच की भूमिका निभा सकते हैं. जिस तरह नदी अपने अंतिम पड़ाव में डेल्टा बनाकर अपने अंदर समेटी सारी उपजाउ मिट्टी दे जाती है, उसी तरह सचिन भी अपने सारे अनुभव युवा खिलाड़ियों को देना चाह रहे हैं. संन्यास के बाद सचिन के पास बहुत सारे विकल्प हैं. अब तक सचिन ने जिस परफेक्शन के साथ मैदान में शॉट सेलेक्शन किया, उसी तरह उन्होंने अपने भविष्य के लिए भी एक बेहतरीन निर्णय किया होगा. वह जिंदगी की नई पिच पर भी सफलता की नई इबारत लिखते दिखाई देंगे. उन्हें शुभकामनाएं. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

नवजोत सिंह सिद्धू

कीर्ति आजाद

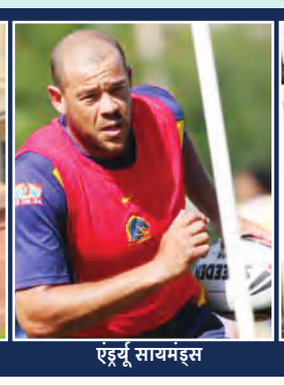
एंड्रयू सायमंड्स

जैक रसैल

एड्रयू फ्लिंटॉफ

इमरान खान

सलिल अंकोला

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
जगमग दुनिया
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467
28 अक्टूबर–03 नवंबर 2013

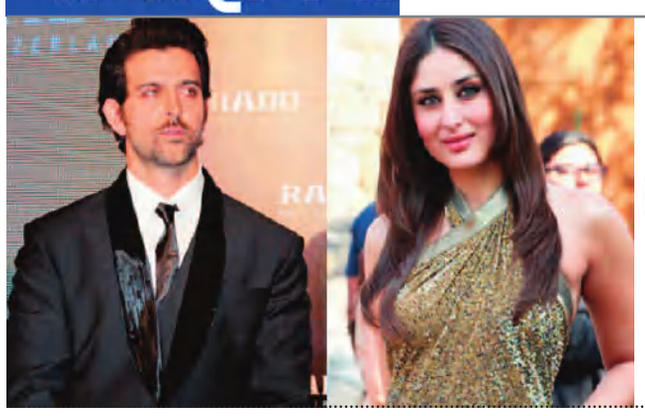

इन दिनों बॉलीवुड में एक और फिल्म अपने बजट को लेकर काफी चर्चा में है. 150 करोड़ रुपये की बजट से बन रही फिल्म शुद्धि को प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर. बॉलीवुड में अब तक की यह सबसे महंगी फिल्म होगी. अग्निपथ से बतौर निर्देशक डेब्यू करने वाले करण मल्होत्रा शुद्धि बना रहे हैं. शुद्धि में ऋतिक रोशन और करीना कपूर मुख्य भूमिका में हैं.

बड़े बजट की फिल्में

सफलता का पैमाना नहीं हैं

इन दिनों एक तरफ छोटे बजट की फिल्में बनाकर फिल्म निर्देशक बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे फिल्मकार भी हैं, जो बड़े बजट की भव्य फिल्में बना रहे हैं. इसके लिए वे विदेशों से महंगे प्रोफेशनल्स लाते हैं, जिनकी वे महंगी फीस चुकाते हैं. इसके अलावा, इन फिल्मों के सेट्स और पूरी फिल्म निर्माण में एक बड़ी राशि खर्च करते हैं. अपनी भव्यता के कारण ये फिल्में पसंद भी काफी की जाती हैं, लेकिन कई बार कुछ अलग और क्रिएटिव देने और बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी दर्शकों द्वारा फिल्में नकार दी जाती हैं, तब उस फिल्मकार को बड़ा नुक़सान होता है.

प्रियंका तिवारी

फिल्मकार एंथनी डिसूजा ने 125 करोड़ की लागत से फिल्म ब्लू बनाई. ऐक्शन और अंडर वॉटर सिनेमेटोग्राफी पर आधारित यह फिल्म बॉलीवुड की आम फिल्मों से अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, लेकिन यह फिल्म बूरी तरह फ्लॉप हो गई. इस कॉन्सेप्ट पर बॉलीवुड में पहली बार कोई फिल्म बनी थी. बावजूद इसके, यह फिल्म अपनी लागत तक नहीं वसूल पाई. फिल्म ने मात्र 54 करोड़ की कमाई की. हालांकि आज फिल्म की कमाई के अनगिनत माध्यम हैं. ऐसे में व्यावसायिक तौर पर फिल्म को कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन अगर किसी फिल्म की किस्मत ब्लू जैसी हो तो फिल्मकार को भारी खामियाजा चुकाना पड़ जाता है.

इन दिनों बॉलीवुड में एक और फिल्म अपनी बजट को लेकर काफी चर्चा में है. शुद्धि नाम से बन रही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर. फिल्म की बजट है 150 करोड़ रुपये. बॉलीवुड में अब तक की यह सबसे महंगी फिल्म होगी. 2012 में रिलीज ब्लॉक बस्टर फिल्म अग्निपथ से बतौर निर्देशक डेब्यू करने वाले करण मल्होत्रा करण जौहर के बैनर तले शुद्धि बना रहे हैं. शुद्धि में ऋतिक रोशन और करीना कपूर मुख्य भूमिका में हैं. बतौर करण मल्होत्रा इस फिल्म की शूटिंग के लिए हमने भोपाल की खूबसूरत झीलों को चुना है. यह एक रोमांटिक फिल्म होगी. गौरतलब है कि इससे पहले एंथनी डिसूजा की फिल्म ब्लू और शाहरुख की फिल्म रावन ही 100 करोड़ का आंकड़ा छू पाई थी.

हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो अपने बजट को लेकर काफी चर्चा में रहीं थीं. इनमें से कुछ हिट हुईं तो कुछ पिट गईं.

गजनी : वर्ष 2008 में रिलीज हुई फिल्म गजनी एक ऐक्शन फिल्म थी. इंडियन मार्केट में इसके 14 सौ प्रिंट्स थे, जबकि 200 प्रिंट्स ओवरसीज ऑडियंस के लिए थे. इसके लेखक और निर्देशक थे साउथ के निर्देशक एआर

मुरुगादास. इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे आमिर खान, असिन और जिया खान. इस फिल्म का बजट कथा 65 करोड़. यह फिल्म हिट हुई और बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई की और विदेशों में 115 करोड़ की.

कमबख्त इश्क : अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर इस कॉमेडी फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था. यह फिल्म वर्ष 2009 में रिलीज हुई थी. फिल्म की बजट 60 करोड़ रुपये थे. वर्ल्डवाइड इसके कुल 2000 प्रिंट जारी हुए थे. यह फिल्म हिट हुई और पहले ही दिन इस फिल्म ने 8.50 करोड़ की कमाई की.

जोधा अकबर : आशुतोष गोवारीकर द्वारा निर्देशित इस ऐतिहासिक फिल्म में मुख्य कलाकार थे ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन. यह फिल्म वर्ष 2008 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बजट 50 करोड़ था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 95 करोड़ की कमाई की.

ब्लू : यह एक थ्रिलर और अंडर वॉटर सिनेमेटोग्राफी पर आधारित फिल्म थी. इसे डाइरेक्ट किया था एंथनी डिसूजा ने. इसके मुख्य कलाकर थे अक्षय कुमार, लारा दत्ता और जायेद खान. इस फिल्म की बजट थी 125 करोड़, जबकि इस फिल्म ने कुल कमाई की 54 करोड़.

दबंग : इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अभिनव कश्यप ने और प्रोड्यूस किया था अरबाज खान ने. यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा. इसके कुल 1800 प्रिंट जारी हुए थे. इस फिल्म का बजट था 30 करोड़. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की. इस फिल्म ने कुल 80 करोड़ रुपये कमाए.

रा–वन : 135 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे शाहरुख और करीना. उस दौरान यह बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म थी. यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी. साइंस फिक्शन पर आधारित इस फिल्म में टेक्निकल ऐस्पेक्ट काफी सराहनीय था, लेकिन कमजोर स्टोरीलाइन और डाइरेक्शन के अभाव में इस फिल्म को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, पर कई माधयमों के जरिये इस फिल्म ने कुल 150 करोड़ रुपये की कमाई की.

डॉन 2 : वर्ष 2011 में बनी इस फिल्म का बजट था 70 करोड़. यह फिल्म डॉन की सिक्वल थी. इसे डायरेक्ट किया था फरहान अख्तर ने. मुख्य कलाकार थे शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा. फिल्म सुपरहिट हुई थी और इसकी कुल कमाई 228 करोड़ रुपये थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

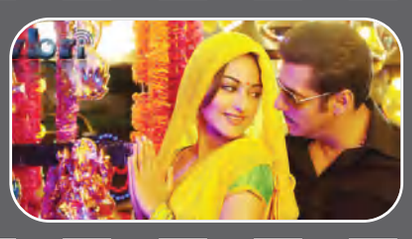

अच्छी कुक भी हैं निमरत

फिल्म लंच बॉक्स की अभिनेत्री निमरत कौर की खुशी का इन दिनों कोई ठिकाना नहीं है. किसी भी नये कलाकार के लिए यह गर्व की बात हो सकती है कि उसकी फिल्म ऑस्कर स्तर की समझी जाए. इस फिल्म को काफी सराहा गया. इस फिल्म में निमरत के सादगीपूर्ण अभिनय की भी काफी सराहना हुई. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक प्रिंट मॉडल के तौर पर की थी. फिर वह थियेटर की तरफ मुड़ीं. निमरत का जन्म पिलानी, राजस्थान में हुआ. पढ़ाई भटिंडा और पटियाला में हुई. उनके पिता आर्मी में थे, लेकिन 12 साल की उम्र में ही उनके पिता कश्मीर में आतंकी वारदात के दौरान शहीद हो गए. इसके बाद उनकी मां उन्हें और उनकी छोटी बहन रूबिना को लेकर नोएडा आ गईं. यहां उनकी पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई. उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया. अभिनय में रुझान की वजह से उन्होंने यहां लोकल थियेटर ज्वॉइन कर लिया. पढ़ाई पूरी कर निमरत मुंबई चली गईं. वहां उन्होंने मॉडलिंग की और थियेटर का हिस्सा बन गईं. उन्होंने कई प्ले भी किया. पहली बार वह 2002 में स्क्रीन पर श्रेया घोषाल और कुमार शानू के एलबम तेरा मेरा प्यार... में नजर आई थीं. कैडबरी डेरी मिल्क के ऐड फिल्म में भी वह दिखीं. 2006 में आई इंग्लिश फिल्म वन नाइट विद द किंग में उनकी बहुत छोटी सी भूमिका थी. 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म पैडलर्स में भी उन्होंने काम किया था. कान्स फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को काफी पसंद किया गया. 2012 में उनकी एक और फिल्म आई थी लव शव ते चिकन खुराना. इस फिल्म में उनके किरदार का नाम मुस्कान खुराना था, लेकिन उन्हें बेहतरीन अभिनय का मौका मिला अनुराग की फिल्म लंच बॉक्स में. खास बात यह है कि निमरत असल जीवन में भी अच्छी कुक हैं. निमरत अच्छी गायिका भी हैं. हालांकि इसकी उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है. स्पेन में बार्सिलोना उनकी पसंदीदा जगह है. उन्हें आर्ट और आर्किटेक्चर से काफी लगाव है. ■

प्रीव्यू : बुलेट राजा

प्रोड्यूसर : राहुल मित्रा, नितिन तेज आहूजा, तिग्मांशु धूलिया
स्टारकास्ट : सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा, विद्युत जमवाल, जिमी शेरगिल, गुलशन ग्रोवर, राज बब्बर, माही गिल, चंकी पांडे एवं रवि किशन
स्टोरी/राइटर : तिग्मांशु धूलिया, अमरेश मिश्रा
संगीत : साजिद -वाजिद
निर्देशक : तिग्मांशु धूलिया
स्क्रीनप्ले : तिग्मांशु धूलिया, अमरेश मिश्रा
डायलॉग : तिग्मांशु धूलिया

यह एक एक्शन फिल्म है, जिसमें रोमांस और कॉमेडी का तड़का भी डाला गया है. एजेंट विनोद, रेस 2, कॉकटेल और गो गोवा गॉन जैसी फ़िल्मों के बाद अब बुलेट राजा में सैफ बिल्कुल अलग भूमिका में नजर आएंगे. पहली बार सैफ इस फिल्म में एक उत्तर भारत के गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके किरदार का नाम राजा मिश्रा नाम के गैंगस्टर की है. राजा के किरदार में सैफ असली बुलेट और बंदुक दोनों चलाते नजर आएंगे. फिल्म में सैफ अली का खान का नाम राजा मिश्रा है, बजाए इसके लोग बुलेट राजा से ही उन्हें पहचानते हैं. इस फिल्म के लिए सैफ ने काफी मेहनत की है. उन्होंने बॉडी बनाने से लेकर उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा भी सिखी. सैफ को स्थानीय बोली की बेहतर समझ के लिए धूलिया ने लखनऊ के कई लोगों से उनकी बातचीत भी कराई. आपको बता दें कि सैफ पहले भी देसी किरदार में नजर आ चुके हैं. फिल्म ओमकारा में सैफ की लंगड़ा त्यागी की भूमिका को सभी ने सराहा था. शायद वहीं से तिग्मांशु को बुलेट राजा के किरदार के लिए सैफ को लेने की प्रेरणा मिली हो. बुलेट राजा के ट्रेलर में सैफ को सीरियस और कॉमिक, दोनों तरह के रोल्स में दिखाया गया है. बुलेट राजा में ऐक्शन, कॉमेडी और रोमांस सभी है. इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा सैफ के अपोजिट हैं. वह पहली बार सैफ के साथ पर्दे पर नजर आएंगी. अभिनेता रवि किशन इस फिल्म में एक किन्नर के किरदार में नजर आएंगे. तिग्मांशु धूलिया इससे पहले पान सिंह तोमर और साहेब बीबी और गैंगस्टर जैसी सफल फिल्में बना चुके हैं. फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कोलकाता में की गई है. तिग्मांशु धूलिया की पिछली लगभग हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है. उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आएगी. ■

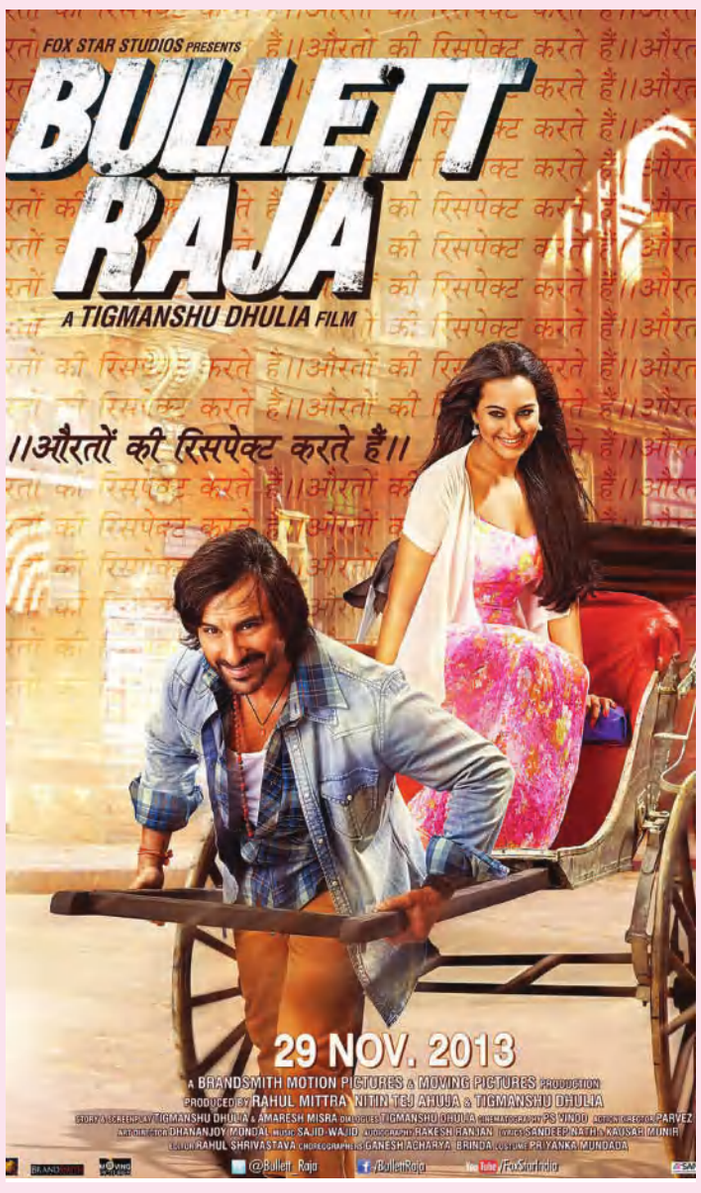

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

28 अक्टूबर–03 नवंबर 2013

बिहार–झारखंड

हर नज़र मोदी पर

सरोज सिंह

पटना में 27 अक्टूबर को होने वाली हुंकार रैली को लेकर तैयारियां चरम पर हैं. गली–मोहल्ले, चौक–चौराहे से लेकर गांव की बैठकों में बस एक ही चर्चा है कि आखिर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में क्या बोलेंगे? इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि भीड़ के लिहाज से नरेंद्र मोदी की यह रैली बिहार की पिछली सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं. इन दो बातों पर जहां आम जनता में बहस छिड़ी है तो वहीं सूबे की राजनीतिक पार्टियों की चिंताएं और जिज्ञासाएं अलग–अलग हैं. बस एक ही बात कॉमन है कि हर कोई नरेंद्र मोदी के आने का ही इंतजार कर रहा है. चूंकि रैली प्रदेश भाजपा कर रही है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर सबसे अधिक चुनौती इसी के सामने है. नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के मद्देनजर यह चुनौती और भी बढ़ गई है. लोकसभा और विधानसभा की चुनावी राजनीति के नजरिये से भी हुंकार रैली का व्यापक महत्व है और सबसे बड़ी बात है कि अगर भाजपा को खुद को बिहार में एक विकल्प के तौर पर स्थापित करना है तो इसका रास्ता हुंकार रैली की सफलता से होकर ही गुजरेगा. इसलिए भाजपा का हर बड़ा या छोटा नेता सारे गिले शिकवे भुलाकर नमो नमो के जाप में जुटा है. रैली की तैयारियों में व्यस्त गोपाल नारायण सिंह कहते हैं कि 27 को हमलोग एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं. नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता खुद ब खुद गांधी मैदान की ओर बढ़ रही है. बिहार को नरेंद्र मोदी का इंतजार था और 27 अक्टूबर को यह इंतजार खत्म होने जा रहा है. भीड़ के लिहाज से इनका दावा है कि हुंकार रैली बिहार की अब तक की सबसे बड़ी रैली साबित होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि जनता खुद इस रैली में शिरकत करने को बेताब है. भाजपा को इस बात का अच्छी तरह अहसास है कि अगर रैली उम्मीदों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो आगे की लड़ाई काफी कठिन हो जाएगी. पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता पटना आ रहे हैं और इस दिन भी अगर पटना मोदीमय नहीं दिखा तो फिर विपक्ष के सवालों का जबाव देना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. इसलिए पूरा दम रैली की तैयारियों में झोंक दिया गया है. अपने–अपने इलाके के मजबूत नेताओं को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है ताकि इनके संसाधनों को रैली को कामयाब बनाने में झोंका जा सके. भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडेय कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बिहार की जनता बेताब है और 27 अक्टूबर को जनसैलाब गांधी मैदान में उमड़ पड़ेगा. भाजपा नेताओं को लग रहा है कि उनकी कमियां नरेंद्र मोदी के नाम के आगे ढक जाएंगी. पार्टी के सभी 91 विधायकों को कहा गया है कि वह अपनी पूरी ताकत लगा दें ताकि गांधी मैदान में इतिहास रचा जा सके. भाजपा इस रैली के लिए युवाओं को खासकर टारगेट कर रही है. युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नितिन नवीन एंड कंपनी आधुनिक तकनीक से लेकर पारंपरिक तरीके भी अपना रही है. भाजपा को यह अहसास है कि उसके सामने चुनौती काफी कठिन है. जदयू भी नरेंद्र मोदी का इंतजार बहुत ही शिद्दत से कर रही है. जदयू यह पुख्ता करना चाहती है कि बिहार के लोगों में मोदी फैक्टर किस तरह और कितनी गहराई तक काम कर रहा है. उसके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अलग होने के बाद भाजपा की जमीनी ताकत क्या रह गई है. ऐसा इसलिए जरूरी है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वह अपनी रणनीति की दिशा तय कर सके. अगर नरेंद्र मोदी की रैली सामान्य रैलियों की तरह रही तो जदयू यह बड़े जोर शोर से प्रचारित करेगी कि बिहार में नरेंद्र मोदी फेल हो गए औ यहां के असली किंग नीतीश कुमार ही हैं. लेकिन अगर यह रैली ऐतिहासिक हुई तो जदयू इसकी काट खोजने में लगेगी और हर वह जतन करेगी जिससे भाजपा की ताकत को कम किया जा सके. इन उपायों में कांग्रेस और लोजपा से गठबंधन भी शामिल है. ऐसा इसलिए भी है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हर हाल में फेल करना चाहते हैं. इसलिए दिली इच्छा न होने और पार्टी के अंदर विरोध के बावजूद नीतीश कुमार कुछ अजीब से गठबंधन भी कर सकते हैं. लेकिन यह सारा कुछ हुंकार रैली की सफलता और विफलता से जुड़ा मसला है. इसी तरह राजद को भी नरेंद्र मोदी के बिहार आने का इंतजार है. राजद के नेता दावा कर रहे हैं कि रैली के मामले में लालू प्रसाद को कोई चुनौती नहीं दे सकता चाहे वह नरेंद्र मोदी ही क्यों न हो. अगर रैली मनमाफिक नहीं हुई तो राजद यह प्रचारित करेगा कि बिहार में लालू से बड़ा जनाधार किसी के पास नहीं है इसलिए राजद ही लोकसभा चुनाव में जनता के सामने स्वाभाविक विकल्प है, लेकिन अगर रैली सफल रही तो राजद यह बात प्रचारित करेगा कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही है और इसके एक मात्र जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं. इसलिए अगर सांप्रदायिक ताकतों को कुचलना है तो लोगों को नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना चाहिए और राजद का साथ देना चाहिए. कांग्रेसी नेताओं को भी नरेंद्र मोदी का इंतजार है. कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि रैली के बाद ही यह निर्णय लिया जा सकेगा कि पार्टी को यहां किसी दल के साथ तालमेल करना चाहिए या फिर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए. इसलिए कहा जाए तो हर दल को नरेंद्र मोदी का इंतजार है. हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी हीरो बनकर उभरे या जीरो बनकर दोनों ही परिस्थतियों में सूबे की राजनीति बदलनी तय है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हर हाल में फेल करना चाहते हैं. इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं. यह हुंकार रैली की सफलता और विफलता से जुड़ा मसला है. राजद को भी नरेंद्र मोदी के बिहार आने का इंतजार है. राजद के नेता दावा कर रहे हैं कि रैली के मामले में लालू प्रसाद को कोई चुनौती नहीं दे सकता, चाहे वह नरेंद्र मोदी ही क्यों न हों.

टिकट के दावेदारों में होड़

बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र को भूमिहार बहुल माना जाता है. दल कोई भी हो, लेकिन हमेशा से इसी जाति के नेताओं का बोलबाला रहा है. अब चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है तो अटकलों का बाजार भी गर्म है.

पिछले दिनों गांधी स्टेडियम में भाजपा द्वारा आयोजित रैली की सफलता का श्रेय लेने के लिए पार्टी नेताओं के बीच मची होड़ से आम कार्यकर्ता नाखुश हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि रैली भाजपा की थी और सफलता का श्रेय भाजपा को जाना चाहिए. रैली में नेताओं के अहं की टकराहट, नोकझोंक से उपजे मतभेद खुलकर सामने आए. मतभेद इस कदर बढ़ा था कि कुछ स्थानीय नेताओं को बोलने तक नहीं दिया गया.

सुरेश चौहान/रघुवीर झा

भोला सिंह

गिरिराज सिंह

बेगूसराय लोकसभा में आगामी चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हैं. मसलन इस भूमिहार बहुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन बनेगा भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी? क्या इस बार अतिपिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को मिलेगा टिकट या फिर भूमिहार का ही होगा इस पर कब्जा? भाजपा में इस बिन्दु पर मंथन जारी है. विधान पार्षद गिरिराज सिंह एवं नगर विधायक सुरेन्द्र मेहता सभी समीकरण को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं. लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के पूर्वमंत्री एवं भाजपा नेता व विधान पार्षद गिरिराज सिंह की सशक्त दावेदारी से नवादा सांसद डॉ. भोला सिंह सकते में हैं. इससे डॉ. सिंह की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है. वहीं बेगूसराय विधायक सुरेन्द्र मेहता की दावेदारी से पार्टी के मठाधीशों की भृकुटि तन गई है. पहले से ही मतभेद से ग्रस्त भाजपा के लिए इस स्थिति से उबरना आसान नही लग रहा है. पिछले दिनों तक यह आम चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव के लिए नवादा सांसद डॉ. भोला सिंह, उपेन्द्र प्रसाद सिंह एवं रामलखन सिंह भाजपा प्रत्याशी के प्रबल दावेदार हैं. इस चर्चा से उत्साहित होकर डॉ. भोला सिंह की गतिविधियां जिले में तेज हो गई थी. स्थिती यह हो गई है कि भोला सिंह जिले के हर छोटे-बड़े कार्यक्रम में नजर आने लगे थे. इतना ही नहीं क्षेत्र में उनका जनसंपर्क अभियान भी तेज हो गया था. भोला को जब इससे संतोष नहीं मिला तो वह पार्टी कार्यकर्ताओं पर रौब डालने के लिए गुजरात जाकर तत्कालीन चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी से भेंट कर आये और उनके साथ वाली अपनी तस्वीर को बेगूसराय के अखबारों में प्रकाशित भी करवाया, लेकिन विधान पार्षद गिरिराज सिंह की दावेदारी से डॉ. सिंह के मंसूबे पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है. कल तक बेगूसराय लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनने के लिए गिरिराज सिंह सिर्फ ताकझांक कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने अपनी दावेदारी को काफी पुख्ता कर लिया है. नरेन्द्र मोदी एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से गिरिराज सिंह की निकटता जगजाहिर है. पूर्व में मुंगेर लोकसभा सीट से गिरिराज सिंह को प्रत्याशी बनाये जाने की संभावना अधिक थी, लेकिन गिरिराज सिंह वैसी सीट की तलाश में थे, जहां से उनके जीतने के प्रबल आसार हो. इसके लिए गिरिराज सिंह ने बेगूसराय की लोकसभा सीट को अपने सर्वथा अनुकूल पाया और यहां अपनी दावेदारी पार्टी आलाकमान के पास ठोक दी. गिरिराज सिंह की इस दावेदारी से न सिर्फ डॉ. भोला सिंह वरन् उपेन्द्र प्रसाद सिंह एवं रामलखन सिंह भी अचंभित हैं. उपेंद्र प्रसाद सिंह एवं रामलखन सिंह के बारे में बताया जाता है कि डॉ. भोला सिंह को सीटिंग सीट नवादा से ही चुनाव लड़ाया जाएगा और बेगूसराय से वे पार्टी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं. इसके लिए दोनों पार्टी के अंदर एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अपनी-अपनी लॉबी मजबूत बनाने में जुटे थे, लेकिन अब उनकी आशाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है.

इसी बीच एक नया समीकरण जन्म लेने की चर्चा जोरों पर है. बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है. गिरिराज सिंह, डॉ. भोला सिंह, उपेन्द्र प्रसाद सिंह एवं रामलखन सिंह इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है. वैसे में किसी एक को प्रत्याशी बनाने से शेष की नाराजगी लेना मुश्किल है. इस स्थिति से बचने के लिए भाजपा द्वारा नगर विधायक सुरेन्द्र मेहता को प्रत्याशी बनाए जाने की प्रबल संभावना है. मेहता अतिपिछड़ा वर्ग से आते हैं. पार्टीजनों का कहना है कि यदि मेहता को प्रत्याशी बनाया जाता है, तो उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिल सकता है और भाजपा की जीत सुनिश्चित हो सकती है.

मालूम हो कि पिछले दिनों गांधी स्टेडियम में भाजपा द्वारा आयोजित रैली की सफलता का श्रेय लेने के लिए पार्टी नेताओं के बीच मची होड़ से आम कार्यकर्ता नाखुश है. उनका कहना है कि रैली भाजपा की थी और सफलता का श्रेय भाजपा को जान चाहिए. रैली में नेताओं के अहम की टकराहट, नोकझोंक से उपजे मतभेद खुलकर सामने आये. कुछ स्थानीय नेताओं को बोलने तक नहीं दिया गया. एक नेता को बोलने देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष से सिफारिश करनी पड़ी. इसी दौरान एक कद्दावर नेता मंच से उठकर चले भी गये. भाजपा के सामने फिलहाल चुनौती यह है कि वो अपने नेताओं के बीच के मतभेद को खत्म करे. ■

मुस्लिम वोटरों को रिझाने में जुटी भाजपा

जुबैर अंसारी

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा पूरी ताकत के साथ कमर कस चुकी है, वहीं सत्ता दल भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जबकि राजद और लोजपा भी इन दोनों दलों को मात देने की तैयारी में लगी हुई है. इन सब के बीच कॉंग्रेस नेत्री व पूर्व सांसद रंजीता रंजन यूपीए सरकार की खूबियां गिना रही हैं.

सुपौल लोकसभा में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी तादाद है और इस वोट बैंक पर अबतक राजद की पकड़ दिखती है, जबकि जदयू कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस बार अधिक से अधिक मुस्लिम वोट जदयू के झोली में जाएगी. अगर कहीं मुस्लिम मतदाता जदयू की ओर 25 फीसद भी झुका तो राजद के लिए परेशानी हो जाएगी. इधर, भाजपा इस कोशिश में दिख रही है कि मोदी के नाम पर मुस्लिम मतदाता उससे छिटके नहीं. यही वजह है कि भाजपा के द्वारा मुसलिम वोटरों को रिझाने की प्रक्रिया जारी है. इसी रणनीति के तहत बसंतपुर प्रखंड के उपप्रमुख बीवी आयशा को अभी से छातापुर विधान सभा का अगला उम्मीदवार बना दिया गया है. सूत्रों से मीली जानकारी अनुसार बाहुबली और पूर्व सांसद तथा युवा शक्ति के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपनी पत्नी और पूर्व सांसद रंजीता रंजन की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा से हाथ मिलाने को तैयार हैं. अगर बीजेपी सुपौल से रंजीता रंजन को अपना उम्मीदवार बनाती है तो लड़ाई दिलचस्प होगी. वहीं जदयू से वर्तमान सांसद विश्वमोहन कुमार की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है. इलाके के कार्यकर्ताओं को नीतीश के नाम का ही सहारा लेना होगा. पिछले विधानसभा चुनाव के अनुभवों को आधार बनाते हुए राजद चुनाव लड़ने की योजना में है, लेकिन बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी दबंग मुस्लिम को चुनावी दंगल में उतारना चाहती है. ऐसे भाजपा के घोषित उम्मीदवार के रूप में जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रवण चौधरी का नाम आ रहा है, लेकिन बीजेपी कोई भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है. यही वजह है कि सीमांचल में मुस्लिमों पर पकड़ रखने वाले और धनाढ्य मदरसा रियाजूल उलुम शंकरपुर की निदेशक मौलाना अखतर आलम सल्फी पर भाजपा डोरे डाल रही है. अगर यह अनुमान सच निकला तो फिर चुनावी रंग बदल जाएगी. ऐसे तो सल्फी कई बार विधान सभा टिकट के लिए राजद लोजपा में हाथ पांव मार चुकी हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है. ■

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

28 अक्टूबर–03 नवंबर 2013

> जमुई जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में यादव जाति के मतदाताओं की संख्या तकरीबन पौने तीन लाख है. भाजपा में अब तक इस जाति के एक मात्र मजबूत नेता फाल्गुनी प्रसाद यादव ही थे. डॉ. रवींद्र के आने के बाद भाजपा की पैठ मतदाताओं में कितनी गहरी होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा.

मुश्किल में रवींद्र यादव

राजेश कुमार/मनोज भारद्वाज

पूर्व विधायक डॉ. रवींद्र यादव के भाजपा में शामिल होने से पार्टी में नए जोश का संचार हुआ है. यादव तपे तपाए नेता हैं और अपनी बिरादरी के अलावा अन्य समुदायों में भी उनकी पकड़ है. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राज किशोर सिंह कहते हैं कि यादव के आने से पार्टी की ताकत बढ़ी है, लेकिन जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार भगत इस बात से सहमत नहीं दिखते. उनका मानना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है. संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं की पहचान होती है. इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि संगठन में कौन आता है और कौन जाता है? जमुई जिले में पड़ने वाले चार विधानसभा क्षेत्रों में यादव जाति के मतदाताओं की संख्या तकरीबन पौने तीन लाख है. भाजपा में इस जाति के एक मात्र मजबूत नेता फाल्गुनी प्रसाद यादव ही अब तक थे. डॉ. रवींद्र के आने के बाद भाजपा की पैठ मतदाताओं में कितनी गहरी होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा. निश्चित तौर पर झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए डॉ. रवींद्र अभी से कमर कस रहे हैं. वर्ष 1986 तथा 1995 में वे झाझा से कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं. उनके पिता स्व. शिवनंदन यादव भी 1980 तथा 1985 में झाझा से कांग्रेस के विधायक रहे. वर्ष 2003 में निर्दलीय

प्रत्याशी के रूप में डॉ. रवींद्र विधान पार्षद चुने गये. भाजपा में शमिल होने पर उनके गृह क्षेत्र झाझा में भाजपा संगठन के तेवर तीखे हैं. झाझा के भाजपा नगर अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह कहते हैं कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए समर्पण की जरूरत है. डॉ. रवींद्र यादव में वैसी समर्पणशीलता है. भाजपा के पूर्व विधायक फाल्गुनी प्रसाद यादव ने इस बाबत अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी और कहा वे डॉ. रवींद्र यादव का भाजपा में आने का स्वागत करते हैं. झाझा में भाजपा के कई ऐसे नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी मिलीं, जो डॉ. रवींद्र को भाजपा में पचा पाने की स्थिति में नहीं हैं. उनका कहना है कि वैश्य व बनिया का वोट भाजपा के लिए डॉ. रवींद्र को मिलना मुश्किल है. इसके पीछे इन बागी तेवर में दिखने वाले नेताओं ने कई तर्क भी दिए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना

रणजीत सिंह

बिन्देश्वरी प्रसाद साह

सुरेंद्र यादव

राकेश कुमार सिंह

माधुरी पासवान

प्रसादी यादव

है कि झाझा विधान सभा क्षेत्र में यादव जाति के मतदाताओं की संख्या तकरीबन 85 हजार है. यहां डॉ. रवींद्र को छोड़ भाजपा का कोई दूसरा सशक्त विकल्प नजर नहीं आता. डॉ. रवींद्र यादव को नये सिरे से झाझा में अपनी सियासत का आगाज करना होगा और यह तभी संभव है, जब वे झाझा के भाजपा संगठन की धुरी माने जाने वाले बिन्देश्वरी साव, सुरेन्द्र यादव, माधुरी पासवान, शंभुनाथ जगन बंधु, कृष्णनन्दन सिंह एवं प्रसादी यादव सहित वहां के अन्य सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने और करीब ला सकें. ■

श्रीकृष्ण बाबू के सपनों को नीतीश पूरा कर रहे हैं : अवनीश

बिहार विधान सभा में शून्यकाल के सभापति व भाजपा के वरिष्ठ नेता अवनीश कुमार सिंह के बगावती तेवर ने भाजपाइयों की होश उड़ा दी है. चंपारण समेत उत्तर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है. बीते दिनों उनका मोतिहारी आना हुआ. पेश है चौथी दुनिया से उनके बातचीत का संक्षिप्त अंश...

■ ऐसी चर्चा है कि आप मोतिहारी लोकसभा से जदयू के प्रत्याशी होंगे.

–बिल्कूल सही चर्चा है. समय आने पर सबकुछ साफ हो जाएगा.

■ आप भाजपा के काफी वफादार सिपाही माने जाते रहे हैं और इससे पहले आप पांच बार विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं.

–भाजपा अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है. नरेंद्र मोदी जैसे दागदार चेहरे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर उसने अपनी छवि को धूमिल कर दी है. भाजपा को पहले आरएसएस सलाह देती थी और अब आदेश देती है.

■ बिहार में भाजपा की क्या स्थिति है.

–बिहार में सुशील मोदी, नंदकिशोर व राधामोहन ने भाजपा को हाइजेक कर लिया है, जिससे यह कुछ खास लोगों की पार्टी बन कर रह गई है.

■ मोतिहारी में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के खुलने में लगने वाले समय की क्या वजह है?

–इसके लिए सीधे–सीधे सांसद राधामोहन सिंह समेत चंपारण के सभी सांसद जिम्मेदार हैं. घोषणा के 15 माह गुजर जाने के बावजूद इस विधेयक पर लोकसभा में बहस नहीं की गई और केवल सड़क पर राजनीति कर जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया.

■ भाजपा का मानना है कि बिहार में फिर जंगल राज कायम हो गया है और उनके सत्ता से अलग होते ही कानून व्यवस्था चरमरा गई है.

–ऐसा कुछ नहीं है. नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश चल रही है. बिहार में नीतीश कुमार ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार का काफी विकास हुआ है और श्रीकृष्ण बाबू के सपने को पूरा किया जा रहा है.

■ क्या श्रीकृष्ण बाबू की तर्ज पर काम कर रहे हैं नीतीश?

–बिल्कुल. श्रीकृष्ण बाबू ने बिहार के लिए जो सपना देखा था, उसे नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं.

■ खोड़ा गांव का क्या मामला है?

–खोड़ा के गरीब मुसलमानों पर यादव समाज के लोगों ने जुल्म किया है. खोड़ा यादव बाहुल्य गांव है और मस्जिद पर माइक लगाने को लेकर पूर्व विधायक लक्ष्मीनारायण यादव के रिश्तेदारों ने आतंक मचाया तथा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया.

■ भाजपा से अलग होने का और कोई कारण?

– बस, न्याय के साथ बिहार का विकास हो रहा है और इस विकास की रफ्तार को और गति देने के लिए मैं नीतीश कुमार का हाथ मजबूत कर रहा हूं.

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

28 अक्टूबर–03 नवंबर 2013

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

वोटों की राजनीति

अल्पसंख्यकों को भटकाते हैं राजनीतिक दल

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता एकजुट रहे. समाजवादी सरकार और पार्टी का इकबाल मुसलमानों के बीच कायम रहे, इसके लिए सपा सरकार और संगठन के सरदारों द्वारा साम–दाम–दंड भेद सभी तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. सपा आलाकमान का आकलन था कि मुसलमानों के सहारे नेताजी की दिल्ली की दावेदारी मजबूत हो सकती है, लेकिन मुजफ्फनगर दंगों ने इसके अरमानों पर पानी फेर दिया. दंगों ने इसकी स्थिति न खुदा मिला न विसाले सनम जैसी कर दी है. सपा किसी भी तरह से यूपी में कम से कम 60 सीटें जीतने का सपना पाले हुए हैं. उधर, कांग्रेस मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है. सपा का मुस्लिम प्रेम को कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है. दंगों ने इसे समाजवादी सरकार पर वार करने का मौका दे दिया तो सपा प्रमुख अभी नहीं, तो कभी नहीं की तर्ज पर मुस्लिमों को लुभाने के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगाए हुए हैं. दंगों के बाद बदले सियासी समीकरण साधने के लिए मुलायम और सीएम अखिलेश यादव अपने–अपने सिपहसालारों पर भरोसा छोड़कर स्वयं मैदान में कूद पड़े हैं. मुस्लिमों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए सपा बड़े पैमाने पर देश बचाओ–देश बनाओं रैलियों का आयोजन करने जा रही है. 29 अक्टूबर को आजमगढ़ से रैली का आगाज होगा, लेकिन 09 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की रैली में मुसलमानों को लुभाने के लिए मुलायम और अखिलेश स्वयं मौजूद रहेंगे.

एक तरफ मुस्लिम वोटों को लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों में मारामारी मची है तो दूसरी तरफ बुद्धिजीवी मुसलमान इस बात से चिंतित हैं कि उनकी कौम को वोट बैंक से अधिक तरजीह नहीं मिल पा रही है. राजनीतिक दल उनकी बुनियादी समस्याओं को दूर करने की बजाय धर्म के नाम पर उनका शोषण करते रहते हैं, जैसा कि जमीयत–ए–उलेमा–ए–हिंद के प्रमुख महमूद मदनी भी कहते हैं. मुसलमानों को डराया जाता है और जो फायदा उन्हें मिलना चाहिए वह नजर नहीं आता. आजादी के बाद से मुसलमान आज भी वहीं खड़े दिखाई देते हैं जहां सपा–बसपा जैसी पार्टियों के उदय से पहले खड़े थे. पिछले दो दशकों की ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हालात में इस दौरान कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. साक्षरता की रफ्तार पहले भी सुस्त थी और आज भी सुस्त है. सरकारी नौकरियों में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ पाया है तो माली हालत भी में भी औसत भारतीयों से पिछड़ा हुआ है. देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की कुल संख्या में मुसलमानों की संख्या चौथाई (25 प्रतिशत) बनी हुई है.

आरक्षण से दलितों और पिछड़े हिन्दुओं का तो उत्थान हुआ, लेकिन मुसलमानों को इसका फायदा नहीं मिला. बसपा, सपा और कांग्रेस समय–समय पर मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा उछालते रहते हैं, लेकिन इसमें गंभीरता का अभाव है. संविधान में जातीय आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है. मुसलमानों में कोई अनुसूचित जाति नहीं होती, इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग में कोई मुस्लिम जाति शामिल नहीं है. पिछड़ा वर्ग की जो सूची है इसमें नाई, अंसारी, दर्जी, रंगरेज, मिरासी, भिस्ती, कुंजड़ा, धुनिया फकीर, घोसी, उफाली, धोबी, मनिहार और हलवाई जैसी एक दर्जन मुस्लिम जातियां शामिल हैं. जिन्हें आरक्षण का लाभ है. चूंकि इन जातियों में साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है इसलिए वह आरक्षण का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं. सपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव के समय मुसलमानों को आरक्षण की बात कही थी, लेकिन सपा सरकार के सत्तारूढ़ होने के डेढ़ वर्ष बाद भी इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं. पिछड़ा वर्ग के लिए जो 27 प्रतिशत आरक्षण तय है, इसमें इन मुस्लिम जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में कोटा तय करना भी आसान नहीं. पूर्व में हुई इस तरह की कोशिश को अदालत भी खारिज कर चुकी है. राजनाथ सिंह जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग की

(शेष पृष्ठ 18 पर)

अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरने में विफल रहे

कुमार निलाम्बुज

खोदा पहाड़ और निकली चुहिया... कुछ ऐसा ही वातावरण रहा नरेन्द्र मोदी के सिपहसालार अमित शाह के वाराणसी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन का. नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अमित शाह को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है. गुजरात भाजपा मशीनरी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में मोदी के लिए राजपथ के कांटों को साफ करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी पाठ पढ़ाने के लिए अमित शाह वाराणसी चुनाव प्रबंधन की टोह लेने आए थे. अमित शाह के वाराणसी आगमन से पूर्व कार्यकर्ता बड़े जोश में थे, लेकिन अमित शाह ने कार्यकर्ताओं जो घुट्टी पिलाई, उसका उल्टा असर दिख रहा है. शाह ने कार्यक्रर्ताओं में जोश भरने के बजाय उन्हें और सुस्त कर दिया है. अमित शाह कार्यकर्ताओं की नब्ज भांपने में पूरी तरह विफल रहे, तभी तो अमित शाह के जाने के बाद काशी क्षेत्र की धांसू टीम ही नहीं, महानगर और जिला इकाई के कार्यकर्ता तक चादर तान कर सो गए है. यहां से वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं. पूरी सांसदी पारी के दौरान न तो जोशी ने कार्यकर्ताओं का ख्याल किया और न ही बनारस का लिहाज. सांस्कृतिक नगरी की गलियां गंदगी से बजबजाती रहीं और सड़कें सांसद और बीजेपी के तीन विधायकों की आस में लोगों को उलझाती रहीं. मूलभूत समस्याओं की मांग को लेकर जनता और मीडिया दोनों ने जोशी से सम्पर्क किया तो उनका कहना था उनसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की जाए. नाराज जनता जोशी को सबक सिखाने की तैयारी में है. इसका श्रेय उनके कारिंदों को भी जाता है. जोशी के कारिंदों ने तो ऐसा माहौल बनाया, जैसे जोशी नेता न होकर दुर्वासा हैं. डा. जोशी के तौर तरीकों से कार्यकर्ता पहले से ही खासे नाराज थे, उसपर से एकाएक टपके अमित शाह कार्यकर्ताओं की सुनने के बजाय कार्यकर्ताओं को छोड़कर चुनावी फरमान सुना दिया. पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के बीच अमित शाह सबसे बड़े नेता नजर आ रहे थे. कार्यकर्ताओं की खबर भी खूब ली उन्होंने. चुनाव में तत्परता से जुटने का फरमान अलग. अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बड़े छोटे का लिहाज छोड़ें और पार्टी के कार्यक्रमों को सख्ती से लागू करें. पार्टी के फरमान को लागू कराने में कतई ढिलाई न बरतें जैसे संदेश कार्यकर्ताओं को थमाते रहे. अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही पार्टी में संघ की थोपी संस्कारिक परिपाटी पर दनादन हथौड़ा चला रहे थे.

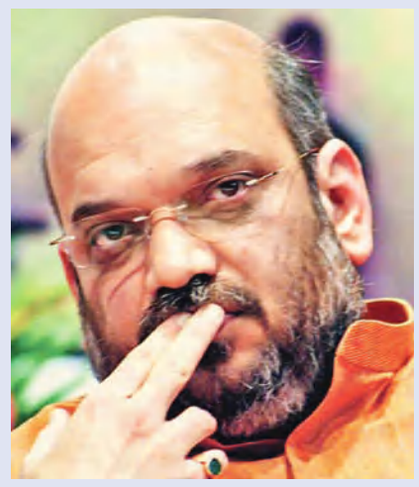

गौरतलब है कि डॉ. मुरली मनोहर जोशी पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं में से हैं जिनका नारा लगाते हुए पार्टी के कार्यकर्ता सयाने हुए हैं. पार्टी का जब उदय हो रहा था, यानी मंदिर आंदोलन के समय भाजपा कार्यकर्ता भारत मां के तीन धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर का नारा अभी भूले नहीं है. इन तीन में से एक धरोहर अटल तो बीमार हैं, लेकिन दो धरोहर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी राजनीति में तो हैं, लेकिन लगता है पार्टी में दोनों की सुनने वाला कोई नहीं है. तभी तो अमित शाह संघ की परिपाटी और मर्यादा की कार्यकर्ताओं के सामने ही बलि चढ़ा रहे थे. अमित शाह के आगे सभी बौने दिखाए जा रहे थे. लोकतंत्र में व्यक्ति संस्था से बड़ा नहीं हो सकता. व्यक्तिवादी होने से लोकतंत्र जैसी संस्था खतरे में पड़ सकती है. अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए सरकार के खिलाफ उपजे असंतोष को भुनाने को कहा. उन्होंने सरकार की नाकामियों से नाराज जनता को पार्टी से जोड़ने का संदेश तो दिया, लेकिन पार्टी पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक की नाराजगी का कोई ख्याल नहीं रखा. सर्किट हाइस में ठहरे अमित शाह एंड कंपनी पार्टी मीटिंग के बहाने टीवी देख रहे थे और कार्यकर्ता बाहर अपने नेता का इंतजार कर रहे थे. सर्किट हाउस में अमित शाह और उनके तीन चार

(शेष पृष्ठ 18 पर)

गुटबाजी से भाजपा आलाकमान सकते में

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में तीन गुटों में बंटी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज देवभूमि में मोदी के मिशन 2014 की हवा निकालने में जुटे हैं. यह मसला राजनाथ जी के लिए खास चिन्ता का विषय बना हुआ है. लोकसभा चुनाव नजदीक देखकर भाजपा आलाकमान परेशान है. प्रदेश भाजपा की गुटबाजी इसका मुख्य कारण है. भाजपा आलाकमान को आशंका है कि गुटबाजी कम न हुई तो लोकसभा चुनाव में प्रदेश से भाजपा को अपेक्षित परिणाम मिलने में दिक्कत हो सकती है. इसी महीने नौ तारीख को लोकसभा चुनावों की तैयारी के सिलसिले में प्रदेश के बड़े नेता दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले थे. सूत्रों की मानें तो डेढ़ घंटे चली भेंट में प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात के साथ ही 2014 के आम चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श तो हुआ ही, राजनाथ सिंह ने प्रदेश के नेताओं को हिदायत दी कि वे आपसी प्रतिद्वंद्विता को दरकिनार कर काम करें. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भले ही उत्तराखंड के सियासी हालात भाजपा के लिए मुफीद दिख रहे हैं, चुनाव एक होकर नहीं लड़े गए तो नतीजों में उलटफेर हो सकता है. जनवरी 2012 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले से ही भाजपा में धड़ेबंदी साफ दिखाई देती रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऊपरी तौर पर भले ही भाजपा के नेता एका दिखाने की कोशिश करें, प्रदेश भाजपा में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों, खंडूड़ी, कोश्यारी और निशंक के तीन गुट हैं. भाजपा का प्रदर्शन इन धड़ों के आपसी समीकरणों पर ही निर्भर करता है. माना जाता है कि इसी धड़ेबंदी की वजह से 2009 में भाजपा को पांचों लोकसभा सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था. कहा जाता है कि तब एक गुट ने चुनाव के दौरान अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई थी. नतीजतन भुवनचंद्र खंडूड़ी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था और इसी के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक का नाम आगे कर दिया. यह बात और है कि बाद में खंडूड़ी और निशंक गुट सीधे–सीधे आमने सामने आ गए.

इस बीच खंडूड़ी को कोश्यारी धड़े का समर्थन मिला और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए चुनाव से पहले निशंक को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि एक गुट विशेष पर यह भी आरोप लगा कि उसने कोटद्वार से खंडूड़ी को ही हरवा दिया. विधानसभा चुनाव के ठीक बाद धड़ेबंदी के चलते ही भाजपा के खेमे एक दूसरे पर उन्हें हराने की साजिश का आरोप लगाते दिखाई दिए. विधानसभा चुनाव के ऐन बाद निशंक सरकार बनाने के लिए सक्रिय हो गए थे, खंडूड़ी और कोश्यारी की असहमति के कारण उनकी योजना परवान नहीं चढ़ी. पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के दौरान भी धड़ेबंदी चरम पर रही. समीकरण तेजी से बदले और खंडूड़ी से दूर दिख रहे निशंक खंडूड़ी के साथ खड़े हो गए. प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कोश्यारी की ताजपोशी तय मानी जा रही थी, खंडूड़ी और निशंक के एक साथ आने से तीरथ सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष बन गए. कोश्यारी के पसंदीदा त्रिवेंद्र सिंह रावत को बाद में आलाकमान ने राष्ट्रीय सचिव बनाया. ऐसे में यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव करीब आने के बाद सीटों की दावेदारी और टिकट आवंटन को लेकर यह खींचतान बढ़ना लाजिमी है. भाजपा की सियासत को बारीकी से जानने वालों का कहना है कि पार्टी के भीतर जारी इस प्रतिद्वंद्विता से आलाकमान चिंतित भी है. मोदी की पहली पसंद पूर्व मुख्यमंत्री जनरल खंडूड़ी निशंक की आंख की किरकिरी बने हुए हैं, इस विरोध को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी हवा दे रहे हैं. राज्य की प्रमुख चर्चित सीट हरिद्वार से निशंक के उतरने के पहले ही मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती के चुनाव लड़ने की चर्चा ने इस छोटे हिमालयी राज्य में भाजपा में एक और गुट पैदा कर दिया है. चार पूर्व मुख्यमंत्रियों की भारतीय जनता पार्टी की ओर से पांच सीटों वाले प्रदेश में संसदीय प्रत्याशी के रूप में उतरने की चर्चा दिग्गजों को दांव–पेच का मौका दे रही है.

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

अल्पसंख्यकों को भटकाते हैं राजनीतिक दल

पृष्ठ 17 का शेष

पूरी सूची को तीन श्रेणी में बांट कर सबके लिए अलग–अलग कोटा तय कर दिया था, लेकिन उनके इस निर्णय को अदालत ने पलट दिया था. यही हाल सरकारी नौकरियों का है. अक्सर मुसलमानों की संख्या के अनुपात में नौकरियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की बात होती है, लेकिन सब जानते हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है. धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने के कारण नौकरी के आवेदन में यह शर्त तो जोड़ी नहीं जा सकती है कि इसके लिए सिर्फ मुस्लिम अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं. इसलिए यहां भी मुसलमान पिछड़ जाता है. सच्चर समिति की रिपोर्ट के आधार पर बात की जाए तो वह शिक्षा के मामले में अन्य कौमों से पिछड़ा हुआ है. राष्ट्रीय साक्षरता के आकड़े बताते हैं कि देश की कुल आबादी में से 65 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं तो मुसलमानों की साक्षरता 59 प्रतिशत ही है. दस से 14 वर्ष उम्र के एक चौथाई मुस्लिम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं. स्नातक स्तर पर 25 में से एक और परास्नातक स्तर पर 50 में एक छात्र ही मुस्लिम होता है. बात नौकरी की करें तो आईएएस संवर्ग में केवल तीन प्रतिशत, आईपीएस में चार प्रतिशत और आईएफएस में केवल 1.8 प्रतिशत ही मुसलमान सफल हो पाते हैं. भारतीय रेल सेवा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 4.5 प्रतिशत, जिनमें 98 प्रतिशत से ज्यादा निचले पदों पर है. सुरक्षा एजेंसियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व चार प्रतिशत, न्यायपालिका में सात प्रतिशत और राज्य सेवाओं के लिए राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में मुसलमानों की भागेदारी मात्र 2.1 प्रतिशत ही है. उत्तर प्रदेश की विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में तीन से 14 प्रतिशत ही मुसलमान हैं, जबकि भारत की कुल आबादी में 23 प्रतिशत गरीब हैं और उनमें बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है.

मुसलमानों की जानमाल की सुरक्षा के लिए साम्प्रदायिक दंगा विरोधी बिल लाने की बात लम्बे समय से हो रही है, लेकिन कब यह बिल आएगा, कोई नहीं जानता. कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि हिन्दुस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, इस पर काफी हायतौबा मची थी. प्रधानमंत्री को सफाई देना पड़ी, लेकिन इससे मुसलमानों को फायदा कम नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा. उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद करीब 20 प्रतिशत है. करीब सवा सौ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक होता है. समाजवादी पार्टी के ताकतवर होने से पूर्व तक मुसलमानों के पास सियासी विकल्प कम थे. अयोध्या विवादित ढांचा गिराए जाने तक मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा. इसके बाद के कुछ चुनावों में वह पूरी तरह से सपा के साथ रहा. सपा प्रत्याशी जीते या हारे, वोट सपा को ही दिया. सपा ने मुसलमानों का कितना भला किया यह तो कोई दावे से नहीं कह सकता है, लेकिन उसने मुसलमानों को भाजपा का हौआ खूब दिखाया. बसपा भी समय–समय पर मुसलमानों पर डोरे डालती रही. बसपा के मजबूत होने के बाद मुसलमान वोटरों ने प्रदेश के चुनावों में भाजपा को हराने के लिए जो भी जीत रहा हो, उसको वोट देना शुरू कर दिया. उसके इस फैसले से 2002 और 2007 के चुनावों में बसपा को भी फायदा हुआ, लेकिन 2012 में वह फिर सपा के साथ आ गया और उसे सत्ता तक पहुंचा दिया. मुसलमान इस बात से दुखी है कि सियासतदार उसको भटकाकर अपना मकसद पूरा करने की साजिश रचता रहता है और भोला–भाला मुसलमान ठगा जाता है. ■

अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरने में विफल रहे

पृष्ठ 17 का शेष

गण अंदर टीवी पर मनोरंजन कर रहे थे और बाहर कहलवा दिया कि जरूरी मीटिंग चल रही है. इसी समय पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अंदर जाना चाहा तो शाह के कारिंदे ने यह कहते हुए रोक दिया कि अंदर मीटिंग चल रही है. जब काफी इंतजार के बाद भी मीटिंग खत्म नहीं हुई तो वे कारिंदे को डपटते हुए अंदर घुसे तो देखा कि शाह एंड कम्पनी टीवी पर मनोरंजन कर रहे थे और बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता और लोकसभा के भावी प्रत्याशी इंतजार में थे. हालांकि बाद में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को महज चंद मिनटों में ही पार्टी का प्रचार करने की नसीहतों के साथ चलता किया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुजरात के अमित शाह बनारस का मिजाज भांपने में विफल हैं. अमित शाह को लगता है कि सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से वोट पड़ते हैं तो वे और उनकी टीम को वोट के लाले पड़ने वाले हैं. मीडिया के मोदी तो शायद जीत जाएं पर उन्हें सरकार बनाने भर की संख्या मिलनी मुश्किल होगी. मीडिया सिर्फ माहौल बना सकता है, वोट नहीं दिला सकता. इंडिया शाइनिंग के नारे की तरह मोदी की हवा भी इस चुनाव में निकल जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मोदी के कारिंदे सिर्फ मोदी की हवा के सहारे हैं. मोदी का भ्रम भी युवा ही दूर करेंगे. मोदी के सिपहसालार अभी तक जमीनी कार्यकर्ताओं से बहुत दूर हैं. लोग भ्रष्टाचार से आहत हैं, लेकिन कोई भी पहल स्वयं से नहीं कर रहा. ऐसे में मोदी के पास क्या जादू की छड़ी है, जो दिखाते ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा. मोदी सिर्फ सपना बेंच रहे हैं जिसे जनता जल्दी ही पहचान लेगी. सभी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं लेकिन अपने घर से नहीं सुधार के सारे काम दूसरों के घर से शुरू होने चाहिए. कोई भी सफाई में अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता. मोदी सिर्फ चुनावी खीर की तरह हैं, जो दिखने में सुन्दर पर स्वाद वहीं है. देश में केन्द्र सरकार के खिलाफ माहौल है, लेकिन इसका फायदा भाजपा उठाने में सक्षम नहीं दिखती. अगर गौर किया जाय तो भाजपा ने किसी भी मुद्दे पर केन्द्र को घेरने का काम नहीं किया. जनता सड़क पर चिल्लाती रही और भाजपा के नेता भी कांग्रेस की गलबहियां किए मजा लेते रहे. कभी जनलोकपाल तो कभी दागियों के मामले में, भाजपा कांग्रेस की बी टीम नजर आई. अगर कांग्रेस ने देश में लूट मचाया तो भाजपा भी इसमें बराबर की दोषी है. भाजपा किसी भी समय देश में मची लूट का विरोध करती नहीं दिखी, अलबत्ता कांग्रेस की लूट में खुद भजपा के पूर्व अध्यक्ष गडकरी तक का नाम उछला था. अमित शाह को पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को पार्टी से जोड़ना होगा. सिर्फ खयाली पुलाव से काम नहीं चलने वाला. ■

उत्तर प्रदेश कांग्रेस को प्रियंका का आसरा

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर ज्यादा निश्चिंत नहीं हैं. न ही वे 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हश्र भूले हैं. उस समय राहुल गांधी वन मैन आर्मी की तरह कांग्रेस पटल पर प्रकट हुए थे, ऐसा लग रहा था कि राहुल ने जनता की नब्ज को पहचान लिया है. उनके चेहरे पर तेज था और बातों में यूपी की तस्वीर बदलने की चाहत नजर आ रही थी.

कांग्रेसियों को सब कुछ चमत्कार जैसा लग रहा था. युवा–बड़े–बूढ़े सभी कांग्रेसी उनके पीछे कतारबद्ध हाथ बांध कर खड़े हो गए थे, सभी को सत्ता कांग्रेस के करीब दिखने लगी थी. इसकी वजह 2009 के लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी भी थी. राहुल के बल पर कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से 22 संसदीय सीटों पर कब्जा किया था. तब भी राहुल आंधी–तूफान की तरह यूपी की राजनीति के गलियारों में छा गए थे, हां इतना जरूर था कि उन्हें मां सोनिया गांधी का भी पूरा सहयोग मिल रहा था. वह भी जनसभाएं कर रहीं थीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में सोनिया ने कोई खास हिस्सेदारी नहीं की थी. प्रियंका भी अमेठी और रायबरेली तक ही सिमट कर रह गईं थीं. सबको चमत्कार की उम्मीद थी, मगर जब नतीजे आए तो राहुल की कांग्रेस कहीं नहीं दिखी. उसकी हवा निकल चुकी थी.

कांग्रेसियों को तीन वर्षों के भीतर (2009 के लोकसभा से 2012 के विधानसभा चुनाव के बीच का समय) ही इस जमीनी हकीकत का अहसास हो गया था कि राहुल से चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी है. यह बातें ज्यादा नहीं फिर भी पुरानी तो हो ही चुकी हैं, मगर कांग्रेसियों के मन से यह टीस आज भी निकल नहीं पाई. कांग्रेसी अतीत को भूल जाते, परंतु हाल में सम्पन्न रामपुर और अलीगढ़ की रैली में राहुल गांधी ने जिस तरह भाषण दिया, उससे यह संदेह और भी पक्का हो गया कि राहुल अभी परिपक्व नेता नहीं हुए हैं. मोदी से भयभीत कांग्रेसियों में राहुल गांधी उर्जा का संचार नहीं कर पा रहे हैं.

स्थिति यहां तक दयनीय है कि कई बड़े नेता तो चुनाव लड़ने का ही साहस नहीं जुटा पा रहे हैं. ऐसे में कुछ नेताओं को प्रियंका गांधी वाड्रा में रुचि दिखाई पड़ती है तो इसे अन्यथा नहीं लिया जा सकता है. वैसे, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि प्रियंका के पति राबर्ट वाड्रा अपनी पत्नी को राजनीति के मैदान में गांधी परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं. आम कांग्रेसी भले ही मुंह न खोलते हों, परंतु असलियत यही है कि राहुल से उनका मोह भंग हो चुका है. इसीलिए ऐसे नेता समय–समय पर प्रियंका का नाम बढ़ाते रहते हैं. कभी पोस्टर के माध्यम से तो कभी पत्र लिखकर या फिर कई बार प्रस्ताव पारित करके भी राजनीति के मैदान में प्रियंका को उतारने की बात चल चुकी है. यह तो कोई नहीं जानता है कि यह बात कहां से उड़ी की प्रियंका पूरे देश में पार्टी के लिए प्रचार करेंगी, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेसियों की मंशा जरूर छिपी हुई है. इस खबर की गंभीरता को दस जनपथ भी समझता था इसलिए उसने ऐसी खबरों का आनन–फानन में खंडन करते हुए, सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया. बात यहां खत्म होती, इससे पहले ही इलाहाबाद में एक बैनर ने कांग्रेसियों की नींद उड़ा दी. इसके साथ ही इस बात का भी अहसास हो गया कि कांग्रेस के भीतर प्रियंका एक मुद्दा बनती जा रही हैं. पार्टी की इलाहाबाद इकाई ने उन्हें पंडित जवाहर लाल नेहरू के संसदीय क्षेत्र फूलपुर से चुनाव लड़ाने के लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित कर नेतृत्व से अनुरोध तक कर डाला. साथ ही एक बैनर भी लगा दिया. इस बैनर से अहसास होता है कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी से निपटने के लिए कांग्रेसियों में प्रियंका गांधी ही अब एक मात्र उम्मीद दिख रही है. इलाहाबाद के सुभाष चौराहे पर लगी होर्डिंग कुछ ऐसा ही संकेत दे रही थीं. शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा फूलपुर संसदीय सीट से प्रियंका वाड्रा को लोकसभा प्रत्याशी प्रस्तावित किए जाने के ठीक दूसरे ही दिन सुभाष चौराहे पर कांग्रेसियों द्वारा लगाई गई होर्डिंग से कांग्रेस में नहीं, वरन विरोधियों में भी खलबली मच गई. होर्डिंग में लिखा था 'मइया अब रहतीं बीमार, भइया के पास हो गया ज्यादा भार, प्रियंका फूलपुर से बनो उम्मीदवार. बैनर में यह भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि मोदी की आंधी से बचाने के लिए प्रियंका ही एकमात्र विकल्प बची हुई हैं. बैनर शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव हसीब अहमद व यूथ कांग्रेस के सदस्य श्रीश चंद दुबे ने तैयार किया था. प्रियंका और राहुल के अलावा उक्त दोनों नेताओं के होर्डिंग चित्र और नाम भी इसमें साफ–साफ दिखाई दे रहे थे. बाद में इन नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि कांग्रेस में एक पक्ष ऐसा है, जो यह मानता है कि प्रियंका गांधी ही मोदी को जवाब दे सकती हैं. इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के भीतर दुविधा, असमंजस, आशंका और विरोधाभास लम्बे समय से व्याप्त है.

वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि प्रियंका राजनीति में आएंगी या नहीं, यह तो दस जनपथ ही तय करेगा, लेकिन यह समय प्रियंका को राष्ट्रीय राजनीति में लाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है. मोदी की हवा बनी हुई है और कांग्रेस को ऐसे में नुकसान हुआ तो राहुल के साथ–साथ प्रियंका की विश्वसनीयता पर भी विपक्षी सवाल खड़े करने लगेंगे. कांग्रेस फिलहाल, एक साथ अपने दोनों इक्के नहीं चलना चाहती है. दोनों के एक साथ मैदान में आने से राहुल का कद भी कम हो जाएगा. बहरहाल, इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आम चुनाव की तिथि नजदीक आते–आते कुछ और क्षेत्रों से भी जीत के लिए प्रियंका को आगे करने की गूंज सुनाई दे सकती है. भले ही इस मसले पर कोई खुल कर न बोले, क्योंकि आखिर मामला दस जनपथ का जो है. ■

रथों की सियासी दौड़

दर्शन शर्मा

समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश को रथ पर सवार कर चुनावी रैलियां करने तीन माह पहले ही भेज दिया था. यह मुलायम सिंह की दूरदर्शी राजनीतिक रणनीति थी, जिसके बल पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता में धमाकेदार वापसी की. मुलायम की यह तोता रटंत कि हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, ने उन्हें आखिरकर गद्दी तक पहुंचा दिया था. इसके पीछे का राज यह था मुलायम सिंह की पुरानी साख. जिसके बल पर उन्होंने और उनकी सरकार ने पिछली सरकारों में किसानों का कर्ज माफ करवाया था. मीडिया से लेकर बड़े–बड़े धनपतियों तक ने उनका साथ दिया था. उनके साथ सिनेमा सितारे और सिनेतारिकाएं भी जुड़ी हुई थीं. उन्होंने कवियों को सम्मान दिया, लेखकों को पुरस्कार बांटे. खबरनवीसों को उन्होंने कभी नाखुश नहीं होने दिया. वहीं उनके यश भारती जैसे पुरस्कारों ने लोगों ने भी अच्छी छाप छोड़ी. इन्हीं कई सुखद और मुफीद आदतों ने मुलायम को राजनीतिक गलियारे में शोहरत दी थी. सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि रही मुस्लिम वर्ग में पैठ. मुस्लिम वर्ग में आपस में कभी इतनी एकता नहीं देखी गई, जिस तरह मुलायम ने उनको अपने साथ जोड़कर एकजुटता का पाठ पढ़ाया. वे सबको सपा के मंच पर खींचने में काफी सफल हुए. मुस्लिमों के बीच इतनी गहरी पैठ आज तक दूसरे किसी हिन्दू नेता को नहीं मिली. ऐसा होता भी क्यों न, मुलायम इतने नरम दिन इंसान बने कि उन्हें लोग मौलाना मुलायम कहने लगे थे.

दंगों के बाद उपजी ज्वाला पर उन्होंने तुरंत पानी डालने के बजाय धीरे–धीरे शांत करने में ही अपनी भलाई समझी. आग ठंडी हुई तो उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने राजनीतिक हथकंडे लोकसभा चुनाव के लिए शुरू कर दिए हैं. उन्होंने 2012 की नकल करते हुए एक बार फिर रथ यात्राओं का जिक्र अपनी एक बैठक के माध्यम से किया. सपा के प्रधान कार्यालय में मुलायम ने पिछड़ा प्रकोष्ठ की एक बैठक में कहा कि समाजवादी पार्टी 24 अक्टूबर को पिछड़ी जातियों की अधिकार रथ यात्राएं और सामाजिक न्याय रथ यात्राएं निकालकर उपेक्षित और वंचितों को उनका हक दिलाएगी. समाज को आगे बढ़ाने और सामाजिक न्याय के लिए सपा लगातार संघर्ष करती रही है. पिछड़ों को मान सम्मान और पहचान दिलाने में सपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी पार्टी ने चलाया है. लोकसभा चुनाव सामने है और भाजपा ने साम्प्रदायिकता फैलाने का अभियान चला रखा है. कांग्रेस–भाजपा दोनों के विरुद्ध जनमत है. सपा जातिवाद की विरोधी और सामाजिक न्याय की पक्षधर है. भाजपा, कांग्रेस दोनों से जनता ऊब चुकी है. इनका विकल्प सिर्फ तीसरी ताकतें हैं. यूपी की इसमें बड़ी भूमिका होगी. सपा की लोकसभा में ताकत बढ़ाने का काम कार्यकर्ताओं पर हैं. सपा साम्प्रदायिकता के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है. बसपा के पांच सालों के शासनकाल में उसके काले कारनामों के खिलाफ संघर्ष भी सपा ने ही किया है. सपा की सरकार से अच्छी कोई दूसरे राज्य की सरकार नहीं हो सकती है. इसने सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी कदम उठाए हैं. बैठक में पहुंचे पिछड़े नेताओं का कहना रहा कि सपा सरकार ने ही पिछड़ों के हितों की रक्षा की है और उन्हें राजनीतिक व सामाजिक ताकत दी है. प्रदेश की सपा सरकार ने बेकारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लैपटॉप वितरण, गरीबों को कंबल व साड़ियां वितरण, किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त दवाई 108 इमर्जेंसी समाजवादी एम्बूलेंस सेवा, मुफ्त सिंचाई सुविधा के अतिरिक्त प्रदेश के विकास की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है. नेताजी ने ही 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की पहल की थी.

भारतीय जनता पार्टी के मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक चौधरी लौटन राम निषाद ने सपा पर अतिपिछड़े वर्ग को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सपा की यह वोट बैंक की राजनीति है. सपा सरकार ने निषाद, बिन्द, कश्यप, पाल कुशवाहा, मौर्य, माली, सैनी, शाक्य, साहू, भुर्जी, प्रजापति, चौहान, राजभर आदि जातियों की उपेक्षा की है. उन्हें मात्र मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. किसी भी अतिपिछड़े को कैबिनेट मंत्री न बनाकर केवल लालबत्ती देकर समाज को भ्रमित करने का काम कराया जा रहा है. अतिपिछड़ों व निषाद, बिन्द, कश्यप, मछुवारा समाज को जागृत करने व सपा बसपा व कांग्रेस की अतिपिछड़ा विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए 10 से 15 नवम्बर के बीच गाजीपुर से गाजियाबाद तथा बलिया से बुंदेलखंड वाया बहराइच तक सामाजिक न्याय रथ व एकलव्य चेतना रथ निकाला जाएगा. इसके तहत बरेली मेरठ, आगरा, सहारनपुर, बांदा, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर में अतिपिछड़ा निषाद, बिन्द, कश्यप सम्मेलन करने के बाद लखनऊ में विशाल सामाजिक न्याय रैली की जाएगी. 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का राजनीतिक मुद्दा उठाकर सपा व बसपा अति पिछड़े लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. सपा प्रमुख मुलायम की कथनी व करनी में कोई मेल नहीं है. निषाद, मल्लाह, केवल, मांझी, बिन्द, धीवर, कहार, गोड़िया, तुरहा आदि को अनुसूचित जाति में शामिल करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मझवार, तुरैहा, गोंड जाति अनुसुचित जाति में पहले से ही शामिल हैं. मुलायम अब समाजवादी व पिछड़ों, किसान के नेता नहीं पूंजीपतियों, माफियाओं व सामंतवादियों के नेता बन गए हैं. सपा के सांगठनिक ढांचे को देखें तो सपा मुलायम एंड फैमिली तथा यादव प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है. बहरहाल, अतिपिछड़ों को लुभाने के लिए जहां समाजवादी पार्टी अपने रथ के कील कांटे दुरुस्त करने में लग गई है. वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बार रथ दौड़ में हिस्सा लेने के पूरी तैयारी कर रही है. जहां इस लोकसभा की दौड़ में सपा के पिता पुत्र की अग्नि परीक्षा होने जा रही है, वहीं मोदी के सबल सारथी माने जाने वाले अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है. हालांकि इस दौड़ में बसपा और कांग्रेस भी अपनी अपनी व्यूह रचना रचने में जुट गई है. इस चतुष्कोणीय मुकाबले हर दल के पास अपनी चतुरंगिणी सेना रहेगी. सभी दलों के प्रमुख यह मानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश फतह करेगा, वही दिल्ली का ताज पा सकेगा. इतना जरूर है उत्तर प्रदेश में इस बार कांटे की लड़ाई है. देखना यह है कि आने वाले वक्त में राजनीतिक पारा कहां तक चढ़ता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

पिछड़ों को पटाने के लिए सपा की यात्राएं

संदीप कश्यप

समाजवादी पार्टी पिछड़ों को साइकिल के पीछे दौड़ाने के लिए हाथ–पैर मार रही है. उसे डर सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नरेन्द्र मोदी के नाम पर इसके वोट बैंक में डाका न डाल दे. सपा की यह आशंका निर्मूल नहीं है. भाजपा में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि इसके प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी की छवि पूरे देश मे में भले ही विकास पुरुष के रूप में चमके लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में मोदी को विकास पुरुष के अलावा पिछड़ों के नेता के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जाए. वैसे भी इस समय उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को आरक्षण और विरोध का हर तरफ सुनाई दे रहा है. बसपा प्रोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है तो अदालत ने पिछले दिनों सम्पन्न पिछड़ों का कोटा बढ़ाने की सपा की मुहिम को झटका दिया है. ऐसे में इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़ा कार्ड काफी अहम साबित होगा. वैसे भी प्रदेश में करीब आधी आबादी पिछड़ों की ही है. सपा चाहती थी कि केन्द्र पिछड़ों को प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में संसद में कानून बना दे, लेकिन बसपा के विरोध के चलते सपा को मुंह की खानी पड़ गई थी. सपा पिछड़ों को अपने साथ जोड़े रखने और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और ज्यादा धार देने के लिए 24 अक्टूबर 2013 को दो यात्राएं निकाल रही है. यह यात्राएं करीब पचास दिनों तक पूरे प्रदेश में घूमेंगी. इसके बाद मुलायम और अखिलेश 14 दिसम्बर को लखनऊ में पिछड़ों की विराट रैली को सम्बोधित करेंगे. 24 अक्टूबर को 17 पिछड़ी जातियों की अधिकार रथयात्रा और समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में सामाजिक न्याय रथयात्रा को हरी झण्डी दिखाकर लखनऊ से विदा किया जाएगा. इसका उद्देश्य पिछड़ों को एकजुट करना है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यात्राओं की प्रसांगिकता बताते हुए कहते हैं कि उपेक्षित और वंचित समाज को आगे बढ़ाने और सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है. पिछड़ों को मान–सम्मान और पहचान दिलाने में समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी पार्टी ने चलाया है. यात्राओं के टाइमिंग के बारे में मुलायम का कहना था, लोकसभा चुनाव सामने है और भाजपा ने सांप्रदायिकता फैलाने और जातीय विद्धेष फैलाने का अभियान चला रखा है. इसलिए सपा को यात्राएं निकालनी पड़ रही हैं. ■

सपा ने राजा को रोका, भाजपा ने बृजभूषण को तोड़ा

राजनाथ का क्षत्रिय पराक्रम

संजय सक्सेना

ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी ने निर्दल दबंग क्षत्रिय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को साध लिया. राजा को लालबत्ती (कैबिनेट मंत्री) देकर सपा नेतृत्व ने भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया. इसके साथ ही राजा के भाजपा में आने की चर्चाओं पर भी विराम लग गया, लेकिन सपा एक अन्य दबंग ठाकुर नेता बृजभूषण शरण सिंह को नहीं रोक सकी. उन्होंने सांसदी का टिकट ठुकराकर समाजवादी पार्टी को बॉय–बॉय कह दिया. कैसरगंज के सपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आजकल भाजपा से काफी करीबी बना रखी है. वैसे, इस सच्चाई को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि सपा में आने से पूर्व वह भाजपा के टिकट से तीन बार संसद पहुंच चुके हैं. उनकी छवि कट्टर हिन्दूवादी नेता के रूप में होती थी. लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और अयोध्या मंदिर आंदोलन में भी भूषण ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया था. भाजपा बृजभूषण को गोंडा या फैजाबाद से मैदान में उतार सकती है. दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता सोमपाल शास्त्री के बाद बृजभूषण शरण सिंह दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सपा का लोकसभा का टिकट ठुकरा दिया है. बृजभूषण की नाराजगी की वजह उनके क्षेत्र में विकास के काम नहीं हो पाने के अलावा पश्चिमी यूपी में ठाकुर नेताओं का उत्पीड़न भी वजह था. शास्त्री ने मुजफ्फरनगर दंगों में सपा सरकार की भेदभावपूर्ण नीति और जाट बिरादरी के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सपा का टिकट ठुकराया था. बृजभूषण बहराइच में होने वाली नरेन्द्र मोदी की रैली में भाजपा में लौटने की घोषणा कर सकते हैं.

बात राजा भैया और राजनाथ सिंह की करें तो यह साफ हो जाता

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और रघुराज प्रताप सिंह, जिनके बीच पहले भी काफी अच्छे संबंध थे, पिछले कुछ दिनों में काफी निकटता देखी जा रही थी. आजम के चलते राजा सपा आलाकमान से नाराज थे और आजम से मुलाकात के बाद ही वह उदार हुए थे. बदले हालात के बाद भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजा भैया ने जो निर्णय लिया है, वह सपा से क्षत्रियों की नाराजगी कोई खास नहीं कम कर पाएगा. न राजा ही अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को भूल पाएंगे कि किस तरह आजम के कहने पर सपा ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था. खैर, राजनाथ जो स्वयं ठाकुर नेता हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में क्षत्रियों की एक सशक्त लॉबी तैयार करना चाहते हैं. ताकि भाजपा तो मजबूत हो ही, उनकी ताकत भी बढ़े. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगों ने राजनाथ की राह काफी आसान कर दी थी. दस जनपथ के कभी काफी करीबी रहे सुल्तानपुर के सांसद संजय सिंह पर भी भाजपा डोरे डाल रही है. संजय के आजकल कांग्रेस आलाकमान से वैसे रिश्ते नहीं रह गए हैं जैसे पहले हुआ करते थे. इसके अलावा सुल्तानपुर और अमेठी में जिस तरह से कांग्रेस कमजोर हो रही है, उसे देखते हुए भी संजय सिंह पाला बदलने में ही भलाई समझ रहे हैं. भाजपा सुल्तानपुर से वरुण गांधी को चुनाव लड़ाना चाह रही है, जबकि कुछ कांग्रेसी सुल्तानपुर से प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारने के लिए ताल ठोंक रहे हैं.

बताते हैं कि राजनाथ सिंह ठाकुर नेता संजय सिंह को ट्रम्प कार्ड के रूप में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ भी उतार सकते हैं. अगर संजय जीत गए तो भाजपा की बल्ले–बल्ले हो जाएगी और हार भी गए तो खोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा. संजय को पार्टी मे हार के बाद भी पूरा सम्मान दिया जाएगा. संजय को पता है कि वरुण के चुनाव मैदान में कूदने से उनकी जीत फंस सकती है, इसलिए वह भाजपा का दामन थामने में ही भलाई समझ रहे हैं. संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह भी राजनीति के मैदान में हैं. उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और हार गईं थीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

काशी के अस्सी का दशहरा

कुमार निलाम्बुज

काशी विश्व में जुदा है, यहां कदम–कदम पर खुदा है. कहते हैं मोक्ष की काशी शिव के त्रिशुल पर बसी है. इसका पृथ्वी से कोई लेना–देना नहीं है, इसलिए देश में भूकंप आए या आपदा, यहां के लोग अपनी मस्ती में रहते है. इसे वैज्ञानिक सोच वाले नहीं समझेंगे, इसे समझने के लिए अध्यात्म की गहराइयों में उतरना होगा.

पिछले दो दिनों से इन्द्र देवता शहर पर मेहरबान हैं. मौसम सुहावना है, बुराई का प्रतीक रावण कई जगह जल चुका है. अस्सी की अड़ी (पप्पू चाय की दूकान) पर अड़ीबाजों का जुटना शुरू है और रावण चर्चा का विषय है. शोर इतना है कि रावण किसका प्रतीक है, पता नहीं चल रहा है. कोई रावण को पूजने की बात कर रहा है तो कोई उसे बुराई का प्रतीक बताकर जलाने की बात कर रहा है. अड़ी की संसद में बिना अध्यक्ष के सभी बैठकबाज एक साथ सभी चर्चा में कूद पड़े हैं, अपनी–अपनी बात मनवा लेना चाहते है. लेकिन तभी मीडियाकर्मी को देखते ही पाण्डेय जी का समाजवाद मुखर हो जाता है. पाण्डेय जी की शिकायत लोहिया के बजाय बिग बी को ज्यादा दिखाने को लेकर है. अशोक गुरु लोहिया के समाजवाद की आड़ में मीडिया की जमकर क्लास ले डालते हैं. उनका साथ देते हैं कुंवर सुरेश सिंह. पुराने समाजवादी हैं आजकल मुलायम के समाजवाद से चिंतित रहते है. तभी एक चौबे गुरु इनकी बात बीच में काटते हुए राम–रावण की बात पर पड़ी धूल साफ कर कहने लगे रावण रामयण के पात्र का जिसे राम ने सीता के अपहरण में मार गिराया था. रावण की अभी चर्चा चल ही रही थी की बीएचयू राजनीति विज्ञान विभाग के कौशल गुरु मिठाइ लिए दिखे. मुंह मीठा होते ही किसी ने मोदी का राग छेड़ दिया. फिर शुरू हुईं मोदी और राहुल की बातें. कौन होगा अगला पीएम. रावण तो बीच में ही छूट गया. बारिश और शहर की समस्या पर बात टिक भी नहीं पाई थी की महंगाई के हाथ से फिसलते हुए बात आलू पर आ गई. भारत कला भवन बीएचयू से रिटायर्ड आरपी सिंह ने हिन्दी के जानकार राय की सड़ी आलू से तुलना कर दी. फिर क्या राय साहब ने मोदी को लेकर हमले शुरू कर दिए. राय गुरु ने मोदी को कभी हिटलर तो कभी सांप्रदायिक करार दिया. यहां हर दो मिनट पर राहुल और मोदी पर चर्चा हो जाती है. बीच–बीच में अमेरिका और पाकिस्तान के साथ, गांधी आदि के दर्शन भी जगह पा जाते हैं. चर्चा के बीच गुरु का मिजाज बना रहता है. कहा जाता है काशी में या तो शिव है या फिर गुरु, यहां चेला कोई नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां हर दस कदम पर शिव के मंदिर या फिर गुरु मिल जाते हैं. आप चाहे जिस किसी गली में जाएं, महादेव और गुरु से पार नहीं पा सकते.

बाहर मौसम सुहावना है रिमझिम फुहार के साथ मौसम में सिहरन और नमी है. लेकिन अड़ी का माहौल इतना गर्म है कि एक बार तो सूरज भी शर्मसार हो जाए. यहां चाय जल्दी नहीं मिलती, नए–नए ग्राहक हों तो जल्दी मिल भी जाए, लेकिन अड़ीबाजों को दो घंटे के बाद ही चाय नसीब हो पाती है. यहां रावण जलने के नाम पर सुबह आठ बजे से दस बजे के बीच दो बार मिठाई बंट चुकी है और शाम का भी प्रबंध किया जा चुका है. मौसम सुहावना हो और अस्सी के अड़ीबाज न जुटें, ऐसा हो ही नहीं सकता. ■

खाद्य सुरक्षा बिल पर सपा सरकार का अड़ंगा

संदीप कश्यप, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम फिलहाल लागू नहीं हो पाएगा. केन्द्र सरकार द्वारा चुनावी मौसम में लाया गया यह बिल अखिलेश सरकार लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश में लागू करने का मन बना रही है. सपा सरकार नहीं चाहती कि खाद्य सुरक्षा बिल लागू करके वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले और कांग्रेस को बढ़त का मौका मिल जाए. वैसे, दिखाया यही जा रहा है कि प्रदेश सरकार इसको लागू करने में आने वाली अड़चनों का शीघ्र से शीघ्र निपटारा करना चाहती है. इसीलिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसकी बैठक प्रत्येक माह आयोजित होगी. प्रचार यह किया जा रहा है कि राज्य सरकार हड़बड़ी में इसे लागू करके दुश्वारियां मोल नहीं लेना चाहती हैं. इसीलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी. खाद्य सुरक्षा अधिनियम को यथाशीघ्र लागू कर क्रियान्वयन कराने हेतु सचिवालय में तथा खाद्य आयुक्त कार्यालय में एक सेल का गठन भी किया जाएगा, इसके लिए एक विशेष सचिव तथा अपर आयुक्त की तैनाती कराने के साथ–साथ आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था कराई जाएगी.

मुख्य सचिव जावेद उस्मानी कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा बिल/अध्यादेश 2013 को उत्तर प्रदेश में जुलाई 2014 तक किसी भी दशा में लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अध्यादेश को सुचारू रूप से बेहतर नेटवर्क बनाकर लगभग 15 करोड़ लोगों लाभान्वित कराया जाएगा. किसी भी पात्र को व्यक्तियों और परिवारों का चयन करने के उपरान्त प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें तीन रूपये प्रति किग्रा की दर से चावल और गेहूं दो रूपये प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध कराया जायेगा. मुख्य सचिव ने कहा कि लाभार्थियों को चिन्हित कर इनकी सूची कंप्यूटराइज्ड कराकर नए राशन कार्ड वितरित कराए जाएंगे. लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण सुचारू रूप से कराने हेतु भण्डारण क्षमता, ट्रांसपोर्ट, खाद्यान्न आदि की भी विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी ताकि किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए. बहरहाल, दुख की बात यह है कि कांग्रेस–सपा अपनी–अपनी सरकारें बचाने के लिए तो आपस में हाथ मिलाए हुए हैं, लेकिन बात जब गरीबों के हितों की आई तो एक–दूसरे को काट खाने वाली राजनीति करने लगे. ■

खाद्य सुरक्षा को लेकर कांग्रेस–सपा में टकराव

खाद्य सुरक्षा बिल के मसले पर केन्द्र में हाथ मिलाकर चलने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक–दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं. कांग्रेस के यूपी प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने खाद्य सुरक्षा बिल राज्य में नहीं लागू हो पाने के लिए समाजवादी सरकार को खरी–खरी सुनाई तो, सपा के रणनीतिकारों ने अपनी 'तोप' का मुंह कांग्रेस की तरफ खोलने में जरा भी देरी नहीं की. सपा ने पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के राज में भुखमरी से सर्वाधिक मौतें हुई हैं. गरीबी हटाओ के नाम पर गरीब को मिटाओ का ही अभियान चलता रहा है. समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में किसान और गरीब को हमेशा केन्द्र में रखकर काम किया है इसलिए कांग्रेस के एक गुजराती प्रभारी का यह कहना कि यूपी सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू नहीं करना चाहती है, तथ्यहीन और अनर्गल बयान है. कांग्रेस चुनाव के मौकों पर लोकलुभावन घाषणाएं करने की आदी है. प्रदेश के खाद्यमंत्री राजेन्द्र चौधरी ने केन्द्र सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि केन्द्रीय मंत्री 18 पेज का भारत का राज पत्र ही देंगे या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए संसाधन भी देंगे? खाद्य एवं रसद तथा कारागार मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने गत दिनों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन के संबंध में रखे गए खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेकर लौटने के बाद लखनऊ में कहा कि उक्त अधिनियम हड़बड़ी में और बगैर पूरी तैयारी के लाया गया है. इसके पीछे सिर्फ चुनावी दृष्टि से राजनीतिक फायदा उठाने का इरादा है. भारत सरकार इसे राज्यों पर थोपकर वाहवाही लूटना चाहती है. यह कदम संविधान की संघीय व्यवस्था को कमजोर करता है. केन्द्र सरकार राज्यों के संसाधन के बारे में सोचे बगैर कैसे अधिनियम को लागू करा सकेगी. इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तमाम प्रावधानों के लागू करने से राज्यों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा. केन्द्र सरकार इसके लिए शत प्रतिशत व्यय वहन करने को तैयार रहे. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लागू करने की दलील पर उत्तर प्रदेश ने जोरदार ढंग से राज्यों का पक्ष रखा. प्रदेश के खाद्य मंत्री का कहना था प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेक विसंगतियों और लीकेज के चलते खाद्यान्न पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से वितरित नहीं हो पाता है. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने से पहले जब तक इसमें सुधार नहीं होता तब तक अधिक खाद्यान्न बाजार में जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. परिणामस्वरूप गरीब किसानों को इनकी उपज का उचित मूल्य नहीं प्राप्त होगा और किसान बाजार की प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगें. आज केन्द्र सरकार और कांग्रेस गरीबों के लिए बहुत चिंतित नजर आती है जबकि हकीकत यह है कि इनका उद्देष्य सिर्फ चुनावी वोट हासिल कर किसी तरह सत्ता में आना हैं. इस संबंध में भाजपा का अलग ही कहना है. वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर ही गरीबी के नाम पर गरीबों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा रही है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक का कहना है, केन्द्र और प्रदेश की सरकारें ऐसा व्यवहार कर रही हैं मानों गरीब की मौज आ गई है. इसके लिए दोनों सरकारों ने अपना खजाना खोल दिया है, जबकि हकीकत इससे उलट है, गरीबी काला बाजारी और मंहगाई से वह त्राहिमाम कर रहा है. उसकी थाली गायब हो गई है. वह हाथ में नमक रोटी रखकर रोटी खाता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

28 अक्टूबर–03 नवंबर 2013

> एनटीटी कोर्स की शुरुआत फैजाबाद जिले में सबसे पहले जिंगेलबेल नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल ने आरम्भ की थी. इस स्कूल से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों छात्र–छात्राएं डिप्लोमा लेकर बाहर निकलते हैं. स्कूल की प्रभारी अंजली ज्ञा.प्र.टे. का दावा है कि हमारे स्कूल से एनटीटी कोर्स करने के बाद अधिकांश छात्र–छात्राएं किसी न किसी स्कूल में समायोजित हो जाते हैं.

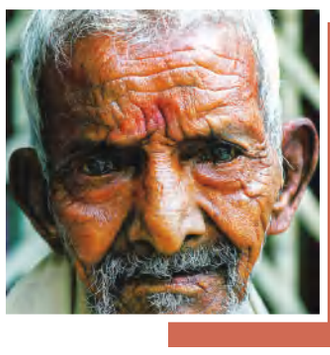

सपना दिखाकर जेब खाली कर रहे एनटीटी सेंटर

राकेश कुमार यादव

फैजाबाद में शिक्षक बनाने का सुनहरा ख्वाब दिखाकर गली–कूचों में खुले नर्सरी टीचर सेंटर अभिभावकों की जेबें ढीली कर रहे हैं. एनटीटी सेंटर संचालकों का कोई शुल्क मापदंड भी नहीं है. दो साल के इस कोर्स के लिए कोई 20 हजार रुपये वसूल रहा है तो कोई मात्र 6 हजार रुपये में कोर्स पूरा करा रहा है. और तो और शिक्षक बनने की आकांक्षा पाले छात्र–छात्राओं को यह भी पता नहीं है कि उन्हें जो प्रमाण पत्र मिलेगा इसकी मान्यता क्या है? फैजाबाद जनपद में व्यावसायिक शिक्षा देने वाली दर्जनों संस्थाएं छात्र–छात्राओं के भविश्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं. एनटीटी के नाम पर अप्रमाणिक कथित संस्थाएं दर्जनों शाखाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं. दूसरी ओर एनटीटी केन्द्र संचालक हर साल लाखों रुपये की उगाही कर मालामाल हो रहे हैं. रोकथाम करने वाला संबंधित विभाग भी आंखें मूंदे हुए है. कभी भी कोई शिक्षा अधिकारी एनटीटी सेंटरों की बैधता की जांच करने के लिए किसी भी सेंटर पर नहीं जाता है.

एनटीटी कोर्स की शुरुआत फैजाबाद जिले में सबसे पहले जिंगेलबेल नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल ने आरम्भ की थी. इस स्कूल से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों छात्र–छात्राएं डिप्लोमा लेकर बाहर निकलते हैं. स्कूल की प्रभारी अंजली ज्ञा.प्र.टे. का दावा है कि हमारे स्कूल से एनटीटी कोर्स करने के बाद अधिकांश छात्र–छात्राएं किसी न किसी स्कूल में समायोजित हो जाते हैं. एनटीटी कोर्स कराने वाली संस्थाओं में एस विद्या मंदिर, टाइनी टाट्स, उदया पब्लिक स्कूल,

फैजाबाद पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रियन स्कूल, सौर्या स्कूल, यूनीवर्सल एकेडमी, देवा पब्लिक स्कूल, अवध इंटरनेशनल स्कूल, टीपी कान्वेंट स्कूल, इंडो अमेरिकन स्कूल, मिशन स्कूल प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन स्कूलों में एंजल ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग, राष्ट्रीय एजूकेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, महर्षि दयानंद एजूकेशनल ग्रुप कक्षाएं सचांलित करती हैं. एंजल गुप ऑफ एजूकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की प्राचार्य सुचित तिवारी बताती हैं कि दो वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा कोर्स के लिए कुल 17,750 रुपये दो किश्तों में अदा करने होते है. एनटीटी के लिए मात्र इंटर उत्तीर्ण होना आवश्यक है. उनके सेंटर की एनटीटी कक्षाएं साकेत महाविद्यालय और महाराणा प्रताप पीजी कालेज में संचालित होती हैं. इसके अतिरिक्त प्रदेश के दर्जनों जनपदों में भी उनके सेंटर है, जहां से इसे कराया जाता है. उनका सेंटर ऑल इंडिया अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजूकेशन से संबद्ध है और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी नई दिल्ली से पंजीकृत. इसी भांति महर्षि दयानंद एजूकेशन ग्रुप से संबद्धता लेकर चलाए जा रहे एनटीटी सेंटर के संचालकों का कहना है कि वह भी एनसीटी नई दिल्ली से पंजीकृत हैं. संस्था दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स 12000 रुपये में करवा रही है. परन्तु कुछ संचालक शुल्क के नाम पर 20 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं. राष्ट्रीय एजूकेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज नाका रामनगर फैजाबाद के डायरेक्टर एके गौड़ बताते हैं कि एनटीटी कोर्स के लिए छात्रों को पहले वर्ष 9400 रुपये और दूसरे वर्ष 7400 रुपये अदा करना पड़ता है. इनकी कक्षाएं मेथडिस्ट गर्ल्स इंटर कालेज में चलाई जाती हैं.

फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी नई दिल्ली संस्था जिसकी संबद्धता बताकर कुकुरमुत्तों की तरह फैले एनटीटी सेंटर जिस तरह से छात्रों और अभिभावकों से वसूली कर रहे हैं, इस संस्था के अस्तित्व में होने या न होने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है. सवाल है कि कोर्स संचालित करने वाली संस्थाएं और केन्द्रों पर प्रशिक्षण किस मापदंड पर दे रही हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमा वाद संख्या सीएम (ओ.एस.) 151/2009 में एक पक्षीय आदेश के बावजूद यह गोरखधंधा धड़ल्ले से चल रहा है. शिक्षण सामग्री, प्रासपेक्टस, शुल्क की रसीदें से लेकर अंकपत्रों और प्रमाण पत्रों में बदले हुए नाम व विरोधाभाषी सूचनाओं के चलते छात्र–छात्राओं के साथ धोखाधड़ी की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता. अनेक संस्थाएं भिन–भिन्न नामों से अपनी सम्बद्धता दिखाकर दर्जनों माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कालेजों में छात्र–छात्राओं को नर्सरी टीचर बनाने का ख्वाब दिखाते हुए उनकी गाढ़ी कमाई डकार रही हैं.

बलिया

अक्षर पहचानने की जंग लड़ रहे हैं बुजुर्ग

शिवनाथ चतुर्वेदी

उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े इन विद्यार्थियों के मन में सिर्फ यही कसक है कि वे भी अक्षर पहचान सकें और पोते के आगे गर्व से सिर उठा सकें. सो हर रोज नाक पर टिकी ऐनक, हाथ में सचित्र किताब लिए ये वह सब कर रहे हैं, जो उन्होंने किसी जमाने में अपने बेटे–बेटियों से कराया था. पके बालों वाले ऐसे विद्यार्थियों की सारी मशक्कत अक्षर पहचानने की है. पहचान लिया तो घर पर पोते से शाबासी मिल जाएगी वर्ना मिलेगी वो मीठी झिड़की जो बाबा के रोम–रोम में सिहरन पैदा कर देती है. आखिर पोता उनसे ज्यादा पढ़ा–लिखा जो है. लोक शिक्षा केंद्र पर निरक्षरता की स्याही मिटाने के लिए बुजुर्ग व उम्रदराज निरक्षर साहित्यक किताबों का सहारा लेकर साक्षर बनने की जंग लड़ रहे हैं. साक्षरता कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद

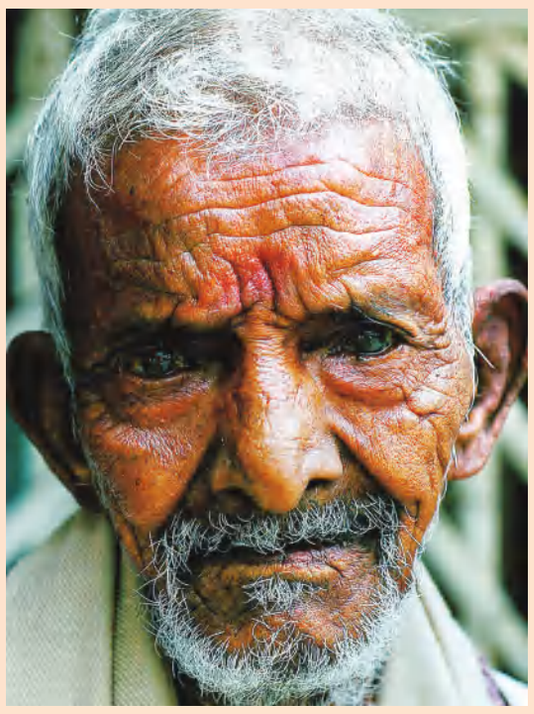

में संचालित 833 लोक शिक्षा केंद्रों पर पुस्तकालय की स्थापना की गई है. उन पुस्तालयों पर केंद्र सरकार द्वारा साहित्यिक व कौशल विकास कार्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं. इसका उद्देश्य आधी उम्र पार कर चुके उन बुजुर्गो के जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैलाना है, जो अब तक आर्थिक व पारिवारिक कारणों की वजह से शिक्षा से वंचित हैं. जिला लोक शिक्षा समिति के पूर्णकालिक अधिकारी अतुल तिवारी के अनुसार केंद्र में पतले पापड़ से मोटी कमाई, हृदय परिवर्तन, खलीफा के कपड़े, ईर्ष्यालु बहनें, बेटी की मुस्कान, हर घर की शान, बच्चों की भलाई के लिए, पेड़ हमारा साथी, पर्यावरण रक्षा में, वनों की भूमिका, शिक्षा हुई अनमोल, कीट–पतंगों की दुनिया, जल गांव का अमृत, भंडार आदि प्रमुख किताबों सहित करीब 200 लोकोपयोगी पुस्तकें हैं. इनती ही संख्या में पुस्तकें हर लोक शिक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराई गई हैं. उन्हें पढ़कर बजुर्ग लोग न सिर्फ तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं, बल्कि निरक्षरता के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं. निरक्षर बुजुर्गों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पुस्तकालयों में जो किताबें उपलब्ध हैं, उनमें अधिकांश की कहानी रोचक व प्रेरणादायक है. इसके अलावा स्वरोजगार व पर्यावरण संरक्षरण पर आधारित पुस्तकों का भी समावेश है. साक्षरता कार्यक्रम के जरिये नव साक्षरों को शिक्षित करने के साथ ही ये पुस्तकें उन्हें मतदान, सूचना का अधिकार, आर्थिक अधिकार, स्वालंबन का महत्व बताने का भी कार्य करेंगी.■

कांग्रेसी दबंग की लालबत्ती छिनी

राजकुमार शर्मा

देहरादून.बहुगुणा सरकार के मंत्री डा. हरक सिंह रावत के घर पर गोली काण्ड को अंजाम देने वाले कांग्रेसी दंबग पर पहली बार सरकार ने चाबुक कसा है.खानपुर से कांग्रेस विधायक प्रणव चौंपियन की लालबत्ती छिनवा कर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) ने अपनी ताकत दिखा दी. सहयोगी होने के नाते सरकार में पीडीएफ का दबदबा है.इस दबदबे ने भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत के माथे पर चिन्ता की लकीरें उकेर दी हैं. सरकार अपनी होते हुए भी कांग्रेसी खुद को हाशिए पर देख रहे हैं. हरिद्वार में कांग्रेसियों की चिंता भी यही है. वहां बसपा सरकार और सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल कर अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है. शासन और प्रशासन में सहयोगी दलों की हनक के आगे कांग्रेसी कशमशा कर रह जा रहे हैं. न चाहते हुए भी पिछले दिनों बसपा कोटे से मंत्री सुरेंद्र राकेश के प्रोटोकाल मामले में मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव को हिदायत देनी पड़ी थी.

इसके बाद अपने ही विधायक को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी करवाना पड़ा. फिर भी पीडीएफ के विधायक और मंत्री संतुष्ट नहीं हुए. आखिरकार दबाव में मुख्यमंत्री को चौंपियन की लालबत्ती इतरवाने का आदेश करना पड़ा। इस घटना केदूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे. पहला तो यह कि पीडीएफ के सदस्यों के हौसले और बढ़ेंगे और सरकार पर इनका दबाव बढ़ता जाएगा. दूसरा यह कि इससे कांग्रेसियों में और हताशा बढ़ेगी. हरिद्वार में बसपा के बढ़ते प्रभाव की बात

> हरिद्वार से सांसद हरीश रावत की भी यही शिकायत रही है कि हरिद्वार प्रशासन उनको और कांग्रेसियों को खास तवज्जो नहीं देता. बसपाइयों की ज्यादा सुनी जाती है. बसपा कोटे से मंत्री सुरेंद्र राकेश को गुंडा कहने के मामले में चौंपियन पर हुई कार्रवाई ने इस बात को और बल दे दिया है.

कांग्रेसी राहुल गांधी के सामने भी उठा चुके हैं. राजनीति के जानकार मानते है कि हालात इस तरह बदल रहे कि कांग्रेस की हरिद्वार सीट को हरीश रावत से छिनने की चिन्ता ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है.

हरिद्वार से सांसद हरीश रावत की भी यही शिकायत रही है कि हरिद्वार प्रशासन इनको और कांग्रेसियों को खास तवज्जो नहीं देता. बसपाईयों की ज्यादा सुनी जाती है. बसपा कोटे से मंत्री सुरेंद्र राकेश को गुंडा कहने के मामले में चौंपियन पर हुई कार्रवाई ने इस बात को और बल दे दिया है.हरिद्वार जिले से ही एक कांग्रेसी विधायक ने हाल ही में मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि इनके विधानसभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति प्लान में मंजूर राशि विभागीय मंत्री ने वापस लेकर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया. जबकि संबंधित राशि से प्रस्तावित निर्माण कार्य आरंभ भी हो चुका है. अवैध खनन और व्यापार कर की चोरी कर रहे ट्रांसपोटर्स की सिफारिशों को लेकर भी तमाम मामले शासन और सरकार में पहुंच रहे हैं. कांग्रेसियों की सुनवाई नहीं हो रही है. इनमें बढ़ रहा असंतोष और हताशा का असर आने वाले चुनावों में दिख सकता है. ■

सरकार की विफलता से हुई भारी तबाही : खंडूड़ी

रेनु शर्मा

अब तक भाई के बचाव में दिखने वाले भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूडी इन दिनों निशंक की सक्रियता का जवाब भाई पर हमला बोल कर दे रहे है.जनरल खण्डूडी इन दिनों हर स्तर पर अपने रिश्ते के भाई के प्रति मुखर दिख रहे है.जनरल ने बहुगुणा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में आपदा से जो भयंकर तबाही हुई है, इसके लिए राज्य की बहुगुणा सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है. यदि मौसम वैज्ञानिकों की सलाह को गंभीरता से लिया गया होता तो इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश में जान-माल की क्षति नहीं हुई होती.भाजपा में अब भी निशंक-जनरल रार जारी है,इशारे से कई बार निशंक जनरल पर भाई बहुगुणा की सरकार के पक्षधर होने की शिकायत पार्टी हाई कमान से करते रहे है. ओडिशा की सरकार ने मौसम वैज्ञानिकों की सलाह पर सही तरीके से अमल किया, जिसकी वजह से वहां ज्यादा तबाही नहीं हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने एक वार्ता के दौरान यह बात अपने आवास पर कही. इन्होंने कहा कि जून में आई आपदा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लापता हो गये. खण्डूड़ी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ओडिशा में आये चक्र वात ने इस बात को साबित कर दिया है कि समय रहते सुरक्षा उपाय किये जाएं तो जनहानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है. खण्डूड़ी ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार को एक भरोसेमंद और अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली भी विकसित करना चाहिए. जिससे आने वाले समय में आ-

पदाओं का आसानी से सामना किया जा सके. केदारघाटी और अन्य जगहों पर आई आपदा का उल्लेख करते हुए बीसी खण्डूड़ी ने कहा कि अगर सरकार समय रहते मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को गंभीरता से लेती और लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देती, तो शायद हजारों लोगों का जीवन बचाया जा सकता था. खण्डूड़ी ने माना कि इस दौरान ही भयंकर बारिश होने की चेतावनी मिल गई थी, काफी कम समय था. बावजूद सरकार बदरीनाथ जैसी से भी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में विफल रही. उन्होंन बांग्लादेश का भी जिक्र किया, जहां के तटीय इलाकों में अक्सर चक्रवात आते हैं और समय रहते वहां की सरकार आवश्यक कदम उठाकर हानि कम करती है. बहुगुणा सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने आपदा राहत कार्यो में लापरवाही को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होने वाली है, अब तक बेघर हुए लोगों के लिए छत का भी इंतजाम नहीं हो पाया, जबकि सरकार ने अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए विज्ञापन पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिया. चौंपियन प्रकरण पर चुटकी लेते हुए इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किन गुंडों से घिरे हुए हैं. डा. निशंक ने आरोप लगाया कि चार माह बाद भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य ढर्रे पर नहीं आए हैं. केंद्र से औद्योगिक पैकेज की मांग का नाटक शुरू करने वाली बहुगुणा सरकार को पुराना औद्योगिक पैकेज लागू करवाना चाहिए. उन्होंने कहा कि विभिन्न मोर्चो फेल हुई कांग्रेस सरकार जनता के साथ ही अपने सहयोगियों का भरोसा भी खो चुकी है. सहयोगी विधायक सरकार को दस दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं. ऐसे में सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. खुद कांग्रेस के विधायक ही अपनी सरकार के मुखिया के लिए रजिया व द्रोपदी जैसे विशेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं. पंचायतों में सरकारी प्रशासक नियुक्त करने पर भी डा. निशंक ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि बुरी तरह डरी सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है. इन्होंने केंद्र से मांगे जा रहे औद्योगिक पैकेज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब आयकर व उत्पाद शुल्क में कोई छूट नहीं मिलनी, तो किस बात का पैकेज. केंद्र को पुराना औद्योगिक पैकेज ही उत्तराखंड में फिर से बहाल करना चाहिए.चौंपियन प्रकरण के बाद राजनीतिक स्थिरता के प्रश्न पर डा. निशंक ने कहा कि सरकार आत्महत्या करने पर तुली है. यदि सरकार आत्महत्या ही कर लेगी, तो भाजपा को भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा.

नाम के चक्कर में फंसे सूबे के 16 हजार छात्र

रेनु शर्मा

उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों के खेल का खामियाजा यहां के 16 हजार छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. नेताओं के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम बदलने के चलते छात्रों को दो साल से मार्कशीट नहीं मिल पाई है. इससे छात्र जहां आगामी कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, वहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं. गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद वर्ष 2011 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने लोगों की मांग पर टिहरी जिले के बदशाहीथौल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की. इस दौरान यह तय किया गया था कि दीनदयाल उपाध्याय विवि से संबद्ध होने वाले महाविद्यालयों के पहले बैच की परीक्षा गढ़वाल विवि ही आयोजित करेगा. इसी बीच कांग्रेस ने सत्ता में आते ही दीनदयाल उपाध्याय विवि का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विवि कर दिया. 2011–12 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने एमए और एमकॉम की व्यक्तिगत परीक्षा आयोजित की, जिसमें करीब 16 हजार छात्र–छात्राओं ने भाग लिया. परीक्षा संपन्न हुए दो वर्ष होने को है, छात्रों को मार्कशीट नहीं मिल पाई है. गढ़वाल विवि शासन को पत्र भेजने की बात कह कर अपना पल्ला झाड़ रहा है. वहीं श्रीदेव सुमन विवि का कहना है कि जिस विवि ने परीक्षाएं आयोजित करवाई हैं, वही अंक तालिका देगा. विश्वविद्यालयों की लीप–ापोती और शासन की अनदेखी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. छात्र दो साल से अंक तालिकाओं की बाट जोह रहे हैं. गढ़वाल विवि के ओएसडी परीक्षा प्रो. एल.जे. सिंह ने बताया कि इस संबंध में शासन को चार अक्टूबर को पत्र भेजा जा चुका है. दिशा–निर्देश मिलते ही मार्कशीट जारी कर दी जाएगी. दीनदयाल उपाध्याय विवि से एमए की व्यक्तिगत परीक्षा देने वाले दिनेश चंद्र का कहना है कि अंक तालिका नहीं मिली है. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रही हूं. दीपा भंडारी का कहना है कि एमकॉम द्वितीय वर्ष की व्यक्तिगत परीक्षा दी है. राजनैतिक पार्टियां अपनी राजनीति के लिए हमारे भविष्य से खेल रही है. अभी तक हमें मार्कशीट नहीं मिल पाई है. ■

> संबद्धता विश्वविद्यालय का नाम अब श्रीदेव सुमन संबद्धता विश्वविद्यालय किया जा चुका है. मार्कशीट इसी नाम से ही जारी होगी. इस संबंध में एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी अवगत कराया जा रहा है.
>
> *– राधिका झा, अपर सचिव*
>
> अब छात्रों का मानसिक शोषण और नहीं सहा जाएगा. यदि शीघ्र ही छात्रों को अंकतालिकाएं नहीं वितरित की जातीं, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.
>
> *– सुधीर जोशी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, गढ़वाल विवि*

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120–6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366